

(सभापतीस्थानी माननीय तालिका सभापती श्री. मोहन जोशी)

पु. शी. : रोजगार हमी योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना

मु. शी. : रोजगार हमी योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना यासंबंधी सर्वश्री एस.क्यू.जमा, हेमंत टकले, माणिकराव ठाकरे, विनायक मेटे, प्रा. सुरेश नवले, सर्वश्री अरुण गुजराथी, भाई जगताप, श्रीमती उषाताई दराडे, सर्वश्री उल्हास पवार, रमेश शेंडगे, मोहन जोशी, प्रकाश बिनसाळे, सुभाष चव्हाण, राजन तेली वि. प. स. यांचा प्रस्ताव

श्री एस. क्यू. जमा (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नियम 260 अन्वये पुढील प्रस्ताव मांडतो.

" राज्यात रोजगार हमी योजना कायदा 1977 साली अंमलात आणून रोजगाराचा अधिकार देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असणे, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात महत्वाची कामे, ज्यामध्ये बंधारे, रस्ते, महामार्ग, विहिरी, इत्यादींसारखी विकासाची कामे केली जाऊन यातून ग्रामीण भागातील बेरोजगार, बेघर व्यक्तींनाही रोजगार उपलब्ध झालेला असणे, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी आवश्यक अशा महत्वाच्या तरतुदी करून त्या अन्वये प्रत्येक बेरोजगारापर्यंत रोजगार पोहचविण्याचा केलेला प्रयत्न, केंद्र शासनाने देखील राज्यासाठी रोजगार हमी योजना लागू केली असून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतर्गत सुमारे 4 कोटी कुटुंबांना रोजगार पुरविण्यात येणे, या योजनेचा लाभ राज्यातील 51 टक्के महिलांना झालेला असणे, परंतु केंद्र शासनाचे पूर्ण अनुदान रोजगार हमी योजनेतून येणे गरजेचे असणे, केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या रकमेमध्ये तफावत असल्याने यासाठी अंमलबजावणी करणे कठीण होत असणे, राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फलोत्पादन, शेतीची कामे इत्यादी कृषी क्षेत्रातील कामे व शहरी व गरीब बेरोजगारांना चांगला रोजगार

...2..

श्री एस. क्यू. जमा...

मिळण्यासाठी या कायद्यात तरतूद करणे आवश्यक असून या योजनेचा लाभ राज्यातील तळागाळातील ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी या योजनेची ठोस अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने करावयाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यावी."

सभापति महोदय, विधान सभा नियम 260 के तहत जो प्रस्ताव यहां पर रुलिंग पार्टी के सदस्यों द्वारा लाया गया है, उस प्रस्ताव पर अपने विचार रखने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूँ.

सभापति महोदय, हमारा महाराष्ट्र राज्य बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य है. पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसने लोगों को संवैधानिक तौर पर रोजगार देने का कानून बनाया.. यह काम हमारे राज्य में सन् 1977 में किया गया. रोजगार हमी योजना के माध्यम से पिछले 30 सालों में विकास के बहुत सारे काम महाराष्ट्र राज्य में हुए हैं. इस योजना के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार भी मिला तथा विकास के भी बहुत काम महाराष्ट्र में हुए. उदाहरण के तौर पर जवाहर विहार योजना का काम, सड़क बनाने के काम, नाले बनाने के काम तथा इरिगेशन के लिए छोटे-छोटे डैम बनाने के काम भी इस रोजगार हमी योजना के माध्यम से किए गए. जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है. यह अच्छी बात है कि दिल्ली में यूपीए सरकार आने के बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम करती ह, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की रोजगार हमी योजना का अध्ययन किया और उसी आधार पर सन् 2005 में रोजगार हमी योजना का सेंट्रल एक्ट पास किया गया. इस एक्ट को हम महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से जानते हैं. पहले यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ ही राज्यों में शुरू की गयी और अब यह स्कीम पूरे देश में लागू है. लेकिन उस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में सिर्फ 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया गया. इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए उनकी एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है. उस एक्ट के सेक्शन 28 के अंदर एक प्रावधान है, उसके अनुसार....

(इसके बाद श्री शर्मा...

. . . . श्री. एस. क्यू. जमा जारी

सेन्ट्रल एक्ट में 100 दिन की रोजगार की गारन्टी देने के लिए प्रावधान किया गया है. विभिन्न राज्यों में यह योजना लागू करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है. इस एक्ट के सेक्शन 28 में यह प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अच्छी स्कीम है तो वह अपने राज्य की अच्छी स्कीम रिटेन कर सकते हैं. महाराष्ट्र में रोजगार हमी योजना पहले से लागू थी और उन्होंने सेक्शन 28 का फायदा लेकर उस योजना में सुधार करके अपनी योजना बनाई और उसको फेज मेनर में महाराष्ट्र में लागू किया गया. एक एप्रिल 2006 से महाराष्ट्र के 12 जिलों में यह योजना शुरू हुई और धीरे धीरे आज यह योजना महाराष्ट्र के सभी 33 जिलों में लागू है. सेन्ट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट को मिलाकर रोजगार हमी योजना को अमल में लाने की योजना बनाई है. सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट और महाराष्ट्र सरकार के एक्ट में बेसिक अन्तर यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अन्तर्गत सब से छोटी यूनिट ग्राम पंचायत है और उसके अनुसार प्लानिंग, एक्जीक्यूशन, मॉनीटरिंग और ऑडिटिंग की गई है. जबकि हमारी राज्य सरकार में ग्राम पंचायत यूनिट नहीं है. राज्य सरकार की योजना में कार्यों की योजना ऊपर से बनाई जाती है और उसके ऊपर अमल जिला स्तर पर जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है. सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान है. बेरोजगारों को ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार कार्ड मिलेगा, उनको काम मिलेगा और उनको डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा. सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में मॉनीटरिंग करने की कड़ी व्यवस्था बनाई गई है. फंड के इधर-उधर होने की संभावना बहुत कम है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू रोजगार हमी योजना में ठेकेदार के द्वारा काम किया जाता है. इस योजना में ग्राम पंचायत यूनिट नहीं है और काम ऊपर से तय किए जाते हैं, डी.पी.डी.सी. के माध्यम से काम तय किए जाते हैं. वर्तमान में हमारी जानकारी के अनुसार यह स्कीम असफल हो रही है. महाराष्ट्र की योजना असफल होने के 2 कारण हैं. पहला कारण मजदूरी में अन्तर की वजह से है और दूसरा कारण यह है कि काम ठेकेदार के द्वारा होता है. बहुत सारे काम होते ही नहीं है और इन कामों का पेमेंट कर दिया जाता है. यह बुनियादी फर्क है और हमें इस बात को समझना पड़ेगा.

. . . B 2

. . . श्री. एस.क्यू. जमा जारी

सभापति महोदय, महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य माना जाता है, लेकिन 1995 के बाद से दो दलों की मिली-जुली सरकार बनने की वजह से सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का स्तर प्रभावित हुआ है. मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता. लेकिन किसी सरकार का मूल्यांकन करना, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है. किसी सरकार का स्टेटस उसके कार्य से जाना जाता है. जिन राज्यों को हम बैकवर्ड कहते थे, उदाहरण के तौर पर बिहार जैसे बैकवर्ड राज्य आज प्रगति कर रहे हैं. यह राज्य महा-राष्ट्र के नाम से जाना जाता है और सचमुच में महाराष्ट्र राज्य पूरे देश में एक नम्बर पर था.

. . . भाषण जारी, नंतर देवदत्त

असुधारित प्रत / प्रसिद्धि प्राप्त है

NTK/ MMP/ D/

श्री एस. क्यू. जमा...

11:10

Our level of governance and administration was excellent but that was only upto year 1995. यहां पर जितने भी अच्छे कानून बने हैं, चाहे वह ई.जी.एस. का कानून हो या महाराष्ट्र हेंडलूम कारपोरेशन का कानून हो, लेबर रिफार्म्स एक्ट हों या पल्प एक्ट हो. इन अच्छे कानूनों की वजह से ही मुंबई के आसपास के जो एरिया हैं, जैसे ठाणे, नई मुंबई और बेलापुर बेल्ट में बहुत सारे कारखाने लगे हैं. यह बात सही है कि सन् 1995 के बाद से या कहिए कि जब से केंद्र और राज्य में मिलीजुली सरकार आयी है तब से हमारे गवर्नेंस के स्तर में गिरावट जरूर आयी है. उस बारे में अभी न बोलकर, मैं बाद में उस बारे में बात करूंगा.

हमें यह देखना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. सेंट्रल और राज्य की दोनों रोजगार हमी योजनाओं को लागू करने के बाद यदि हम दोनों योजनाओं की तुलना करें तो हम देखेंगे कि केंद्र की जो रोजगार हमी योजना हमारे राज्य में लागू है उसकी अच्छी परफार्मेंस हमें अपने राज्य में देखने को नहीं मिलती.

मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम, आंध्र प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में अच्छी तरह से लागू की गयी है. उस बारे में मेरे पास इस वर्ष के जनवरी महीने तक के आंकड़े हैं. आंध्र प्रदेश में सन् 2008-09 में 2963 करोड़ रुपए, सन् 2009-10 में 4509 करोड़ रुपए और 2010-11 में 3976 करोड़ रुपए केंद्र की रोजगार हमी योजना से प्राप्त किए गए हैं. इतना पैसा उन्होंने सिर्फ 100 दिन का रोजगार देने के लिए केंद्र की योजना के माध्यम से प्राप्त किया है.

लेकिन यदि हम महाराष्ट्र राज्य में केंद्र की रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो सन् 2008-09 में सिर्फ 361 करोड़ रुपए, 2009-10 में 321 करोड़ रुपए और 2010-11 में 240 करोड़ ही खर्च किए गए हैं. जबकि आंध्र तथा कर्नाटक राज्य ने इस योजना के अंदर बहुत फंड लिया. सिर्फ 100 दिन रोजगार देकर उन्होंने अपने राज्यों का बहुत फायदा किया है. जबकि महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के अंदर हम पूरे वर्ष लोगों को रोजगार देते हैं. फिर भी केंद्र की रोजगार हमी योजना के संदर्भ में हमारा परफार्मेंस बहुत ही पुअर है.

NTK/ MMP/ D/

श्री एस. क्यू. जमा...

मैं यहां पर मध्यप्रदेश की जानकारी देना चाहूंगा. पिछले तीन सालों की जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सन् 2008-09 में 3554 करोड़ रुपए, सन् 2009-10 में 3722 करोड़ रुपए तथा 2010-11 में जनवरी माह तक उन्होंने 2078 करोड़ रुपए केंद्र की रोजगार हमी योजना से प्राप्त किए हैं.

इसी प्रकार मैं राजस्थान के आंकड़े यहां पर देना चाहूंगा कि वहां पर सन् 2008-09 में 6163 करोड़ रुपए, 2009-10 में 5669 करोड़ रुपए तथा सन् 2010-11 में 2078 करोड़ रुपए केंद्र की रोजगार हमी योजना से प्राप्त किए हैं. ये फीगर 25 जनवरी 2011 तक के हैं. दूसरे राज्यों की फीगर भी मेरे पास हैं लेकिन सभी फीगर्स यहां पर बताकर मैं सदन का ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता हूं.

कर्नाटक की स्थिति भी काफी अच्छी है. हालांकि गुजरात और केरल राज्यों ने इस योजना का ज्यादा फायदा नहीं उठाया है. उसके कारणों की स्टडी भी मैंने नहीं की है. लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है. क्योंकि यहां पर भी पिछले तीन सालों में कभी 3 सौ करोड़ तथा कभी 2 सौ करोड़ रुपए का ही फंड खर्च किया गया है. यह फंड बहुत ही कम है.

महाराष्ट्र सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने एमजीएनआरईजीएस में सन् 2008-09 में 361.54 करोड़ रुपए खर्च किए तथा अपने राज्य की ई.जी.एस. के माध्यम से 613.7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. इसी प्रकार सन् 2009-10 में केंद्रीय फंड से 321.9 करोड़ रुपए खर्च किए तथा अपने राज्य के बजट से इस काम के लिए हमने 792.79 करोड़ रुपए खर्च किए. सन् 2010-11 में महाराष्ट्र शासन ने केन्द्र सरकार से 240.96 करोड़ रुपए लिए तथा अपने राज्य के फंड से हमने 5 सौ करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

इसके बाद श्री शर्मा के पास जारी....

. . . श्री. सय्यद जमा जारी

सभापति महोदय, सही स्थिति हमारे सामने आ सके, इसलिए ये आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मैंने सदन में आने के पहले नागपुर जिले के 2-3 सरपंचों को फोन लगाया और उनसे पूछा कि उनकी ग्राम पंचायत में रोजगार हमी योजना के कार्य चालू हैं या नहीं। सभी सरपंचों ने एक ही बात कही कि हमारे यहां न तो केन्द्र सरकार की रोजगार हमी योजना के कार्य चालू हैं और न ही महाराष्ट्र सरकार की रोजगार हमी योजना के कार्य चालू हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास फंड उपलब्ध हैं तो उन्होंने कहा कि केन्द्र शासन की योजना के अन्तर्गत पहले के काम का पैसा आया है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहां पर काम नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि राज्य की योजना का अमल ठेकेदार के द्वारा होता है। ठेकेदार के द्वारा बहुत से कार्य होते ही नहीं हैं और उनका पेमेंट हो जाता है। स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि लेबर मिलते नहीं हैं। हमने यह मालूम करने की कोशिश की कि लेबर क्यों नहीं मिलते हैं तो हमें यह मालूम हुआ कि जितना पैसा हम महाराष्ट्र सरकार की योजना में देते हैं, उससे अधिक पैसा उनको बाहर से मिल जाता है, इसलिए मजदूर काम पर नहीं आते हैं। राज्य सरकार की रोजगार हमी योजना में बदल करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस योजना को फेल करने के लिए एक षडयंत्र चल रहा है, शायद हमारे कुछ अधिकारी ऐसा नहीं चाहते कि ग्रामसभा को यह अधिकार मिले। ग्रामसभा के लोग वहां के बेरोजगारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका जॉब कार्ड बनता है। हम लोग यह चाहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिक से अधिक फंड हमारे पास आना चाहिए। लेकिन जब तक हम उनकी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक वे पैसा नहीं देते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे इस योजना के अन्तर्गत कार्य बंद हैं, जबकि आंकड़ों के आधार पर कार्य चालू हैं। बिना काम हुए सरकार का पैसा जा रहा है और काम नहीं हो रहे हैं। मेरे पास 2-3 जिलों की जानकारी है, चाहे केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत कार्य हों, चाहे राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत कार्य हों, सही स्थिति यह है कि कार्य नहीं के बराबर हो रहे हैं।

सभापति महोदय, नवम्बर के महीने में इंडियन लेबर कॉफ्रेंस हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और इंटक के प्रतिनिधि के रूप में मैंने इसमें भाग लिया था। सभी

. . . D 2

. . . श्री. सय्यद जमा

राज्यों के श्रम मंत्री और श्रम सचिव इसमें उपस्थित थे. महाराष्ट्र के दोनों श्रम मंत्री इसमें हाजिर नहीं थे, केवल श्रम सचिव श्रीमती कविता गुप्ता इसमें हाजिर थीं. लगभग सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों ने कहा कि रोजगार हमी योजना के काम में मजदूरी बहुत कम मिलती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर इसमें नहीं आते हैं. उनको मिनिमम वेज के अनुसार थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसलिए वे वहां पर काम करने की कोशिश करते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 14 जनवरी 2011 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में रोजगार हमी योजना के अन्तर्गत 127 रुपए मजदूरी तय की गई है.

. . . . भाषण जारी, नंतर देवदत्त.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धि प्राप्त

श्री एस. क्यू. जमा

यह भारत सरकार का गॅजेट नोटिफिकेशन है जिसमें मिनिमम वेजेज तय किया गया है. यह 127 रुपए है. जम्मू कश्मीर में 123 रुपए है. केरल में 150 रुपए है. नार्थ इस्टर्न प्रोवींसेज में यह रेट थोड़ा ज्यादा है. चंडीगढ़ में यह रेट उन्होंने ज्यादा रखा है. वह अरबन एरिया है, इसलिए शायद उन्होंने वहां पर ज्यादा रेट रखा है. मिनिमम वेज लागू होने के बाद 127 रुपए का रेट महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है या नहीं किया है, इसकी जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की थी. लेकिन वह जानकारी मुझे नहीं मिल सकी. मुझे लगता है कि केंद्र में तय होने के बाद यह मिनिमम वेज 127 रुपए ही रहा होगा.

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बार्डर के जो जिले हैं, वहां पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश से मजदूरों को लाया जाता था. ठेकेदार हमारे राज्य के होते थे तथा वे ठेकेदार दूसरे राज्यों से मजदूरों को लेकर आते थे. गोंदिया भंडारा, नागपुर या गडचिरोली में रोजगार हमी योजना का काम करने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों से लाये जाते थे. लेकिन अब परिस्थिति बदल हो गयी है, अब इन बार्डर के जिलों में मजदूरी का काम करने के लिए दूसरे राज्यों से लेबर नहीं आती है. इसका मुख्य कारण यही है कि केंद्र की रोजगार हमी योजना, उन राज्यों में बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू हुई है. अब वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है. यह बात सही है कि एक वर्ष में सिर्फ 100 दिन ही वहां पर मजदूरों को काम देने की व्यवस्था, केंद्र की उस योजना में है. जबकि हम महाराष्ट्र की रोजगार हमी योजना के माध्यम से मजदूरों को पूरे वर्ष काम देते हैं

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ किसान भाईयों ने मुझ से कहा कि जमा साहब आप मजदूरों के नेता हैं और आपने यदि मजदूरों की मजदूरी बढ़वा दी तो हम किसान तो मर जाएंगे. क्योंकि खेतों में काम करने के लिए हमें मजदूर नहीं मिलेंगे. अभी मजदूरों की मजदूरी कम है, तो भी खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं. इस लिए मेरा कहना है कि इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार को बहुत गंभीरता से स्टडी करके इस समस्या को समझना पड़ेगा. मेरा कहना है कि यदि राज्य की ई.जी.एस. स्कीम या केंद्र की रोजगार गारंटी योजना जो कि सन् 2005 में बनी है उसमें कोई बदलाव या सुधार करना है तो उसके

श्री एस. क्यू. जमा....

लिए राज्य सरकार को यथाशीघ्र स्टडी करनी चाहिए. केंद्र की रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से बहुत कम पैसा आने का एक कारण मुझे यह भी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अपनी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पिछले 20-30 सालों में विकास के बहुत काम पहले ही कर लिए हैं. मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी हालत हमारे राज्य में सड़कों की है. दूसरे राज्यों में उतना अधिक विकास न होने की वजह से, वे राज्य केंद्र की रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अब विकास कार्य कर रहे हैं, इसीलिए केंद्र की रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से वे लोग उस योजना का ज्यादा फंड अपने राज्यों में खर्च कर पा रहे हैं.

राज्य सरकार से मेरा बार-बार यही अनुरोध है कि सरकार इस बारे में जल्द से जल्द स्टडी करके इस बात का पता लगाए कि इस योजना को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मजदूरी बढ़ाने के बाद इसका उल्टा असर हमारे किसान भाईयों पर न पड़े. क्योंकि यदि हमारे किसान भाईयों को अपने खेतों में काम कराने के लिए मजदूर चाहिए तो वे उन मजदूरों को आज दो सौ रुपए या तीन सौ रुपए मजदूरी नहीं दे सकते हैं. इन सभी बातों में सामंजस्य बनाए रखते हुए हमें कोई वर्कबल फार्मूला निकालना होगा, कोई कारगर फार्मूला हमें निकालना होगा. इसके अलावा अपने राज्य की योजना के मार्फत हम पूरे साल भर काम देते हैं और केंद्र की रोजगार गारंटी योजना के मार्फत हम सिर्फ 100 दिन काम देते हैं. इस तफावत को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि हम पुराने ढंग से ही इन योजनाओं को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं. हम अभी भी ग्राम पंचायत को उसका अधिकार देना नहीं चाहते. यही सबसे बड़ी रुकावट इस योजना में है. अभी हमारा माइंड उस तरह से सेट ही नहीं हुआ है. हम अभी भी यही चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से होने वाले काम, हमारे मंत्रालय से सेंक्शन होकर ही वहां जाएं. जबकि केंद्र सरकार का जो एक्ट है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत को यूनिट बनाया गया है.

(इसके बाद श्री शर्मा के पास....

. . . श्री. सय्यद जमा

संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे राज्य में पंचायत राज प्रणाली लागू है. पंचायत राज प्रणाली में सकारात्मक कदम उठाकर महाराष्ट्र सरकार को रोजगार हमी योजना को अच्छी तरह से लागू करना चाहिए. महाराष्ट्र सरकार की रोजगार हमी योजना में ज्यादातर काम व्यक्तिगत हैं, जैसे जवाहर विहिर योजना व्यक्तिगत काम है, तालाब बनाना व्यक्तिगत काम है, फलोत्पादन करना व्यक्तिगत काम है, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की योजना में व्यक्तिगत स्कीम्स नहीं हैं. उसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को 100 दिन के लिए रोजगार देना है. मैंने कुछ राज्यों के बारे में जानकारी ली है, उन्होंने पीस रेट लागू किए हैं. रोजगार हमी योजना में 127 रुपए मजदूरी तय की गई है. आपने कम काम किया तो आपको 70 रुपए या 80 रुपए मिलेंगे और अगर ज्यादा काम किया तो 127 रुपए से ज्यादा भी मिल सकते हैं. मेरा यह स्पष्ट रूप से कहना है कि किसानों के हित का भी संरक्षण होना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए उनको खेती के काम के लिए ज्यादा मजदूरी न देनी पड़े.

सभापति महोदय, अब मैं आखिरी मुद्दा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार हमी योजना लागू की गई है. शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं. ए,बी,सी और डी क्लास की नगर परिषदों के बेरोजगारों के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. हमें इस बारे में स्टडी करनी पड़ेगी. सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अन्तर्गत हमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेना चाहिए. रोजगार हमी योजना के लिए पैसा शहर में काम करने वाले मजदूरों से प्रोफेशनल टैक्स के रूप में प्राप्त होता है. हालांकि पिछले 2 सालों से प्रोफेशनल टैक्स का पैसा कन्सोलिडेटेड फंड में जमा होता है. प्रोफेशनल टैक्स के पैसे का शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिलता है. शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें इस पैसे का उपयोग करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फंड का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए. कई राज्यों ने इस योजना को अच्छी तरह से लागू करके उन्होंने अपने यहां से होने वाले मायग्रेसन को रोक दिया है. बिहार की सरकार ने बिहार से होने वाले मायग्रेसन को रोक दिया है और उसी का परिणाम है कि

. . . F 2

. . . श्री. सय्यद जमा.

बिहार में वह पार्टी दोबारा सत्ता में आई. अन्त में मेरा इतना ही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम सेन्ट्रल फंड बढ़ाएं. ए, बी, सी और डी नगर परिषद क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार दे सकें तो बहुत अच्छा होगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.

प्रस्ताव प्रस्तुत झाला.

. . . नंतर खर्चे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. अरुण गुजराथी (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य

श्री. नितीन राऊत (रोजगार हमी योजना मंत्री) : महोदय, या प्रस्तावावर किती सन्माननीय सदस्य बोलणार आहे हे अगोदर समजले तर वेळेचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने योग्य होईल.

डॉ. नीलम गोन्हे : महोदय, प्रस्तावावर भाषण करताना सत्तारूढ पक्षातील सदस्यांनंतर एक विरोधी पक्षाचा सदस्य बोलतो, असा प्रघात आहे.

तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) : ठीक आहे, सन्माननीय सदस्य श्री. गुजराथी साहेब बोलण्यासाठी उभे राहिलेले आहेत. त्यांचे भाषण संपल्यानंतर आपण सुचविल्यानुसार बोलण्याची संधी देऊ.

श्री. अरुण गुजराथी : महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. एस.क्यू.जमा यांनी सभागृहात एका महत्वाच्या विषयाच्या संदर्भात नियम 260 अन्वये प्रस्ताव चर्चेसाठी आणलेला आहे, त्यावर मी माझे विचार व्यक्त करणार आहे.

महोदय, सभागृहातील या चर्चेचा महत्वाचा भाग म्हणजे केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेमध्ये तफावत असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे. माननीय मंत्री महोदय सभागृहात उपस्थित आहेत. हा फरक नेमका कोणता आहे हे सभागृहात अगोदरच स्पष्ट केलेले आहे. मघाशी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्यानुसार ज्या पध्दतीने राजस्थान राज्यात 16 हजार कोटी रुपये गेल्या तीन वर्षात त्या राज्याने केंद्राकडून मिळविले, मध्य प्रदेश राज्याने याच तीन वर्षात 10 हजार कोटी रुपये प्राप्त करून घेतले आणि आपल्या राज्याने मात्र केवळ 900 ते 1000 कोटी एवढीच रक्कम मिळविली. म्हणजे राजस्थानला मिळालेल्या रकमेचा विचार केला तर 15 हजार कोटी रुपये त्या राज्याला जास्त मिळाले आहेत. या 15 हजार कोटीमध्ये किती तरी विकास होऊ शकतो, यापासून आपण वंचित राहिलो आहोत. आपल्या राज्याचा अर्थसंकल्प किती आणि रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून इतर राज्यांना किती पैसे मिळाले याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

सभापती महोदय, 1 मे, 1972 पासून रोजगार हमी योजना आपल्या राज्यात अमलात आली. या योजनेचे जनक माजी विधान परिषद सदस्य कै. वि.स.पागे हे असून त्यांच्या नावाने परवा आपण विधान भवनमध्ये नुकतेच एक प्रशिक्षण केंद्रही सुरु केले आहे. सन 1972 मध्ये

....2....

श्री. अरुण गुजराथी

महाराष्ट्र राज्यात फार मोठा व भीषण असा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळेस स्व. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री पदावर होते. अशा दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठीच ही योजना राज्यात आणली असावी, असा माझा कयास आहे. सन 1978 मध्ये या योजनेला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आणि सन 1979 मध्ये त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. ज्या पध्दतीने मागील वर्षी केंद्र शासनाने "राईट टू एज्युकेशन" हा कायदा करून एक घटनात्मक अधिकार जनतेला दिला. त्याचप्रमाणे राज्यातील ग्रामीण भागात तसेच "अ" वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील अकुशल कामगारांना हक्काचे काम मिळावे म्हणून हा कायदा केलेला आहे. पण या कायद्याप्रमाणे आपण मागे त्याला 100 टक्के काम देऊ शकलो काय, हा गेल्या 15-20 वर्षातील संशोधनाचा विषय आहे. ही योजना इतकी चांगली आहे की, जगप्रसिध्द शास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी सुध्दा या योजनेबाबत सांगितले की, विकसनशील देशात एखादी कोणती योजना आणावयाची असेल तर महाराष्ट्रासारखी रोजगार हमी योजना आणावयास पाहिजे. याचे कारण केंद्र शासनाने सुध्दा या योजनेच्या धर्तीवर एनआरईजीएस या नावाने एक योजना सुरु केली. एवढेच नाही तर अमर्त्य सेन सारख्या उच्च व्यक्तिमत्वानेही आपल्या राज्यातील रोजगार हमी योजनेची प्रशंसा केली. अशा या रोजगार हमी योजनेचे सन 1979 मध्ये कायद्यात रुपांतर झाले. केंद्र शासनाने मागील पाच वर्षापूर्वी हाच कायदा केला व ही योजना संपूर्ण देशात सुरु केली. ग्रामीण भागातील गरिबी हटवावयाची असेल तर रोजगार हमी योजनेला पर्याय नाही. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून लोकांची रोजगाराची निर्मिती करून त्यांची खरेदी शक्ती वाढविणे आणि गरिबी हटविणे असा मुख्य हेतू आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण जनेतेमध्ये खरेदी शक्ती निर्माण झाल्यामुळेच हा भाग टिकून आहे. जगात महामंदी असताना देखील हिंदुस्तान आणि विशेष करून महाराष्ट्र राज्यात ही मंदी सहन करण्याची देखील गरज भासली नाही. त्याचप्रमाणे केंद्रशासनाच्या व माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री श्री. शरदरावजी पवार यांच्या प्रयत्नांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाला चांगला भाव मिळायला लागला, हे आपल्याला मान्य करावे लागेल.

यानंतर श्री. जुन्नरे

श्री. अरुण गुजराथी...

रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात केंद्र शासनाची योजना ही केवळ 100 दिवसांची आहे. त्यामुळे मला असे वाटते की, ही योजना अशी तयार करण्यात यावी की, 100 दिवस केंद्र शासनाचे व 265 दिवस राज्य शासनाचे असे मिळून ही रोजगार हमी योजना तयार केली तर त्याचा मजुरांना चांगला फायदा मिळू शकेल. 100 दिवसाचा पैसा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या योजनेसाठी आला तर आपल्या राज्याचा पैसा देखील वाचू शकेल.

सभापती महोदय, कारखान्यांमध्ये काम करणा-या महिलांची टक्केवारीचे प्रमाण 15.5 लक्ष आहे. परंतु संघटित क्षेत्रात काम करणा-या महिलांची संख्या फक्त 3 टक्के आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करणा-या महिलांची टक्केवारी 51 टक्के आहे. याचा अर्थ रोजगार हमी योजना ही महिलांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची अशी योजना आहे. रोजगार हमी योजनेचा आपल्याकडील मजुरीचा दर 127 रुपये आहे तर मध्यप्रदेशचा 125, चंदीगड 150 व केरळमध्ये 150 रुपये रोहयोच्या मजुरीचा दर आहे. मी या सभागृहाला सांगू इच्छितो की, 127 रुपयांमध्ये शेतीच्या कामासाठी सुध्दा मजूर मिळू शकत नसल्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात शासनाने असे धोरण स्वीकारले होते की, ज्यावेळी शेतीची कामे सुरु असतील त्यावेळी म्हणजे जून महिन्यापासून ते डिसेंबर-जानेवारी पर्यंत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु करावयाची नाहीत. ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील कामासाठी मजूर उपलब्ध होऊ शकतील. 127 रुपयांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामावर महिला कामावर येऊ शकेल अशी परिस्थिती नाही. शेतात काम करण्यासाठी पुरुष मजुरांना 225 ते 250 रुपये मजुरी दिली जाते व 175 ते 200 रुपयांपर्यंत महिलांना शेतामध्ये काम करण्याची मजुरी दिली जाते. अंगावर कापूस वेचण्याचे काम घेतले तर महिलांना 200 ते 500 रुपयांपर्यंत रोज पडू शकतो. एवढ्या प्रमाणात मजुरांना मजुरी मिळत असेल तर 127 रुपयांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामावर कोणता मजूर येऊ शकेल ? ग्रामीण भागाची पायाभूत विकास सुविधा रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून आपल्याला तयार करावयाची आहे. नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे, मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड, ऑदर डिस्ट्रीक्ट रोड, क्लासीफाईड व्हीलेज रोड व अनक्लासीफाईड व्हीलेज रोडला रोजगार हमी योजनेशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. शेत रस्ते जिल्हा परिषदेच्या

श्री. अरुण गुजराथी...

माध्यमातून किंवा डीपीडीसीच्या माध्यमातून घेतले जात असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत विकास सुविधा देण्याच्या संदर्भात रोजगार हमी योजना कशी राबवता येईल यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

सभापती महोदय, केंद्र शासनाची 100 दिवसांची व राज्य शासनाची 265 दिवसांची मजुरी रोजगार हमी योजनेसाठी वापरली पाहिजे. रोजगार हमी योजनेची अगोदरची मजुरी 68 रुपये होती व त्यानंतर ती 105 रुपये झाली. केंद्र शासनाची रोहयोची मजुरी 127 रुपये आहे. राज्य शासन रोहयासाठी किती मजुरी देते याची मला माहिती नाही. परंतु रोहयोची मजुरी वाढवून देण्याच्या संदर्भात मंत्री महोदयांनी विचार करावा असे मला वाटते.

सभापती महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे संपूर्ण देशात 4 कोटी लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. खरे म्हणजे या योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने फार मोठी ऊडी घेतलेली आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेमुळे 880 कोटी तास रोजगार निर्मिती झालेली आहे. अजून देखील रोजगाराची किती गरज आहे हे दिसून येते. रोजगार हमी योजनेचा सर्वात जास्त फायदा आदिवासी भागात झालेला आहे. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेच्या मिळणा-या मजुरीवर मजुराचे जीवन सुरु आहे. आदिवासी भागात रोहयाची कामे करीत असतांना यासंदर्भातील अटी शिथिल करता येतील काय याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात 60-40 हा जो रेश्यो आहे तो प्रथम बंद करण्याची आवश्यकता आहे. अकुशल 60 व कुशल 40 हा जो रेश्यो आहे तो सुध्दा बंद करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला जर जलसंवर्धनाची कामे घ्यावयाची असेल तर त्यासाठी 51-49 हा जो आताचा रेश्यो आहे तो सुध्दा बदलण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

श्री.अरुण गुजराथी ..

या संदर्भात माननीय मंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आजच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मला माननीय मंत्र्यांकडे दोन प्रमुख मागण्या करावयाच्या आहेत. त्यातील पहिली मागणी अशी आहे की, विदर्भात ज्या जिल्हयांमध्ये शेतकरी आत्महत्या करतात त्या जिल्हयातील कोरडवाहू आणि अल्प भू धारक शेतकरी स्वतः शेतामध्ये काम करीत असतील तर त्यांना शासनाने मजुरी दिली पाहिजे. रोजगार हमी योजनेचा विस्तार अशा पध्दतीने करण्यात यावा असे मला सांगावयाचे आहे. रोजगार हमी योजना ही अत्यंत चांगली योजना आहे त्या योजनेच्या माध्यमातून मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर निर्माण व्हावयास पाहिजे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे या विद्यापीठाला नाव देण्यापूर्वी त्या विद्यापीठातील काही व्यक्तींनी क्रिएशन ऑफ असेटसचा अभ्यास केला होता. आता पर्यंत रोजगार हमी योजने मार्फत महाराष्ट्रात जे पैसे खर्च झालेले आहेत त्या पैशातून किती कोटी रुपयांची मालमत्ता निर्माण झाली याचा त्यांनी अभ्यास केला होता त्यावेळी त्यांना असे आढळून आले की, रोजगार हमी योजनेतून ज्या प्रमाणात पैसे खर्च झाले होते त्या प्रमाणात मालमत्तेची निर्मिती झालेली नाही. तेव्हा रोजगार हमी योजनेच्या कामातून मालमत्तेची निर्मिती होणे अत्यंत महत्वाचे आहे असे मला सांगावयाचे आहे. गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून राज्यामध्ये रोजगार हमी योजना सुरु आहे परंतु असे म्हटले जाते की, " रोजगार हमी, काम कमी किंवा रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही " रोजगार हमी योजनेच्या एखाद्या कामात जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर ती योजना बंद न करता त्यातील भ्रष्टाचार कसा थांबविता येईल या दृष्टीने विचार करून रोजगार हमी योजना आणखी पुढे कशी नेता येईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.नियोजन विभागाला अत्यंत चांगले व कार्यक्षम मंत्री लाभलेले आहेत तेव्हा मी आताच उल्लेख केल्याप्रमाणे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील जे शेतकरी स्वतःच्या शेतात काम करतील त्यांना देखील शासनाने मजुरी देण्याची व एक पायलट योजना सुरु करावी. केन्द्रीय कृषी मंत्री आदरणीय श्री शरद पवार यांनी दहा पंधरा वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेतून फलोत्पादन योजना हाती घेतली होती. एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या खाजगी शेतात फळ झाडे लावली तर त्याचे पैसे देखील शासनाकडून देण्यात येतील अशा प्रकारची ती योजना होती. आज राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत कठीण झालेली आहे त्यामुळे पीक घेण्याकरिता स्वतःच्या शेतामध्ये जर ते काम करीत असतील तर त्यांना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मजुरी देण्याची योजना सुरु

2..

श्री.अरुण गुजराथी ..

केली पाहिजे. ही योजना सुरु करीत असतांना आवश्यकता असेल तर ठराविक दिवसांची मर्यादा टाकण्यात यावी. त्या शेतक-यांना 365 दिवस मजुरी दिली पाहिजे असे मी म्हणणार नाही परंतु निदान 100 दिवस तरी त्यांना रोजगार मिळावा या दृष्टीने शासनाने प्रयत्न करावा अशी माझी शासनाला विनंती आहे.

सभापती महोदय, मध्यंतरी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभाची कामे देखील घेता येतील असे सांगलीला सांगितले होते. शेतक-यांच्या शेतात सिंचन विहिरी , बांद बंदिस्तीची कामे, वृक्षारोपण इत्यादी कामे घेता येतील असे सांगितले होते. त्याच्याही पुढे जाऊन आपण एक पाऊल टाकले पाहिजे. महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे .महाराष्ट्राने केवळ देशालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला रोजगार हमी योजनेची देणगी देण्याचा विचार केला होता .तेव्हा मी सांगितल्या प्रमाणे जो शेतकरी आपल्या शेतात पिके घेण्याकरिता मजुरी करील त्याला देखील शासनाकडून मजुरी देण्यात येईल अशी योजना राबविण्याच्या संदर्भात शासनाने विचार करावा.

सभापती महोदय, माझ्याकडे काही आकडेवारी असून ती आकडेवारी मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. रोजगार हमी योजनेतून अनुसूचित जातीच्या लोकांनी चांगल्या प्रकारे रोजगाराची निर्मिती केली आहे . जवळजवळ 51 लाख अनुसूचित जातीच्या लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता तसेच अनुसूचित जमातीच्या 23.36 टक्के लोकांनी रोजगार हमी योजनेचा लाभ घेतला होता. रोजगार हमी योजना ही एक अत्यंत चांगली योजना आहे. केन्द्र सरकारच्या योजनेतून मजुरांना मिळणारा मजुरीचा दर आणि राज्यातील रोजगार हमी योजनेतून मजुरांना मिळणारा दर यामध्ये तफावत आहे. म्हणूनच 127 रुपये जर केन्द्र सरकाराने दिले तर वरचे फरकाचे पैसे आपण देऊ शकतो काय याचा विचार आपल्याला करता येईल. मघाशी बोलत असतांना सन्माननीय सदस्यांनी 26 कलमासंबंधी उल्लेख केला होता.ज्या राज्यामध्ये ही योजना सुरु आहे त्यांना वेगळ्या पध्दतीने ही योजना राबविता येईल.तेव्हा केन्द्र सरकार तर 127 रुपये मजुरी देत असेल तर वरचे पैसे राज्य सरकारने टाकून त्या लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला तर 100 दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जलसंवर्धन,नॉन क्लासीफाईड रोडस आणि शेत रस्ते

3..

श्री.अरुण गुजराथी ...

इत्यादीची कामे मोठया प्रमाणावर होऊ शकतील. रोजगार निर्मिती ही शासन व आर्थिक नियोजनकार यांचे लक्ष वेधून घेण्यामध्ये प्रमुख प्राधान्यक्रमामध्ये आहे. ज्याप्रमाणे राईट टू एज्युकेशन आपण आता म्हणत आहोत त्याप्रमाणे या देशात एक दिवस असा येईल की, त्या दिवशी राईट ऑफ एम्प्लायमेंट म्हणावे लागेल. आज तसे म्हणता येत नाही. घटनेने आज देखील आपण तशा प्रकारचे स्वरूप दिलेले नाही.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री जमा यांनी बोलतांना असे सांगितले की, शहरी विभागात ही योजना नेण्याच्या दृष्टीने शासनाने विचार केला पाहिजे. तेव्हा सुशिक्षित बेरोजगारांना दर महा आपण काही रोजगार देऊ शकतो काय याचा देखील शासनाने विचार करावा असे मला या निमित्ताने सांगावयाचे आहे.

नंतर श्री.सरफरे

श्री. अरुण गुजराथी....

ग्रामीण भागामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्याप्रमाणे शहरी भागामध्ये सुध्दा आहेत. त्यांना महिना 500, 2 हजार किंवा 3 हजार रुपये द्यावेत अशी त्यांची मागणी आहे. किंवा इयत्ता 12 वीपर्यंतचे शिक्षण घेत असतील तर त्यांना अमूक इतकी रक्कम द्यावी किंवा पदवीधर असतील तर त्यांना त्या प्रमाणात रक्कम द्यावी अशी मागणी होत असते. त्याबाबत सुध्दा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांना नोकरीकरिता मुलाखतीला जावे लागत असेल तर त्यांच्या प्रवास भाड्यामध्ये आपण त्यांना सवलत देत असतो. यावर्षी माननीय केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की, पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना रेल्वेने मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात येईल. त्याप्रमाणे आपण बेरोजगारांना एक ओळखपत्र देऊन त्यांना मुलाखतीला जाण्यासाठी रेल्वे किंवा एस.टी. बसेसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा देऊ शकतो काय याचा विचार करावा. अशाप्रकारचे महत्वाचे मुद्दे मांडण्यास आपण मला संधी दिल्याबद्दल आपले आभार मानून माझे भाषण संपवितो.

श्रीमती शोभाताई फडणवीस (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. एस. क्यू. जमा यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाबद्दल मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करते.

सभापती महोदय, त्यांनी आपल्या प्रस्तावामध्ये मांडलेल्या विषयाच्या संदर्भात सांगावयाचे झाले तर ती आज एक काळाची गरज निर्माण झाली आहे. एकीकडे आपण म्हणतो की, महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारने आणली. परंतु या योजनेमध्ये आपल्याला खऱ्या अर्थाने बदल करता येईल काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना या राज्यामध्ये आणली होती, त्यानंतर केंद्र सरकारची महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आपण राज्यामध्ये राबवीत आहोत. या दोन्ही योजनांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. या राज्यामध्ये 1972-73 सालापासून रोजगार हमी योजना राबवीत आहोत. त्यानंतर या योजनेला कायद्याचे स्वरूप देण्यात येऊन आणि खऱ्या अर्थाने ही योजना कायद्यामध्ये बसवून राज्यामध्ये राबविली जात आहे. अशाप्रकारे विकासाच्या कामामध्ये लोकांचा सहभाग घेणारी, काम मागणाऱ्या मजुरांना काम मिळवून देणारी, आणि लोकांच्या गरजेनुसार कामे करणारी योजना म्हणून तिला आपण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसविली. सुरुवातीला राज्यामध्ये ही योजना राबवीत असतांना ती 60/40 च्या रेश्योमध्ये बसवून ग्रामपंचायतींना कामे देण्यात आली. परंतु या योजनेची कामे ग्रामपंचायतींनीच केली पाहिजेत अशाप्रकारचा अड्डाहास नव्हता. आपण ही कामे शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून करित होतो. परंतु ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मजूर मिळवित होतो, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मजुरांची नोंदणी करित होतो व त्या माध्यमातून त्यांना काम देत होतो. मजुरांनी कामांची मागणी करून सुध्दा 1 ते 14 दिवसापर्यंत त्यांना काम देऊ शकलो नाही तर त्यांना 1 रुपया बेकार भत्ता दिला जात होता. अशाप्रकारे राज्यामध्ये लोकप्रिय झालेली योजना केंद्राने स्वीकारल्यानंतर त्यामधील बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टींना फाटा देण्यात आला.

आपण सुरुवातीला या योजनेमध्ये 60/40 चा रेश्यो आणल्यानंतर पुन्हा सुधारणा करून 49/51 चा रेश्यो कशासाठी आणला? याचे कारण 60/40 च्या रेश्योमध्ये ती कामे बसत नव्हती. त्यामुळे त्या रेश्योमध्ये ही कामे बसण्याकरिता गिड्टी आणि मुरुम यांच्या वहातुकीवरील खर्च स्वतंत्र केला आणि 49/51 या रेश्योमध्ये आपण कामे सुरु केली. अशाप्रकारे आपण रेश्योमध्ये बदल

DGS/ MMP/ D/

श्रीमती शोभाताई फडणवीस....

केल्यानंतर राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेऊ शकलो. परंतु आता महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 60/40 च्या रेशोमध्ये कामे बसत नाहीत हे आपले पहिले दुर्दैव आहे. त्यामुळे या योजनेमध्ये बदल करीत असतांना आपल्याला 60/40 च्या रेशोमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. दुसरे असे की, आज वहातुकीच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे, सिमेंटचे दर वाढले आहेत, पूलाचे बांधकाम करावयाचे असेलतर पाईप आणि इतर मटेरिअलचे सुद्धा दर वाढले आहेत. त्यामुळे जुन्या एस्टीमेटमध्ये ही कामे बसत नाहीत म्हणून या योजनेचा सर्वांगीण विचार झाला पाहिजे. याठिकाणी रोजगार हमी योजना आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्ही योजना एकाच वेळी राबविण्याचा आपला उद्देश होता. परंतु या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आल्यानंतर आपली रोजगार हमी योजना बाजूला ठेवून आपण ती ग्रामपंचायतीकडे सोपविली आणि ती राबविण्याचे सर्व हक्क ग्रामपंचायतींना दिले. परंतु या योजनेच्या माध्यमातून एकही पैसा विदर्भामध्ये आलेला नाही हे मी ठामपणे याठिकाणी सांगते. जवाहर विहिरीच्या योजना किंवा वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजना महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये नव्हत्या. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या निधीमधून वैयक्तिक लाभार्थी योजना राबवाव्यात असे ठरविण्यात आले. ही योजना राबवितांना आपण सन 2008-09 मध्ये 300 दिवस प्रति तालुका अशापध्दतीने कामांची वाटणी केली व त्या कामांना मंजुरी दिली. त्यानंतर लोकांनी आपल्या शेतामध्ये खोदकाम सुरु केले. परंतु लोकांनी केलेल्या कामांचे पैसे अजूनपर्यंत त्यांना मिळाले नाहीत. या सभागृहामध्ये 14 तारखेला माझा तारांकित प्रश्न आला होता, त्याला शासनाकडून उत्तर देण्यात आले की, "हा प्रश्न उद्भवत नाही." रोजगार हमी योजना ही स्वतंत्र योजना असल्यामुळे आम्ही सरकारच्या बजेटवर कोणत्याही प्रकारे आर्थिक भार येऊ दिलेला नाही.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

श्रीमती शोभा फडणवीस

शासन प्रोफेशनल टॅक्सच्या रुपाने लोकांकडून पैसे घेते आणि त्या माध्यमातून मजुरांना काम देऊन विकास करावयाचा अशी अतिशय चांगली आणि विकासाची योजना हाती घेतली. परंतु आज अशी स्थिती आहे की, रोजगार हमी योजनेच्या नावाखाली लोकांकडून प्रोफेशनल टॅक्स वसूल केला जातो.परंतु तो पैसा परत जनतेपर्यंत जावयास पाहिजे, ते होत नाही.आता महाराष्ट्र रोजगार ही एकमेव योजना सर्व विभागांमध्ये राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे.मग यामध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत? ज्याप्रमाणे 60:40 चा रेषो आहे तसाच आणखीही आहे.आपण ग्राम पंचायतीला सर्व अधिकार दिले आहेत की, तुम्ही एस्टीमेट तयार करावे,जॉब कार्ड काढावे,मजुरांना काम द्यावे. सभापती महोदय, आपण मला सांगावे की, जर मेळघाट मधील किंवा गडचिरोली मधील ग्राम पंचायत असेल, नंदूरबार येथील ग्राम पंचायत असेल त्याठिकाणी त्यांना कोणता इंजिनिअर एस्टीमेट करुन देणार आहे ? पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतील अधिकारी सांगतात की, आमच्याच कडे मोठया प्रमाणात जागा रिक्त आहे, त्यामुळे आमचीच कामे आम्हाला पूर्ण करता येत नाहीत तर तुम्हाला कुठून द्यावयाची. त्यामुळे ही योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतीला इंजिनिअर मिळू शकत नाही. त्यामुळे एस्टीमेट करण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये इंजिनिअर नाहीत. अशा वेळी या योजनेच्या बाबतीत इंजिनिअरमार्फत एस्टीमेट तयार करुन देण्याची एकतरी जबाबदारी सरकार घेणार आहे काय ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

सभापती महोदय, दुसरे म्हणजे त्याठिकाणी कशा प्रकारे कामे होत आहेत हे पहाण्यासाठी ग्राम पंचायत मध्ये तेवढे कोणी विद्वान नाहीत.तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेमध्ये एस्टीमेट तयार करण्याची जी पध्दत आहे, ती अतिशय किचकट आहे.जर रस्त्याचे काम करावयाचे असेल तर त्याला किती कट घ्यावयाचा, त्याचे अंतर किती असाव, जमिनीपासून वर किती पाहिजे, जमिनीच्या खाली किती फूटापर्यंत जावयाचे इ.क्लिष्ट बाबी असल्यामुळे इंजिनिअर देखील एस्टीमेट करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे शासनाला कोणतीही गोष्ट करावयाची असेल तर सोप्या आणि सरळ भाषेमध्ये असावी असे माझे स्पष्ट मत आहे.त्यामुळे यामध्ये सर्वच बाबतीत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.पूर्वी रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करण्याची लोकांमध्ये आवड होती आणि याचे कारण म्हणजे आपण त्यांना बऱ्याच सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या होत्या. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून काम करीत असताना दुपारी जेवण करण्यासाठी मजुरांना कुठेतरी सावलीची जागा असली पाहिजे. पण शासनाने तशी जागा उपलब्ध करुन दिली काय हा प्रश्न आहे. त्याच -

श्रीमती शोभा फडणवीस

बरोबर रोजगार हमी योजनेच्या ठिकाणी जर महिला काम करीत असतील तर तेथे त्यांच्या मुलांसाठी पाळणा घर असले पाहिजे, तसे आपण दिलेले आहे काय ? तसेच तेथे फर्स्ट-एड बॉक्स असावयास पाहिजे, औषधांची सुविधा असली पाहिजे. परंतु आज आपण अशा सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत काय ?

श्री.सुरेश नवले (खाली बसून) : सध्या कामच नाही तर सुविधा कशा देणार ?

श्रीमती शोभाताई फडणवीस : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छिते की, जेथे काम सुरु आहे तेथे तरी या सुविधा दिल्या पाहिजेत. परंतु यातील एकही सुविधा उपलब्ध करून दिली जात नाही. मग मजुरांवर उन्हामध्ये बसून जेवण्याची वेळ येते, जर तेथे महिला काम करीत असतील तर त्यांनी आपल्या मुलांना उन्हामध्ये ठेऊन जेवण करावयाचे अशी स्थिती आहे. जर या योजना कायदानुसार आहेत तर त्या राबविल्या गेल्या पाहिजेत. शासनाचे असे म्हणणे आहे की, आपण 127 रुपये रोज याप्रमाणे मजुरांना काम देतो आणि ही मजुरी ठरलेली आहे. पण आम्ही मजुरांना त्यांच्या मेहनतीवर रोजी देतो म्हणजे जेवढे काम करील तेवढे पैसे देतो. पण तसे करीत असताना उन्हाळा आणि हिवाळ्यामधील वातावरणाचा विचार केला जातो काय ? उन्हाळ्या मध्ये माती कडक होते. अशा वेळी मजुरांना माती खणून ती दूर अंतरावर नेऊन टाकावयाची असते परंतु त्या मजुरांना तसे करणे कठीण होते आणि मजुराला या कामासाठी आवश्यक असलेली मजुरी मिळत नाही. त्यामुळे तो कामावर येत नाही. परंतु हिवाळ्यामध्ये तेच काम करणे त्याला सोपे असते. म्हणून मजुराने खणलेली माती दूर अंतरावर नेऊन टाकण्याचे काम करीत असताना उन्हाळा आणि हिवाळ्यातील वातावरणाचा देखील विचार झाला पाहिजे. अशा पध्दतीने काम करीत असताना आपण या मजुरांना खऱ्या अर्थाने त्यांची मजुरी, त्यांची जी मेहनत आहे, त्याची आपण किंमत देत आहोत हे जरी लक्षात घेतले तरी आपल्याला यामध्ये मोठया प्रमाणात बदल करता येऊ शकेल. तसेच रस्त्यांची, शेत तलावांची, बंधान्याची, नहरांची अशी विविध कामे असतात. जे मोठे तलाव आहेत, त्यांच्या नहरांची कामे रोजगार हमी योजनेतून काढून टाकली आहेत. याचे कारण काय आहे? खरे म्हणजे त्याठिकाणी त्यांना रोज काम मिळते. मशिनने काम केले पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्ट पध्दतीने काम केले पाहिजे असे कुठेही नाही. मी बोलले तर कदाचित या सदनामध्ये आरोप केल्यासारखे होईल. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मशीनद्वारे कामे होतात. परंतु विदर्भामध्ये जर एखादी

श्रीमती शोभा फडणवीस

मशीन आणण्यात आली तर सगळ्यात पहिल्यांदा तेथील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते.तेव्हा एका भागासाठी एक न्याय आणि दुसऱ्या भागासाठी एक न्याय असे का? शासन मशिनव्दारे काम करण्यासाठी परवानगी का देत नाही ? मशीनने जर माती काढण्यात आली तर ती उपसण्याकरता आमचे मजूर तयार आहेत. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच प्रकारचे धोरण राबवावे. त्यासाठी पहिल्यांदा केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये बदल करता येईल काय ते पहावे. नाहीतर आपल्या राज्याची जी रोजगार हमी योजना आहे, ज्याच्यासाठी आजही प्रोफेशनल टॅक्सच्या माध्यमातून साडेतीन हजार कोटी रुपये गोळा करित आहात, ती योजना आमच्यासाठी राबविण्यात यावी. तसेच वैयक्तिक लाभार्थींना योजना दिली जाते, ती पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात यावी. तसेच लोकांना जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड देण्यात यावे.

सभापती महोदय, मी एक बाब सांगू इच्छिते की, मी एका गावामध्ये गेले होते. या मजुरांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आले होते. त्या स्मार्ट कार्डच्या आधारे तो मजूर आपल्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी रुग्णालयामध्ये गेला असता, त्याला डॉक्टरांकडून असे सांगण्यात आले की, पेन ड्राईव्हवरील तपशीलामध्ये तुझे नावच नाही. सभापती महोदय, ग्रामीण भागातील आदिवासीला पेन ड्राईव्ह म्हणजे काय हे कसे समजणार, या मजुरांना स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड म्हणजे काय, पेन ड्राईव्ह म्हणजे काय, कॉम्प्युटर म्हणजे काय? हे समजत नाही. आपण महाराष्ट्रामध्ये रहात आहोत. त्यामुळे अशा प्रकारचे इंग्रजी शब्द न वापरता मराठी शब्दाचा वापर करावयास शिकले पाहिजे. तसेच या मजुरांनाही न्याय द्यावयास पाहिजे एवढेच मला सांगावयाचे आहे.

यानंतर कु.थोरात

श्री. हेमंत टकले (विधानसभेने निवडलेले) सभापती महोदय, नियम 260 अन्वये अतिशय महत्वाच्या विषयावर आज या सभागृहात चर्चा होत आहे. खरे म्हणजे आज आपण या विषयावर चर्चा करताना आपल्या राज्यामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या लोकसंख्या विचार केला तर आपल्याला असे दिसून येते की, आपल्या कुठल्याच योजना या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचत नाहीत म्हणून सर्वच योजनांमध्ये काही गुणात्मक बदल करता येतील काय, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. माझ्या सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी इतर राज्याची काही उदाहरणे दिलेली आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारने सन 2010 मध्ये 4 कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या अतिशय महत्वाकांक्षी योजनेचा उल्लेख केला आहे. या योजनेतील इतर राज्यांच्या टक्केवारीचा विचार करता महाराष्ट्राची टक्केवारी किती नगण्य आहे, हेही या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. शेवटी हा सगळा प्रश्न कशाशी निगडित आहे?. लोकसंख्येचा विचार केला तर जगामध्ये सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारताची गणना होते तशीच चीनची सुद्धा गणना होते. पण आपल्याला उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा अतिशय चांगला वापर करून घेतला तर विकासाच्या दृष्टीने हे मनुष्यबळ आपल्याला जगातील महासत्ता बनविण्यासाठी उपयोगी पडू शकते हा मूलभूत सिध्दात आहे. आपण आपल्या जवळ उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा योग्य प्रकारे वापर करून घेण्यास असमर्थ ठरतो आहोत की काय, अशा प्रकारचा एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो.

सभापती महोदय, आपल्या राज्याची रोजगार हमी योजना असेल किंवा केंद्र शासनाची रोजगार हमी योजना असेल, 100 दिवसांची मजुरी असेल या सगळ्या सांख्यिकी गोष्टींमध्ये जाऊन मी सभागृहाचा वेळ घेऊ इच्छित नाही पण यासंदर्भात मूलभूत सिध्दात असा आहे की, ग्रामीण भाग जेव्हा सक्षम होईल, त्यांची क्रय शक्ती जेव्हा वाढेल त्यावेळी गावाकडून येणारे लोंढे कमी होतील आणि शहरांवर पडणारा ताण कमी होईल. शहरांमध्ये द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांवरील ताणही कमी करता येईल. अगदी गाव पातळीपर्यंत जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने झाली तर कदाचित गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या गोष्टी आणि आवश्यक त्या प्राधान्यक्रमाने घेण्याची बाब या सगळ्या योजनांमध्ये कुठे अंतर्भूत होते काय चाचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. अनेक ठिकाणी असे दिसून येते की, जी यंत्रणा यासाठी राबविण्यात येते, त्या

..2..

श्री. हेमंत टकले....

यंत्रणेमध्ये निश्चितपणे दोष आहेत. अनेक वर्तमानपत्रे काढून पाहिली तर त्यामध्ये मजुरांची संख्या घटताना दिसत आहे. या योजनेमध्ये छोट्या-छोट्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराला अतिशय सहजतेने वाव मिळेल अशा पध्दतीने कारभार केला जात आहे. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होऊन या योजनांचा दृश्य स्वरूपात काही तरी परिणाम झालेला आहे, जीवनमानामध्ये फरक झाला आहे, असे आपल्या निदर्शनास येते काय, असाही प्रश्न मला या निमित्ताने विचारावासा वाटतो. सन्माननीय सदस्या श्रीमती शोभाताई यांनी या ठिकाणी उल्लेख केला की, रोजगार हमी योजनेवर खडी फोडण्याचे काम असेल तर साधारणतः 20 वर्षापूर्वी खडी फोडणाऱ्या कामगारांना खडी फोडतांना दगडाचे कपचे उडून त्यांच्या डोळ्यात जाऊ नयेत म्हणून गॉगल्स खरेदी करण्याची एक योजना शासनाने आणली होती.

यानंतर श्री. बरवड....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

श्री. हेमंत टकले ...

चामड्याचे पट्टे लावलेले गॉगल्स सगळ्या मजुरांना द्यावयाचे होते. त्या काळामध्ये त्याची किंमत जवळपास 60 रुपये होती आणि त्या योजनेमध्ये शासनाची खरेदी साधारणतः 200 रुपये प्रमाणे झाली. असा गुणाकाराच्या पध्दतीने वाढणारा भ्रष्टाचार जर या योजनांमध्ये कोठे तरी शिरत असेल तर हल्लीच्या नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे हे सगळे व्हायरस या वेगवेगळ्या कारणांनी या योजनेमध्ये घुसतात आणि योजनेचा बोजवारा उडवून टाकतात. हे दुरुस्त करण्यासाठी कोठे तरी आता प्रयोगशीलतेची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रोजगार हमी योजनेसाठी एका उप जिल्हाधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. त्यांचे काम मूल्यमापन करण्याचे असते. आपण आता इतके पुढे चाललो आहोत की, युनिक आयडेंटिफिकेशन कोडद्वारे आपण प्रत्येक नागरिकाचे आयडेंटिफिकेशन करणार आहोत. तिथपर्यंत आपण पोहचू शकतो. जर याचे विकेंद्रीकरण खालच्या पातळीवर नेण्यापर्यंत पोहोचणार असू तर एक छोटे केंद्र, एक गाव, एक खेडे, त्याची लोकवस्ती किती, त्यामध्ये शेती किती, त्यामध्ये माणसे किती, त्यामध्ये स्त्रिया किती, त्यामध्ये रोजगारांची आवश्यकता असणाऱ्या किती, ही सगळी माहिती आपल्याला उपलब्ध का होऊ शकत नाही ? त्या माहितीच्या आधारे जर आपल्याला नियोजन करावयाचे असेल तर उप जिल्हाधिकारी असो किंवा नियोजन अधिकारी असो, हे सगळे अधिकारी काय करीत आहेत ? या कामांमध्ये बऱ्याच वेळा असे दिसून येते की, जी कामे घ्यावयास पाहिजेत ती न घेता उगाचच दुसरीच काही तरी कामे दाखवून कागदोपत्री त्याची पूर्तता केली जाते. केवळ कागदोपत्री पूर्तता करून त्या माणसाच्या जीवनामध्ये जर काही फरक पडणार नसेल तर अशा कितीही योजना आल्या तरी दारिद्र्य रेषेखालील या राज्यातील जनतेची आज जी संख्या आहे ती काहीही केल्या कमी होणार नाही. त्यामुळे फार गांभीर्याने या योजनेचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

सभापती महोदय, आपल्या राज्याने एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ही योजना चालू केली. मग दुष्काळावर मात करण्यासाठी असेल, त्यासाठी ही योजना केली असेल. कारण कोणत्याही संकटानंतर काही तरी चांगल्या गोष्टी घडतात तशी ही महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. अरुणभाई गुजराथी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या योजनेचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला, ज्या योजनेची आंतरराष्ट्रीय नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञांनी वाखाणणी केली,

RDB/ KTG/ KGS/

श्री. हेमंत टकले

इतके सगळे चांगले असताना ही योजना चांगली न चालण्याची जी काही कारणे आहेत त्याची एखाद्या त्रयस्थ संस्थेकडून पाहणी करण्याची गरज आहे.

सभापती महोदय, जेव्हा आपण या सगळ्या नागरिकांचा विचार करतो, जे बेरोजगार आहेत, ज्यांचा आज रोजीरोटीचा प्रश्न आहे त्यांच्या करिता रोजगार निर्माण करणे इथपर्यंतच जर आपण मर्यादित राहिलो तर मला असे वाटते की, आपला हा सुखवस्तूपणा कोठे तरी या सगळ्या योजनेच्या आड येणार आहे. कारण एखाद्या मजुराला जर आपण आयुष्यभर खडीच फोडावयास लावली तर तो खडी फोडण्याच्या पलीकडे कोठलीही प्रगती करू शकणार नाही. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या या सगळ्या वर्गाची कुशलता वाढविण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये अधिक मूल्य येण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. आपल्या शासनाकडे अशा कोणत्या योजना आहेत की नाहीत, अशा योजना घेता येतील की नाहीत, याचाही विचार केला पाहिजे. या रोजगार हमी योजनेच्या कामावर अनेक स्त्रिया आणि पुरुष जात असतात. त्यांची लहान मुले असतात. त्या लहान मुलांच्या शिक्षणाची सोय होण्याची गरज आहे. मला असे वाटते की, ऊस तोडणी कामगारांसाठी अशा तांड्यावरच्या शाळा आणि त्या तांड्यावरून फिरताना ते कोठे तरी कायम वस्तीला आल्यानंतर त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सोय असली पाहिजे. शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या, दैनंदिन गरजेच्या मूलभूत सुविधा त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. नुसती क्रयशक्ती वाढवली पण त्यामधून जर काहीच मिळत नसेल आणि त्या क्रयशक्तीतून निर्माण झालेले उत्पन्न जर चुकीच्या मार्गाने वापरले जाणार असेल आणि केवळ या सगळ्या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे जो निधी प्रत्यक्ष ज्या माणसापर्यंत पोहोचावयास पाहिजे तिथपर्यंत जर पोहोचलाच नाही तर हे राज्याचे दुर्दैव आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा पुनर्विचार करून याची पुन्हा एकदा मांडणी करावी. आपले राज्य या सगळ्यात अग्रभागी होते त्याप्रमाणे आपण दरवर्षीसाठी एक निश्चित उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे की,

यानंतर श्री. खंदारे ...

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

N-1

NTK/ KTG/ KGS/

श्री.बरवडनंतर

12:05

श्री.हेमंत टकले....

यावर्षी राज्याच्या रोजगार हमी योजनेवर झालेल्या कामांपेक्षा पुढील वर्षी 10 टक्के, 15 टक्के किंवा 20 टक्के अधिक वाढ करु, अधिक लोकांना रोजगार देऊ, सोयीसुविधा वाढवू अशा प्रकारचा व्यापक विचार यानिमित्ताने केला पाहिजे. त्या दृष्टीकोनातून हा प्रस्ताव महत्वाचा आहे. राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने, गोरगरीब जनतेच्या दृष्टीने, दारिद्र्य रेषेखालील असंख्य लोकांसाठी या योजनेचा अधिकाधिक उपयोग शासनाने करुन देण्याच्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलावीत अशी विनंती करुन मी माझे भाषण संपवितो.

2.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ KTG/ KGS/

श्री.दिलीपराव सोनवणे (नाशिक विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा यांनी नियम 260 अन्वये अतिशय महत्वाच्या विषयावर सभागृहात प्रस्ताव मांडलेला आहे. या प्रस्तावावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी याठिकाणी उभा आहे.

सभापती महोदय, राज्याच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून, केंद्र व राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजनेच्या रकमेमध्ये येत असलेल्या तफावतीबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही चर्चा उपस्थित करण्यात आलेली आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम या योजनेंतर्गत 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी दिलेली आहे. राज्याच्या रोजगार हमी योजनेमार्फत वर्षभर कामाची हमी दिलेली आहे. त्यामध्ये 80 टक्के जलसंधारणाची कामे तर 20 टक्के रस्ते व इतर कामे करण्याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून, यंत्रणांच्या माध्यमातून म्हणजे सा.बां.विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभाग व लघुसिंचन विभाग यांच्यामार्फत 50 टक्के कामे केली जाणार आहेत. अशाप्रकारे कामाचे नियोजन होत असताना या रेश्योमध्ये बदल करण्याचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत 50 टक्के कामे केली जाणार आहेत. परंतु तेथील ग्रामसेवकांकडून कामे करीत असताना त्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना एस्टिमेट तयार करणे, कामाचे मोजमाप करणे, एम.बी.रेकॉर्ड करणे अशा कामांचे प्रशिक्षण दिले तर त्याचा फायदा होईल. एमआरइजीएस अंतर्गत कृषी विभागांतर्गत जास्तीत जास्त कामे होत होती, जलसंधारणाची कामे होत होती. परंतु कृषी विभागाकडून सध्या कामेच केली जात नाहीत. त्याठिकाणी लाभक्षेत्राच्या अडचणी असतील, अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचे काम असेल तर त्यावर सुध्दा विचार अहोणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, शेतकऱ्यांकडे असलेल्या मजुरांचे रजिस्ट्रेशन केले पाहिजे. सन्माननीय सदस्य श्री.अरुण गुजराथी यांनी शेतीसाठी, पिकासाठी सूचना केली आहे. त्यानुसार पिकांच्या संदर्भात रोहयोच्या मजुरांना अधिक मजुरी देण्याबाबत शासनाने विचार केला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मदत होईल. एक प्रकारे शेतकऱ्यांना सबसिडी दिल्यासारखे होईल व शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. ही योजना चांगल्या प्रकारे राबविण्यासाठी रोजगाराची निर्मिती करता येईल. त्याचप्रमाणे आदिवासी भागामध्ये अधिक रोजगार निर्मिती करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली

3...

श्री.दिलीपराव सोनवणे.....

पाहिजेत. मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो की, फलोत्पादनातील फळबाग लागवड असेल, शेतीची कामे असतील, एमएसइबीची कामे असतील, ग्रामीण भागातील पायाभूत विकासाची कामे असतील या सर्व कामांचा समावेश रोहयोच्या कामात केला तर त्याचा निश्चितपणे फायदा होईल.

मी यानिमित्ताने शासनाला विनंती करतो की, सध्या मगारोहयोच्या मजुरांना 127 रुपये मजुरी दिली जाते ती वाढवावी आणि फरकाची रक्कम राज्य सरकारने दिली तर मजुरीचा प्रश्न सुटेल. मजुरांना रोजगार मिळत नाही असे म्हटले जाते तो सुध्दा प्रश्न सुटू शकेल. याबाबतचा पॅटर्न सुध्दा बदलणे आवश्यक आहे. मी मघाशी सांगितल्याप्रमाणे या योजनेचा रेश्यो ठरविलेला आहे तो 80:20 याएवजी 51:49 असा करण्यात यावा. तसेच लोकांच्या गरजेनुसार कामे घ्यावीत अशीही सूचना करतो. सर्व शेतकऱ्यांसाठी व्यक्तिगत लाभाच्या योजना सुरु कराव्यात. त्यामध्ये विहीर, नालाबंडिंग, शेततळे बांधणे, लहान बंधारे बांधणे याचा त्यात समावेश करावा. सामुहिक शेतीवरील कामे सुरु करण्यात यावीत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नर्सरी असेल, फलोत्पादन असेल, शेतीतील कामे असतील, प्रत्यक्ष शेतीसाठी लागणारे मनुष्यबळ असेल, व्यक्तिगत लाभाच्या योजना अशा प्रकारे या सगळ्या कामांचा समावेश केला तर त्याचा निश्चित फायदा होईल. सभापती महोदय, मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो की, राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फलोत्पादन, एमएसइबी, शेतीची कामे, कृषी क्षेत्रातील कामे यासाठी तरतूद करुन ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न करावा. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो.

यानंतर श्री.शिगम.....

डॉ. नीलम गो-हे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.एस.क्यू.जमा यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभी आहे.

सभापती महोदय, राज्यातील रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात सभागृहामध्ये नेहमी चर्चा होते. 55 लाख मजुरांना जॉब कार्ड दिलेले आहे असे मंत्री महोदय श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी या सभागृहामध्ये सांगितले आहे. रोजगार हमी योजना राबविण्याच्या संदर्भात गेल्या 5-6 वर्षातील ही फार मोठी प्रगती आहे. 27 हजार ग्रामपंचायती पैकी 24315 ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेची कोणतीही कामे घेतलेली नाहीत. त्या गावातील लोकांना 100 दिवस देखील काम मिळालेले नाही. केन्द्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि राज्याची रोजगार हमी योजना या दोन्ही योजनेतून ग्रामीण भागातील लोकांना कामे दिली जातील. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर या दोन्ही योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील अशी घोषणा मागील अधिवेशनामध्ये करण्यात आली. सभापती महोदय, मला कुणावर वैयक्तिक टीका करावयाची नाही. आपण जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकाला सदस्य म्हणून असता. जेव्हा रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु करण्यासंबंधीचा प्रश्न चर्चेला येतो त्यावेळी अशी कुजबूज होते की जर रोहयोच्या कामावर मजूर गेले तर शेतीच्या कामावर मजूर मिळणार नाहीत. त्यामुळे ताई तुम्ही या विषयावर शांत रहा, असे मला सांगितले जाते. आज शेतक-याला शेती परवडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही राज्यामध्ये शेतकरी, अल्प भूधारक, भूमिहीन किती आहेत याचा अंदाज घेऊन कायम स्वरुपी किती लोकांना काम पाहिजे याची माहिती घेऊन त्या लोकांना रोहयोची कामे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.

सभापती महोदय, आमच्या सारखे शहरातील कार्यकर्ते ग्रामीण भागामध्ये काम करायला लागले त्यावेळी असे वाटले होते की रोहयोच्या कामावर जाणा-या मजुरांच्या संख्येमध्ये वाढ होईल, त्यांच्यामध्ये जागृती होईल आणि तसेच झाले. प्रत्येक ग्रामीण भागात काम करणा-या कार्यकर्त्यांने कधी ना कधी रोहयोच्या कामावरील मजुरांशी संवाद साधलेला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनातून मजुरांच्या अनेक संघटना ग्रामीण भागामध्ये उभ्या राहिल्या. श्रमशक्तीतून ग्राम विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरुप यावयास लागले. परंतु नंतर हळूहळू ग्रामीण भागातील या मजुरांच्या संघटना जिवंतच राहिल्या नाहीत. सभापती महोदय, आपण या रोहयोच्या मजुरांना

..2..

डॉ. नीलम गो-हे...

जेवढे जीवदान देऊ, प्रोत्साहन देऊ, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करू तेवढी रोहयोची अंमलबजावणी चांगल्या त-हेने होईल.

सभापती महोदय, विधान मंडळाची रोजगार हमी योजना समिती आहे. या समितीमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य असतात. ही समिती जिल्ह्यांना भेटी देऊन कामांचा आढावा घेऊन शासनाला शिफारशी करते. आता पर्यन्त या समितीने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून शासनाला ज्या ज्या शिफारशी केलेल्या आहेत त्यांचा आढावा घेतला तर कोणत्याही शिफारशीवर कारवाई झालेली नसल्याचे दिसून येईल. अनियमितता करणा-या कोणत्याही अधिका-यावर कारवाई झालेली नाही. सोलापूरमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामावर प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्पन्न झाले. काही अधिकारी दोषी आढळले. त्या प्रकरणी पुढे काय झाले हे माहित नाही. त्यावेळी मंत्री महोदय श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी असे सांगितले होते की, संबंधितांना कठोर शिक्षा होईल. एका अधिका-याने आत्महत्या केल्यानंतर तो विषय तेथेच संपला की काय असा प्रश्न निर्माण झाला.

सभापती महोदय, आपण रोजगार हमी योजनेच्या बाबतीत जशी रोजगार हमी योजना समिती गठीत केलेली आहे त्या प्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी देखील वेगळी अशी समिती गठीत करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी सध्याच्या समितीची कार्यक्षमता वाढवून घेण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि राज्याची रोजगार हमी योजना या दोन्ही योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील लोकांना दिली पाहिजे. नगरच्या बैठकीमध्ये रोहयोच्या कामावर प्रत्यक्षात किती मजूर होते याची माहिती अधिका-यांना देता आली नव्हती. वर्षानुवर्षे असे पहायला मिळते की, बजेटमध्ये वारेमाप मागणी केली जाते आणि अखर्चित राहिलेली रक्कम दुसरीकडे वळविली जाते. तेव्हा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी कोणतेही पक्षीय राजकारण न आणता मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये बैठक घेऊन रोहयो अंतर्गत किती मजुरांना काम मिळाले याची माहिती घेतली पाहिजे.

...नंतर श्री. गिते...

डॉ.नीलम गोन्हे....

महत्वाची गोष्ट म्हणजे रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांचे वेळेवर पगारच होत नाहीत. त्यामुळे लोकांचा या योजनेवरचा विश्वास उडालेला आहे. दोन-दोन महिने मजुरांना पगार मिळत नसेल तर मजूर म्हणतात की, रोजगार हमी योजनेच्या कामावर कशासाठी जावयाचे ? यामुळे एका चांगल्या योजनेवरचा जनतेच्या मनात अविश्वास तयार झालेला आहे. तो विश्वास पुन्हा कशा पध्दतीने उभा करावयाचा याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सभापती महोदय, माझा श्वेटचा मुद्दा असा आहे की, एखाद्या घटकाळा काही वेळा नाराज करावे लागते. परंतु सर्वांच्या हितासाठी तो निर्णय घ्यावा लागतो. काही योजना प्रबोधनाशी संबंधित असतात. मी तर असे म्हणेन की, प्रत्येक योजना कायद्याने चालत नाही. परंतु काही ठिकाणी मजुरांना काम नाही, त्या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेच्या प्रश्नावर राजकीय इच्छाशक्ती उभी करण्यासाठी म्हणून एकट्याने काम करून चालणार नाही, त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेऊन काम केले पाहिजे. त्याचबरोबर शेतीच्या कामासाठी मजूर उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे प्रश्न तयार झालेले आहेत. त्यासाठी तुम्हाला शेतीवर काम करायला मजूर पाहिजेत आणि एरवीच्या काळात रोजगार हमी योजना पाहिजे. याचे नियोजन लोकांना विश्वासात घेऊन केले गेले व त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली तर खूप चांगले होईल. मी आपल्याला सांगू इच्छिते की, मजुरांच्या संघटना नाहीत. ज्यांना ज्यांना मजुरांच्या संघटना तयार करावयाच्या असतील त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे काम सुध्दा राजकीय पक्षांनी केले पाहिजे असे मला वाटते. मला आपण बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल आभार व्यक्त करते आणि माझे मनोगत पूर्ण करते. धन्यवाद.

प्रा. सुरेश नवले (नामनियुक्त) : आदरणीस सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री. जमा यांना मनापासून धन्यवाद देईन की, त्यांनी या सभागृहात अतिशय चांगला प्रस्ताव चर्चेला आणला आहे.

सभापती महोदय, स्व.वि.स.पागे यांनी 1977 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधानपरिषदेमध्ये रोजगार हमी योजनेचे विधेयक संमत करून घेतले. ते विधेयक सभागृहात चर्चेला आले होते, त्यावेळी त्यांनी अतिशय चांगल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांच्या संकल्पनेचा अविष्कार म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे. ते त्यावेळी असे म्हणाले होते की, हे माझे जीवित्ताचे कार्य होते. हे माझ्या आयुष्याचे मिशन होते आणि सभागृहातील सर्व सदस्यांनी सदर मिशन पूर्ण केल्यामुळे मी पूर्णपणे समाधानी आहे. आज महाराष्ट्राने आशीर्वाद दिले, कदाचित उद्या भारत देश आशीर्वाद दिल्या शिवाय राहणार नाही. सभापती महोदय, त्यांनी सभागृहात अशा प्रकारची भावना व्यक्त केली, त्या भावनेचे प्रत्यंतर केंद्र शासनाने ही योजना स्वीकारल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्यांच्याही आत्म्याला समाधान मिळाले असेल. राष्ट्रपिता यांच्या नावाने ही योजना आहे. अनेक राज्यामध्ये ही योजना सक्रियपणे राबविली जात आहे. परंतु महाराष्ट्रातील चित्र मात्र अतिशय चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रात या योजनेकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, आपणास आठवत असेल की, या योजनेवर एकेकाळी लाखो मजूर काम करीत होते. "विठू माझा लेकूरवाळा" असे संपूर्ण चित्र महाराष्ट्रात या योजनेचे होते. गरिबाची गाय म्हणून या योजनेला संबोधिले जात होते. आज ही गरिबाची गाय लंगडी होऊन पडली आहे. तिला टेकू देण्याची आवश्यकता आहे. आमचे मंत्री महोदय अतिशय क्रियाशील आहेत. मला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की, महाराष्ट्रातल्या लाखो गरीब रोजगारांना एक प्रकारे आश्रय देणारे हे स्थान असून त्यांचे पुनरुज्जीवन करा.

यानंतर श्री. भोगले...

प्रा.सुरेश नवले.....

मध्यंतरी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केली होती. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की, आपल्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांचा एक अभ्यास गट नेमण्यात यावा. या सभागृहाचे माननीय सदस्य श्री.पाशा पटेल, माननीय सदस्य श्री.अरुणभाई गुजराथी यांचा या विषयामध्ये चांगला अभ्यास आहे. या योजनेबाबत पुनर्विचार करुन महाराष्ट्रामध्ये ही योजना सक्षमपणे राबविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, अशी माझी या निमित्ताने विनंती आहे.

सभापती महोदय, बीड जिल्हयातील 4 ते 5 लाख ऊस तोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र व राज्यातील इतर जिल्हयांमध्ये ऊस तोडणी करायला जातात. बीड जिल्हयातील मजुरांना रोजगार हमी योजनेवर काम करण्याची विनंती केली तर कोणताही मजूर रोजगार हमी योजनेवर काम करण्यास तयार नसतो. बीड जिल्हयामध्ये कापूस वेचणारी महिला दिवसाकाठी किमान 500 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीचा कापूस वेचते. माननीय सदस्या श्रीमती उषाताई दराडे यांच्यासारखी क्रियाशील महिला असेल तर दिवसाला किमान 700 रुपये किंमतीचा कापूस वेचते. आज रोजगार हमी योजनेचे जे चित्र आहे ते बदलण्याची गरज आहे.

सभापती महोदय, मध्यंतरी वृत्तपत्रामध्ये एक बातमी छापून आली होती. केंद्र शासनाने देशातील 4 कोटी मजुरांना नरेगा योजनेच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन दिला. माझी मंत्री महोदयांना आग्रहाची विनंती आहे की, या 4 कोटी मजुरांपैकी महाराष्ट्रातील मजुरांची संख्या किती आहे याची आकडेवारी सभागृहामध्ये जाहीर करावी. 2005 नंतर केंद्र शासनाने नरेगा योजना लागू केली. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला किती निधी प्राप्त झाला? त्यापैकी राज्य शासनाने किती निधी खर्च केला, याची आकडेवारी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ठेवावी अशी आपल्या माध्यमातून मी मंत्री महोदयांना विनंती करु इच्छितो. महाराष्ट्रामध्ये सर्वकष रोजगार हमी योजना लागू करावयाची असेल तर सर्व थरामध्ये ही योजना राबविली पाहिजे. महाराष्ट्र टॅकरमुक्त करावयाचा असेल तर या योजनेचा अतिशय परिणामकारक उपयोग करता येऊ शकतो. महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांची त्यांच्या शेतामध्ये शेततळे निर्माण करण्याची इच्छा असेल त्यांना या योजनेच्या माध्यमातून लाभ देता येऊ शकतो. लाखो शेततळी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात निर्माण करुन महाराष्ट्राला कायमस्वरुपी टॅकरमुक्त करता येईल. आज पाणीपुरवठा करणारे टॅकर अर्धे

..2..

प्रा.सुरेश नवले.....

फुटलेले आणि पाण्याने अर्धे भरलेले दिसून येतात, असे टँकर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाठविण्याची आवश्यकता भासणार नाही. दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याकरिता करोडो रुपये खर्च करावे लागतात, हा खर्च सुध्दा वाचविता येईल. पाझर तलाव निर्माण झाल्यामुळे एकप्रकारे भूगर्भामध्ये पाणी साठविले जाईल, पाणी जिरविता येईल आणि त्याचा चांगला परिणाम पर्यावरणावर देखील झाल्याशिवाय राहणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी देखील या योजनेचा चांगल्याप्रकारे उपयोग करता येऊ शकेल.

सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम विकास अभियान योजनेंतर्गत "एक व्यक्ती एक झाड" ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाने मनोदय व्यक्त केला आहे. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या निमित्ताने या विषयावर ऊहापोह करता येऊ शकेल. परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज जेवढे बोडके डोंगर दिसून येत आहेत ते बोडके डोंगर या योजनेच्या माध्यमातून हिरवेगार करता येऊ शकतील. हे चित्र बदलावयाचे असेल तर या योजनेचा उत्तम प्रकारे राज्य शासनाला उपयोग करता येऊ शकतो.

सभापती महोदय, 1972 च्या भीषण दुष्काळानंतर महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेद्वारे कोट्यवधी जनतेला जीवदान मिळाले, त्यांच्या हाताला काम दिले गेले. आजही हे काम राज्य शासन निश्चितपणे करू शकते.

नंतर आर.1....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

R-1

PFK/ KGS/ KTG/

पूर्वी श्री. भोगले.....

12:25

प्रा. सुरेश नवले

राज्यातील सुशिक्षित बेकारांना सुध्दा त्यांच्या शिक्षण आणि कौशल्यानुसार या योजनेचा फायदा कसा करून देता येईल याचा विचार शासनाने करावा, अशी माझी सूचना आहे. कारण या योजनेसाठी व्यवसाय कराच्या माध्यमातून आपण जो पैसा जमा करित होतो तो आता एकत्रित निधीत जमा केला जातो. त्यातून गेल्या पाच वर्षात या निधीच्या माध्यमातून एकूण किती रक्कम जमा झाली व त्यापैकी किती खर्च झाला हे राज्यातील जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावे अशी पुन्हा विनंती करतो आणि या चांगल्या योजनेचे मातेरे न करता ती अधिक सक्षमपणे पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत अशी आग्रहाची विनंती करतो आणि माझे भाषण संपवितो.

.....2.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. विनोद तावडे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. एस.क्यू जमा यांनी रोजगार हमी योजनेसारख्या महत्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा उपस्थित केली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो आणि थोड्याच वेळात दोन-चार मुद्दे आग्रहाने मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

महोदय, या सभागृहाचे माजी सभापती व स्व. वि.स.पागे यांनी या राज्यात रोजगार हमी योजनेसारखी महत्वपूर्ण योजना आणली त्याबद्दल त्यांचे मी नक्कीच कौतूक करतो. पण मुंबई विद्यापीठात भरविण्यात आलेल्या एका परिषदेसाठी मी गेलो असता त्या परिषदेत अशी माहिती दिली होती की, प्राचीन भारतामध्ये सुद्धा दुष्काळी भागात लोकांना त्या काळातील प्रशासनाकडून रोजगार पुरविला जात होता. त्या परिषदेत चाणक्यापासून शिवाजी महाराजांच्या काळापर्यंतची माहिती दिली होती. अशा वेळी पायाभूत सुविधांची कामे शासनाने केली पाहिजेत, हे प्राचीन युगापासून चालत आलेले आहे आणि तेच स्व. पागे साहेबांनी आपल्या राज्यात आवर्जून केले त्यातूनच या रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. याच योजनेच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने देखील नरेगा या नावाने जी योजना आणली त्या योजनेची आपल्या राज्यातील स्थिती पाहता सन 2002-03 मध्ये एकूण मनुष्यदिन निर्मिती 15.05 कोटी एवढी होती, सन 2003-04 मध्ये 18.05 कोटी, सन 2004-05 मध्ये 22.02 कोटी एवढी मनुष्यदिन निर्मिती होती. त्यानंतर सन 2005-06 या वर्षात हे प्रमाण 16.09 कोटीवर आले. नरेगा योजना सुरु झाल्यानंतर मात्र सन 2006-07 या वर्षात ही आकडेवारी एकदम 1.06 कोटीवर आली, सन 2007-08 मध्ये 1.09 कोटी, सन 2008-09 मध्ये 1.19 कोटी आणि जानेवारी, 2010 पर्यंत 2.39 कोटी एवढ्यापर्यंतच आपली मनुष्यदिन निर्मिती सीमित राहिली आहे. केंद्रशासनाने ही योजना सुरु केल्यानंतर त्याचा गवगवा मात्र भरपूर झाला, योजनेचे कौतूक आणि चर्चाही पुरेशा प्रमाणात करण्यात आली. तत्कालीन वित्त मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी आपल्या मूळ रोजगार हमी योजनेसाठी व्यवसाय कराच्या माध्यमातून जमा होत असलेला पैसा इतरत्र वळविण्यासाठी विधेयक आणून सभागृहाची मान्यता घेतली. तसेच या योजनेचा राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला फायदा झाला की नुकसान हे केंद्र शासनाला कळविले पाहिजे, असे असताना ते मात्र केले जात नाही. मघाशी सन्माननीय सदस्या श्रीमती शोभा फडणवीस यांनी आग्रहाने जो मुद्दा उपस्थित केला त्यावर विचार होणे अपेक्षित आहे. रोजगार

श्री. विनोद तावडे

हमी योजनेवरील लोकांचा विश्वास आज उडत चालला आहे. त्याचे कारण 15 दिवसांनी मजुरांचे पगार व्हायला पाहिजे पण सहा सहा महिने हे पगार होत नाहीत. अशा प्रकारे रोजगार हमीवर येणाऱ्या मजुरांना एक प्रकारे डिस्क्रेज करण्याचे, कामावर येण्यापासून परावृत्त करण्याचेच काम होत असल्याचे दिसून येते. तसेच या नवीन योजनेच्या माध्यमातून 80 टक्के जलसंधारणाची कामे झाली पाहिजेत असे असताना तेही होत नाहीत. अशा अनेक गोष्टी शासनाने तपासल्या पाहिजेत व त्यासाठी त्या त्या विभागात नवीन रचना करण्याची गरज आहे. अनेक सन्माननीय सदस्यांनी सभागृहात आंध्र प्रदेशमध्ये सुरु असलेल्या रोजगार हमी योजनेचा उल्लेख केला. ज्याप्रमाणे आम्ही नेहमी माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातील कामाचे कौतुक करतो त्याप्रमाणे आंध्र प्रदेशात सुध्दा काँग्रेस पक्षाचेच सरकार आहे. या राज्यात माननीय श्री. रेड्डी यांच्या सरकारने नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अनेक सुधारणा केल्या आहेत.

यानंतर श्री. जुन्नरे

तालिका सभापती (श्री. मोहन जोशी) : या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठीची वेळ 12.30 वाजेपर्यंत होती. या प्रस्तावासाठी अजून 10 मिनिटांची वेळ वाढवून देण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित चर्चा व त्यावर मंत्री महोदयांचे उत्तर नंतर घेण्यात येईल.

श्री. विनोद तावडे : आंध्र प्रदेशमध्ये रोहयोवर काम करणा-या मजुराला तत्काळ मजुरी मिळण्याच्या संदर्भात रचना करण्यात आलेली असून यासंदर्भातील माहिती आपल्याला असल्यामुळे या रचनेच्या संदर्भात मी जास्त काही बोलणार नाही.

सभापती महोदय, आपल्या रोहयोमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो याची चर्चा सगळीकडे होत असते. आंध्र प्रदेशच्या रोहयोच्या रचनेमुळे भ्रष्टाचाराला अटकाव करता येईल अशी परिस्थिती आहे. ज्यावेळी माफियाराजच्या विरुद्ध अभियानासाठी मी राज्यभर फिरत होतो तेव्हा एकदा जव्हार आणि मोखाडा भागात गेलो होतो. त्या ठिकाणी काम करणारे एनजीओ आणि इतर मान्यवरांना मी भेटलो होतो. आमच्या जेव्हा गप्पा सुरु होत्या त्यावेळेस मी माझ्या लॅपटॉप वरून नरेगाच्या संकेत स्थळावर गेलो व त्या ठिकाणच्या किती मजुरांचे पेमेंट झालेले आहे याची माहिती घेतली तेव्हा आम्हाला एक एक धक्काच बसत गेला. त्या ठिकाणच्या एनजीओचे जे कार्यकर्ते होते ते ग्रॅज्यूएट होते व ते एनजीओचे सुध्दा काम करीत होते. या एनजीओच्या नावाने वेबसाईटवर रोहयोचे पेमेंट झाल्याचे मला आढळून आले होते. यासंदर्भातील सर्व माहिती वेबसाईटवरून वाचावयास लागलो तेव्हा संकेत स्थळावर पेमेंट झाल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे परंतु प्रत्यक्षात मजुरांना मजुरी मिळालेलीच नव्हती. श्री. भास्कर जोशी-जॉब कार्ड नंबर-एमएच 02007 यांना 23415 रुपये पेमेंट केल्याचे नरेगा डॉट,एमआयसी डॉट इनमध्ये अमाऊंट दाखवली होती परंतु प्रत्यक्षात श्री. भास्कर जोशीला मजुरी मिळाली नसल्यामुळे त्यांचे यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र मी लिहून घेतलेले आहे. वेबसाईटवर श्रीमती जयू दिघे या प्राध्यापिकेच्या नावाने 14,832 रुपयांचे पेमेंट दिल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात मी संबंधित प्राध्यापिकांना भेटलो व त्यांचेही प्रतिज्ञापत्र घेतले. अशा प्रकारे मी जवळ जवळ 450 प्रतिज्ञापत्र तीन दिवस राहून मिळवलेली आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात वेबसाईटचे नाव, जॉबकार्ड नंबर, पेमेंट किती मिळाले याचा सर्व उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

श्री. विनोद तावडे...

सभापती महोदय, काल आम्ही सभागृहात माफिया शब्द वापरला तेव्हा माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील एकदम अस्वस्थ झाले होते. जव्हार-मोखाडा भागातील रोहयोच्या अधिका-यांशी या विषयावर बोललो असता त्यांनी सांगितले की, "साहेब, आम्हाला सर्व वरपर्यंत पोहचावे लागते." खरे म्हणजे क्रिमिनल एकत्र येऊन सिंडीकेट होत असतात. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण बोलत असतात की, बिल्डर, राज्यकर्ते, नोकरशहा हे एकत्र झालेले आहे. परंतु रोहयोमध्ये ठेकेदार, नोकरशहा आणि राज्यकर्ते मिळून सिंडीकेट झालेले आहेत. ही 450 प्रतिज्ञापत्रे फक्त एकाच तालुक्यातील आहेत. मी तुम्हाला असे काही जिल्हे दाखवतो की, त्या ठिकाणच्या रोहयोमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा होत असतो. रोहयाचा खालचा अधिकारी सांगतो की, आम्हाला मंत्रालयापर्यंत हे पैसे पोहचावे लागतात. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची तुम्ही चौकशी करणार आहात की, नाही ? आदिवासी भागातील रोहयोच्या संदर्भात माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात एक वाक्य आहे.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

श्री.विनोद तावडे

की," आम्ही आता रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुरांना 127 रुपये दर देणार आहोत" परंतु हा दर आपण कसे काय देऊ शकतो ? 1 जानेवारीपासून हा दर देण्यात येईल, असे केन्द्र सरकारने जाहीर केलेले आहे. त्यांनी जे घोषित केलेले आहे, ते राज्य सरकार आपल्या नावाने का जाहीर करते, कशासाठी जाहीर करते ? 1 जानेवारी 2011 पासून जर केन्द्र सरकार 127 रुपये दर देणार असेल आणि राज्य सरकार मात्र 14 फेब्रुवारी 2011 पासून हा दर देण्यात येईल, असे सांगत आहे तेव्हा मधल्या 44 दिवसांचे काय करण्यात येणार आहे, हे पैसे कोणाच्या खिशात जाणार आहेत, माननीय राज्यपालांच्या तोंडून आपण असत्य का वदवून घेत आहात ? तुम्ही तर असत्य बोलताच परंतु माननीय राज्यपालांनासुद्धा असत्य बोलावयास लावत आहात.

सभापती महोदय, आपल्या खात्यात एखादे चुकीचे काम सुरु असेल आणि ते काम जर मंत्री थांबवत नसेल तर त्या मंत्र्यांविषयी बाकीच्यांना कितीही आदर असला तरी मला असे वाटते की, आपल्या खात्यातून काही चुकीचे घडत असेल तर ते चुकीचे काम माननीय मंत्र्यांनी थांबवले पाहिजे. वर पर्यंत पैसे द्यावे लागतात असे अधिकारी तोंड वर करून सांगतात तेव्हा या घोटाळ्याची आपण चौकशी करणार आहात काय ? माझ्याकडे जेवढी प्रतिज्ञा पत्रे आहेत ती सगळी मी माननीय मंत्र्यांकडे देतो. मूळात या योजनेसाठी पैसे कमी येतात आणि जे काही पैसे येतात, ते प्रत्यक्ष लाभधारकां पर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्या ठिकाणी कोटयावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असतो. वेब साईटवर मला ही माहिती दिसली, म्हणून या बाबी मला समजल्या. मी वेब साईटवर सर्फिंग करून त्यामध्ये कोणाची नावे होती हे शोधून काढले. त्यातील दोन चार व्यक्ती माझ्या समोरच बसलेल्या होत्या. म्हणून मी त्यांना विचारले, तेव्हा हे पैसे मिळाले नाहीत असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मी बाकीच्या दोन सभा रद्द करून पाडया पाडयावर जाऊन या संबंधीची अधिक खोलात जाऊन माहिती घेतली. एका पाडयावर गेल्यानंतर दुस-या पाडयातील व्यक्ती येऊन मला सांगू लागली की, आमच्याही पाडयावर आपण येऊन माहिती घ्यावी. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर सन्माननीय मंत्री श्री नितीन राऊत आणि मी अशा दोघांची एकत्रितपणे संपूर्ण राज्यभर यात्रा काढावी, असे मला वाटते. या माफियाकडून हजारो कोटी रुपये कसे गिळंकृत केले जातात, हे या चर्चेतून बाहेर पडेल. या प्रकरणात मी ठोस पुरावे देण्यास तयार आहे. तेव्हा या प्रकरणाची

..2..

श्री.विनोद तावडे

सीआयडी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे काय ? जर माननीय मंत्री या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करणार असतील तर ते स्वच्छ आहेत असे समजू अन्यथा सन्माननीय सदस्य श्री. अरुण गुजराथी यांनी सांगितल्याप्रमाणे रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही असेच होईल. सन्माननीय मंत्री डॉ.नितीन राऊत हे किती स्वच्छ आहेत, हे त्यांच्या उत्तरावरून दिसून येईल एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवितो.

..3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.मनिष जैन (जळगाव स्थानिक प्राधिकारी संस्था) : सन्माननीय सदस्य श्री एस.क्यु जमा यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलण्याकरिता मी उभा आहे.

सभापती महोदय, राज्यातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे तसेच त्यांच्या मजुरीमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन दिल्या बद्दल मी सर्व प्रथम माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री एस.क्यु जमा आणि श्री अरुण गुजराथी यांनी या प्रस्तावावर आपले विचार सविस्तर मांडलेले आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय सदस्य श्री. विनोद तावडे यांनी मजुरांबद्दल आणि त्या योजनेतील भ्रष्टाचाराबद्दल आपले म्हणणे मांडलेले असल्यामुळे मी यावर जास्त काही बोलणार नाही.

सभापती महोदय, या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मला दोन तीन मुद्दे या ठिकाणी मांडावयाचे आहेत. शेतक-यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी जर फलोत्पादन, भू सुधारणेची कामे रोजगार हमी योजनेतून घेतली गेली तर अधिक बरे होईल. आज केन्द्र सरकार किमान वेतन कायद्याप्रमाणे या मजुरांना 230 रुपये मजुरी देत आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. अरुण गुजराथी यांनी सांगितले की, शेतावर काम केले तर मजुरांना 400 ते 500 रुपये मजुरी मिळते. अशा प्रकारे एका कुटुंबातील दोन व्यक्तींनी शेतातील कापूस वेचण्याचे काम केले तर त्यांना एक हजार रुपये मिळतात. 127 रुपये हा दर फारच कमी असल्यामुळे, हा दर वाढवून देण्याच्या दृष्टीने विचार करावा, असे मला सांगावयाचे आहे.

सभापती महोदय, यानंतर मला दुसरा मुद्दा असा सांगावयाचा आहे की, या गरीब शेतक-याला डायरेक्टली पैसे मिळाले पाहिजेत. जो शेतकरी आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती घेऊन स्वतःच्या शेतात काम करील, त्याला डायरेक्ट पैसे दिले पाहिजे. या योजनेच्या अंतर्गत रोजगार पुरविण्याचे काम फक्त ग्रामीण भागातच केले जाते. परंतु शहरी भागात सुध्दा सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. शहरी भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना सामाजिक संरक्षण देणे तसेच शहरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना तात्पुरत्या नोक-या मिळवून देण्याची गरज आहे. शहरात सायकल, रिक्शा चालविणारे, हातठेला चालविणारे, हमाल,मजूर

..4..

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

T 4

VTG/ KGS/ KTG/

प्रथम श्री.जुन्नर

12:35

श्री.मनिष जैन..

गवंडी काम करणारे, रंग काम करणारे तसेच घर काम करणाऱ्या मोलकरणी आहेत. या सर्वांचा या योजनेत समावेश करून घेतला तर शहरी भागातील बेरोजगारांचा प्रश्न काही प्रमाणात दूर होऊ शकेल. शहरामध्ये लहान सहान काम करणाऱ्या मजुरांची किती कुटुंबे आहेत, याचा सामाजिक व आर्थिक अभ्यास करून त्यांचा समावेश या योजनेत करून घ्यावा, अशी माझी विनंती आहे. त्यासाठी शहरी भागात सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाची स्थापना करण्याची गरज आहे, असे माझे मत आहे.

यानंतर श्री. सरफरे..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

U 1

DGS/ KTG/ KGS/

12:40

श्री. मनिष जैन...

सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपणास धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे माननीय सदस्य श्री. जमा साहेब, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उपस्थित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवितो.

तालिका सभापती : आता सभागृहाची बैठक स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक दुपारी 12.45 वाजता सुरु होईल.

(12.40 ते 12.45 बैठक स्थगित झाली.)

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापतीस्थानी - माननीय सभापती**माननीय मुख्यमंत्र्यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा**

सभापती : महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री.पृथ्वीराज चव्हाणसाहेब यांचा आज 64 वा वाढदिवस आहे. याठिकाणी सभापती म्हणून आपल्या सदना मार्फत, सर्व सन्माननीय सदस्यां मार्फत मी आपल्या सर्वांच्या वतीने एक अभिनंदनाचा ठराव करुन त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्याचे ठरविलेले आहे. त्यांच्याकडे एक कर्तव्यसंपन्न व्यक्ती या दृष्टीकोनातून पाहिले तर त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर आतापर्यंत अत्यंत चांगल्या पध्दतीचे काम केलेले आहे. माननीय मुख्यमंत्री हे अत्यंत कुशाग्र बुध्दीचे, अत्यंत अभ्यासू आहेत. तसेच सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न समजावून घेऊन ते सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे असे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे.त्यांना यापुढच्या काळामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सेवा करण्यासाठी परमेश्वराने ताकद द्यावी या दृष्टीकोनातून मी याठिकाणी आपल्या सर्वांच्या मार्फत ठराव मांडलेला आहे. त्याचे आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केलेले आहे. मी सदरहू ठराव संमत करतो.

श्री.दिवाकर रावते (खाली बसून) : विरोधी पक्षाच्या वतीने देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा दिल्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो.

सभापती : आपल्या सर्वांच्यावतीने माननीय मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत.

. . . . व्ही-2

पु.शी./मु.शी.: नियम 289 अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सूचनेसंबंधी

सभापती : आज माझ्याकडे नियम 289 अन्वये प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्यासंबंधी सन्माननीय सदस्य सर्वश्री. पांडुरंग फुंडकर, दिवाकर रावते, विनोद तावडे, रामदास कदम, डॉ. दीपक सावंत, डॉ.नीलम गोन्हे वि.प.स.यांनी "आदर्श गृहनिर्माण संस्थेची चौकशी व्दिसदस्यीय समितीद्वारा करण्याची माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करुनही समितीची नेमणूक विलंबाने करण्यात येणे, चौकशी देखील संथ गतीने सुरु असणे, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेद्वारे होणारी चौकशी दीड महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक असतानाही या प्रकरणी राज्याकडून केंद्र शासनाकडे कोणताही पाठपुरावा करण्यात न येणे, सदर घोटाळ्यामध्ये 13 जणांचा समावेश असून 14 वे आरोपी म्हणून श्री.जयराज फाटक यांचे नाव समाविष्ट होणे,सदर प्रकरणात महाराष्ट्राच्या तत्कालीन दोन मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होणे तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण या प्रकरणी 13 वे आरोपी असतानाही त्यांच्या संदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांनी "सरकार तुमच्या पाठीशी आहे" असे वक्तव्य करणे, या विषयाच्या संदर्भात जी प्रस्तावाची सूचना दिली आहे.प्रत्यक्षात शासनामार्फत व्दि-न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच मला असे वाटते की, हा संपूर्ण प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, हा संपूर्ण प्रश्न न्यायप्रविष्ट नाही.

(काही सन्माननीय सदस्य एकदम बोलतात.)

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट नाही.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आपण शब्द बदलून वापरावा एवढीच आमची विनंती आहे. कारण तो शब्द रेकॉर्डवर रहाणे चुकीचे ठरेल.

यानंतर कु.थोरात

सभापती : ठीक आहे. परंतु हे संपूर्ण प्रकरण शासनाने निवृत्त द्वी न्यायाधीशांकडे चौकशी करिता दिलेला आहे. आजच्या कामकाज पत्रिकेवर या अनुषंगाने कोणतीही बाब नसल्यामुळे मी या प्रस्तावाच्या सूचनेला सदनमध्ये मान्यता देऊ शकत नाही. पण सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते आणि सन्माननीय गट नेते यांना यावर दोन-दोन मिनिटे बोलण्याची परवानगी देतो.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचे हे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले त्या वेळी महाराष्ट्रालाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला धक्का बसला. ही गृहनिर्माण संस्था स्थापन करताना ज्या अनियमितता झाल्या आणि त्या अनियमिततेतून हे प्रकरण बाहेर आले, या प्रकरणाच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले होते की, या प्रकरणामध्ये जे कोणी दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी द्वी सदस्यीय समिती घोषित करण्यात आली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे प्रकरण सभागृहासमोर आले तेव्हा पासून आज पर्यंत तीन महिन्यांचा कालावधी निघून गेला आहे. या कालखंडामध्ये या द्वी सदस्यीय समितीचे कामकाज किती झाले? कारण वर्तमानपत्रात याबाबतीत वेगवेगळ्या बातम्या छापून येत आहेत. या समितीकडे स्टाफ नाही, पगार झालेले नाहीत, कार्यालय नाही म्हणून या समितीचे कामकाज धिम्या गतीने चालू आहे. या प्रकरणामध्ये जे अधिकारी दोषी आढळून आले आहेत त्यासंबंधातील सीबीआयचे आरोपपत्र माझ्या जवळ आहे.

सभापती : मी आपल्याला या प्रस्तावावरील चर्चेला परवानगी दिलेली नाही. प्रस्ताव कसा योग्य आहे याबद्दल फक्त दोन मिनिटात आपण बोलावे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मी थोडक्यात बोलतो.

सभापती : थोडक्यात नाही तर फक्त दोन मिनिटात आपण आपले म्हणणे मांडावे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सीबीआयने 13 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले होते त्यामध्ये काल 14 वे आरोपी श्री. जयराम फाटक दाखल झाले आहेत. 20 अधिकाऱ्यांपैकी फक्त 3 अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. बाकीचे अधिकारी मोकळी सुटलेले आहेत. ज्यांच्या नावावर 18-18 फ्लॅट आहेत असे श्री. खोब्रागडे सारखे अनेक अधिकारी मोकळे आहेत. महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, एका बाजूला सीबीआयची चौकशी सुरु आहे आणि दुसऱ्या बाजूला द्वी सदस्यीय समितीची चौकशी सुरु आहे. या राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नांदेडमध्ये जाऊन श्री. अशोक

..2..

SMT/ KGS/ KTG/

श्री. पांडुरंग फुंडकर.....

चव्हाण यांना तुमचे वार्डट दिवस जातील, तुम्हाला चांगले दिवस येतील, काँग्रेस पक्ष तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करुन या चौकशीवर एक प्रकारे अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब झालेली आहे म्हणून या सर्व प्रकरणावर ताबडतोबीने सभागृहात चर्चा करुन या प्रकरणाची स्पष्टता या राज्यातील सर्व जनतेला समजली पाहिजे म्हणून सभागृहाचे कामकाज थांबवून आपण या प्रस्तावावरील चर्चेला ताबडतोब परवानगी द्यावी, अशी विनंती मी आपल्याला करतो.

श्री. सय्यद जमा : सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. जब प्रश्नकाल शुरू होता है तो प्रतिदिन नियम 289 के अनुसार प्रस्ताव पेश किया जाता है. माननीय विरोधी पक्ष के नेता को नियम 289 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का अधिकार है और उस पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन इसमें प्रश्नकाल का बहुत सारा समय चला जाता है. पार्लमेंट में प्रश्नकाल डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा निर्णय लिया गया है. प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों को बहुत सारे मुद्दे उठाने और अपनी बात कहने का मौका मिलता है. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बी.ए.सी. में इस मामले को लेकर प्रश्नकाल में कोई डिस्टर्बेंस न हो, ऐसी कोई व्यवस्था करें.

श्री. हुसेन दलवाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. ज़मा यांनी मांडलेल्या मुद्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पार्लमेंटमध्ये शून्य तास प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर असतो, तशी काही तरी व्यवस्था आपल्याकडे करण्यात यावी. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील सगळ्या प्रश्नांवर या ठिकाणी चर्चा होते. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी नियम 289 अन्वये जो प्रस्ताव उपस्थित केलेला आहे त्याला आमचा विरोध नाही.

यानंतर श्री. बरवड....

सभापती : काल सन्माननीय सदस्य श्री. रामनाथ मोते यांनी नियम 289 अन्वये दिलेली प्रस्तावाची सूचना याच पध्दतीची होती. प्रश्नोत्तराचा तास हा अत्यंत महत्वाचा आहे आणि तो तास कोणत्याही परिस्थितीत वेळेवर झाला पाहिजे या अनुषंगाने त्यांनी नियम 289 अन्वये प्रस्तावाची सूचना दिली होती. आताच सन्माननीय सदस्य श्री. सय्यद जमा तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. हुसेन दलवाई यांनी जे सांगितले त्या पध्दतीने या अनुषंगाने दरम्यानच्या काळात मी नियम समितीची बैठक घेण्याचे ठरविले आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण झाला पाहिजे. प्रश्नोत्तराचा तास अत्यंत महत्वाचा आहे. त्याच बरोबर नियम 289 मध्ये जी तरतूद आहे त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्यांना योग्य ती संधीही दिली पाहिजे या दृष्टीने कसा मार्ग काढता येईल ते मी जरूर पाहीन.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सय्यद जमा ज्यावेळी बोलण्यासाठी उभे राहिले त्यावेळी ते माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी माजी दोन मुख्यमंत्र्यांची नावे का घेतली नाहीत, त्यांची काही चूक झाली का, असे काही तरी सांगण्यासाठी उभे राहिले की काय, असे मला वाटले. सभापती महोदय, आपण आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी या महाराष्ट्राची सेवा करावी आणि भविष्यात त्यांना या सेवेत सुयश मिळो अशाही शुभेच्छा दिल्या. आपण सुंदर सुरुवात केली. आपण महाराष्ट्रातील जुन्याजाणत्यांपैकी आहात म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये आपलीही कीर्ती अशीच आहे की, आपण जर पीठासीन अधिकारीपदी असाल तर जनतेच्या कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत अन्याय होणार नाही. अशा प्रकारची जी भावना सगळीकडे आहे ती आपण जपावी अशी माझी नम्र विनंती आहे.

सभापती महोदय, हा प्रस्ताव शासनाच्या विरोधातील वगैरे नाही. आदर्शच्या भ्रष्टाचारामध्ये रोज एक एक अधिकारी येत आहेत, समाविष्ट होत आहेत. शासनाला म्हणावे तसे बळ मिळत नाही काय ? मग यावर चर्चा झाली पाहिजे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सतत अशी चर्चा आहे की, जे भ्रष्टाचारी आहेत ते मोकट सुटलेले आहेत. त्यामध्ये यांचा कोणाचाही संबंध नाही. उलट या प्रस्तावावर चर्चा झाली तर शासनाचे हात बळकट करणारीच चर्चा होणार आहे. म्हणून माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की, नियम 289 चा विशिष्ट विषय नसतोच पण महाराष्ट्रातील

RDB/ KGS/ D/ KTG/ MMP

श्री. दिवाकर रावते

तातडीचा अतिशय गंभीर विषय असेल तर तो मांडण्याकरिता या सदनतील सदस्यांचा जो अधिकार आहे त्या माध्यमातून हा विषय आलेला आहे. आपण सांगितल्याप्रमाणे जरी हा विषय आजच्या दिवसाच्या कामकाज पत्रिकेवर नसला तरी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धी नुसार महाराष्ट्रातील या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, या भ्रष्टाचाराची अगदी झोपडीपर्यंत चाललेली चर्चा लक्षात घेऊन या प्रस्तावावरील चर्चेला परवानगी द्यावी. मला खात्री आहे की, आमचे सहकारी सदस्य सुध्दा याच्या विरोधात नसतील. श्री. अशोक चव्हाण काल बोलताना आरोप करणारे बोलले. एवढेसे काही केले तर त्यांना लगेच आरोपी केले परंतु भ्रष्टाचाराने माखलेले एवढे जे अधिकारी आहेत त्यांच्या बाबतीत काहीही झाले नाही. एका माणसाला, मला एक मुलगा आहे तरी माझे 8 फ्लॅट आहेत, कोणत्या तरी अधिकाऱ्याचे 18 फ्लॅट आहेत असे या ठिकाणी सांगण्यात आले. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असे जाहीर केले की, मी नोटिसेस दिलेल्या आहेत पण आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्याला नोटीस गेलेली नाही. मी या सदनत मागणी केली होती की, त्यांना ताबडतोब निलंबित करा किंवा रजेवर पाठवा, तरच कारवाई होईल. परंतु त्या बाबतीतही काही झालेले नाही. अधिकाऱ्यांना या शासनाकडून जर कोणताही जाब विचारला नाही तर वातावरण असे आहे की, हा भ्रष्टाचार लपविण्याकरिता, पचविण्याकरिता शासन मदत करीत आहे का ? म्हणून या संदर्भात चर्चा होऊन शासनाची स्पष्ट भूमिका समोर आली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. म्हणून मी आपल्याला अत्यंत नम्रपणे सांगू इच्छितो की, हा ज्वलंत विषय आहे, लोकांच्या मनातील विषय आहे आणि लोकांच्या भावना व्यक्त करण्याचे हे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे आपण या प्रस्तावावरील चर्चेला मान्यता द्यावी आणि या संदर्भात चर्चा करावी. फार मोठ्या चर्चेची आमची अपेक्षा नाही.

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी आदर्श प्रकरणाच्या बाबतीत या ठिकाणी चर्चा घडवून आणावी असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. एक गोष्ट मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, की आदर्शचा विषय काही प्रमाणात महसूल विभागाशी सुध्दा निगडित असल्यामुळे मला काही

...3...

RDB/ KGS/ D/ KTG/ MMP

श्री. बाळासाहेब थोरात

असल्यामुळे मला काही गोष्टी माहित आहेत. यामध्ये सीबीआयची एक चौकशी चालू आहे. दुसरी बाब अशी की, काही सदस्य हायकोर्टात गेलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यावरचे हिअरींग सुध्दा चालू आहे. तिसरी बाब अशी की, आपण यासंदर्भात जे कमिशन नेमले आहे त्या कमिशनचे हिअरींग सुध्दा आता चालू होतील. त्यांचे कामकाज चालू होईल. ज्यावेळी या विषयाच्या संदर्भात या तीनही गोष्टी चालू आहेत त्यावेळी जर आपण सभागृहामध्ये चर्चा केली आणि काही मुद्दे उपस्थित झाले तर शासन म्हणून आम्ही काही बाबी मांडण्याचा प्रयत्न केला तर या ज्या निरनिराळ्या प्रोसिडींग्ज चालू आहेत त्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामध्ये हस्तक्षेप होण्यासारखे ते होऊ शकते. म्हणून या बाबतीत कोणतीही चर्चा सभागृहात होऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे.

यानंतर श्री. खंदारे

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, या प्रकरणाच्या चौकशीला कोणतीही बाधा येईल अशाप्रकारच्या चर्चेची आम्ही मागणी करित नाही. याप्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. ज्या पध्दतीने हे सर्व चालले आहे ते योग्य नाही. मंत्री महोदयांनी सांगितलेल्या चौकशीच्या प्रक्रियेला बाधा येईल असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही करित नाही.

सभापती : आज देण्यात आलेल्या नियम 289 अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सूचनेबाबत सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपले मत मांडले आहे, सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी आपले मत मांडलेले आहे. त्यानंतर सन्माननीय महसूल मंत्र्यांनी आपले मत मांडलेले आहे. मी या नियम 289 अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सूचनेबाबत माझा निर्णय देत आहे. आज नियम 289 अन्वये जी प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली आहे त्याबाबत मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे त्यातील विषय आजच्या दिवसाच्या कामकाजपत्रिकेत समाविष्ट नसल्यामुळे मी या सूचनेला अनुमती नाकारित आहे.

पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे

(विरोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य उभे राहून बोलत असतात.)

गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आल्याबाबत

(१) * १३५१९ श्री.केशवराव मानकर , श्री.नितीन गडकरी , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्रीमती शोभाताई फडणवीस , श्री.नागो गाणार : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान राज्यातील आणेवारीत नागपूर विभागातील १४११ गावे दुष्काळग्रस्त असून खरीप पिकांसाठी तब्बल १४ हजार ३१७ गावांची आणेवारी ५० पैशांच्या वर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आणेवारीत गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आले आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात दरवर्षी सर्वात जास्त दुष्काळ पडणाऱ्या या तिन्ही जिल्ह्यांना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून वगळण्यासाठी आणेवारीची कोणती पध्दत शासनाद्वारे अवलंबण्यात आली आहे, सर्वेक्षणाचे वेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना याची माहिती पुरविण्यात आली होती काय,

(४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?

डॉ.पतंगराव कदम : (१) नागपूर विभागातील खरीप हंगामाच्या अंतिम पैसेवारी दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार एकूण ७८११ गावांपैकी १५११ गावातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे.

(२) होय.

(३) शासनाच्या प्रचलित पध्दतीनुसार सर्वेक्षण करून पैसेवारी निर्धारित करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(उपप्रश्न विचारण्यात आले नाहीत)

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, या प्रकरणाच्या चौकशीला बाधा येईल असे आमच्याकडून वक्तव्य होणार नाही.

सभापती : मी नियम 289 अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सूचनेला अनुमती नाकारलेली आहे.

(विरोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये जमून माननीय सभापतींशी बोलण्याचा प्रयत्न करित असतात.)

3....

मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, आपण जी नियम 289 अन्वये प्रस्तावाची सूचना दिली होती त्याबाबत सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री.पांडुरंग फुंडकर आणि सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांना थोडक्यात म्हणणे मांडण्याची मी संधी दिलेली आहे. मी मी ही सूचना नाकारली असल्याचे सांगितलेले आहे. त्यानंतर मी प्रश्नोत्तराचा तास सुरु केलेला आहे. त्यामुळे कृपया सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या जागेवर जाऊन बसावे.

4.....

राज्यातील आश्रमशाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी
नॅपकिन्स खरेदी केले जात असल्याबाबत

(२) * १३७५७ डॉ.दिपक सावंत : सन्माननीय आदिवासी विकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) राज्यातील आश्रमशाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स खरेदी केले जातात, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, सदरहू सॅनिटरी नॅपकिन्स किती आश्रमशाळेत पुरवठा करण्यात आले आहेत,
- (३) अद्यापपर्यंत कोणत्याही आश्रमशाळेत हा पुरवठा झाला नसल्यास, त्यांची कारणे काय आहेत ?

श्री.बबनराव पाचपुते : (१) होय.

- (२) आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील सर्व ५५१ शासकीय आश्रमशाळांना सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे.
- (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

(उपप्रश्न विचारण्यात आले नाहीत)

5.....

NTK/ KTG/ D/ KGS/ MMP/

(विरोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये घोषणा देत असतात.)

राज्यात आकारास येत असलेल्या काही मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत

(३) * १४०६२ श्री. एस. क्यू. जमा , श्री.विजय सावंत , श्री.हुसेन दलवाई : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आकारास येत असलेल्या सात मोठ्या प्रकल्पांमुळे (गोसीखूर्द, मिहान, एनटीपीसी मौदा, निम्न वर्धा योजना, बिरसी विमानतळ आदानी ऊर्जा आणि शिर्डी विमानतळ) विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्यास, राष्ट्रीय पुनर्वसन कायदा, २००७ प्रमाणे सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश दिनांक २३ डिसेंबर, २०१० च्या आसपास दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आजपर्यंत किती प्रकल्पांकडून सदर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत, असल्यास त्यावर शासनाने काय कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त झाले नसल्यास संबंधित प्रकल्पांचे काम थांबविण्यासाठी शासनाने काय कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.प्रकाश सोळंके, डॉ.पतंगराव कदम यांच्याकरिता: (१) नाही.

(२), (३), (४) आजपर्यंत शासनाकडे ६ प्रकल्पांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाले आहेत. सदर सर्व प्रस्तावांवर शासन स्तरावर छाननीचे काम सुरु आहे.

श्री एस. क्यू. जमा : सभापति महोदय, में बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रकल्पग्रस्त किसान हैं, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं हुई है. मेरा कहना है कि गोसीखूर्द, मिहान, एनटीपीसी मौदा आदि जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जमीन अधिगृहित की गयी है. उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में, उनका पुनर्वसन करने के बारे में तथा उनको रोजगार देने के बारे में सरकार ने क्या योजना बनायी है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है ? कृपया इसकी जानकारी मंत्री महोदय दें.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, राज्यातील सात मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. आदानी ऊर्जा प्रकल्प, ता.तिरोडा, जिल्हा गोंदिया, एनटीपीसी मौदा, गोसीखूर्द प्रकल्प, नागपूर व भंडारा, बिरसी विमानतळ व कार्गोहब या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झालेले आहेत. परंतु त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर पुनर्वसनाच्या प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देण्यात येईल.

यानंतर श्री.शिगम.....

(विरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन जोरजोराने घोषणा देत असतात.)

श्री. हुसेन दलवाई : सभापती महोदय, खरे तर अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थितच होता कामा नये. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केल्या शिवाय, त्यांचे प्रश्न सोडविल्या शिवाय प्रकल्पाचे काम सुरु करू नये असे शासनाचे धोरण असून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील तसे वारंवार या सभागृहामध्ये सांगितलेले आहे. असे असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात गोंधळ का होतो ? प्रश्नाच्या छापील उत्तरामध्ये असे नमूद केलेले आहे की, "आजपर्यंत शासनाकडे 6 प्रकल्पांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाले आहेत." हे प्रस्ताव विभागाकडून लवकर प्राप्त का झाले नाहीत ? कोकणातील कोयना प्रकल्पाला 60 वर्षे झाली. त्या प्रकल्पाचा चौथा टप्पाही कार्यान्वित झाला तरी अद्याप त्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही.

सभापती : मी सन्माननीय सदस्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपापल्या जागेवर जाऊन बसावे.

(विरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन जोरजोराने घोषणा देत असतात.)

सभापती : सभागृहामध्ये कामकाज चालविण्यासारखी परिस्थिती नसल्यामुळे मी सभागृहाची बैठक 25 मिनिटांकरिता तहकूब करित आहे.

श्री. हुसेन दलवाई : सभागृहाची बैठक सुरु झाल्यानंतर ता.प्र.क्र.14062 पुन्हा चर्चेला घेण्यात येईल काय ?

सभापती : होय.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 1.05 ते 1.30 पर्यन्त स्थगित झाली.)

....नंतर श्री. गिते....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

AA-1

ABG/ D/ MMP/

प्रथम श्री. शिगम

13:30

स्थगितीनंतर

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.मोहन जोशी)

(विरोधी पक्षाचे सदस्य घोषणा देतात)

तालिका सभापती : अशा परिस्थितीत सभागृहाचे कामकाज करणे शक्य नसल्यामुळे सभागृहाची बैठक मी 10 मिनिटांसाठी स्थगित करतो.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 13.30 ते 13.40 वाजेपर्यंत स्थगित झाली.)

यानंतर श्री. भोगले

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

BB.1

SGB/ D/ MMP/

13:40

स्थगितीनंतर

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.मोहन जोशी)

तालिका सभापती : सभागृहाची बैठक 25 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 1.40 ते 2.05 पर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

CC-1

PFK/ D/ MMP/

पूर्वी श्री. भोगले.....

14:05

स्थगिती नंतर

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. मोहन जोशी)

तालिका सभापती : सभागृहाची बैठक मध्यंतरासाठी 25 मिनिटे स्थगित करण्यात येत आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 2.05 ते 2.30 पर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(मध्यंतरानंतर)

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती)

सभापती : सन्माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, गट नेते यांच्याशी नियम 289 च्या प्रस्तावाच्या सूचनेच्या संदर्भात चर्चा झालेली आहे. आजच्या नियम 289 अन्वयेच्या प्रस्तावाच्या सूचनेबाबत मी असा निर्णय दिला होता की, या सूचनेतील विषय आजच्या दिवसाच्या कामकाज पत्रिकेत समाविष्ट नसल्यामुळे मी सदर सूचनेस अनुमती नाकारतो. तरी सुद्धा हा विषय अत्यंत महत्वाचा असल्यामुळे सोमवारी या विषयावर 1 तासाची चर्चा घेण्यात येईल. चर्चेसाठी 45 मिनिटे व उत्तरासाठी 15 मिनिटांचा अवधी देण्यात येईल.

दुसरे असे की, अनेक कारणामुळे प्रश्नोत्तराचा तास वाया जातो, ही पध्दत लोकशाहीच्या दृष्टीने बरोबर नाही. राष्ट्रीय पातळीवर राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या संदर्भात परवा निर्णय झालेला आहे. प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही परिस्थितीत झालाच पाहिजे. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास सुरुवातीला न घेता कामकाजाच्या मध्येच घेतला जाईल. प्रश्नोत्तराच्या तासात 10-15 मिनिटांचा वेळ गेलेला आहे. त्यामुळे राहिलेली पुढील प्रश्नोत्तरे 45 मिनिटात घेतली जातील. प्रश्नोत्तराचा तास रोखून ठेवणे ही पध्दत कधीही योग्य नाही. प्रश्नोत्तराचा तास अशा पध्दतीने वाया जात असेल तर ते बरोबर नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

आजच्या कामकाज पत्रिकेत दाखविल्या प्रमाणे माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, आजच्या कामकाजात ज्या लक्षवेधी सूचना दाखवल्या आहेत त्या कधी घेतल्या जाणार आहेत ?

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, 14 मार्च पासून म्हणजे तीन दिवसापासूनच्या ज्या लक्षवेधी सूचना आहेत त्या स्पेशल सिटींगमध्ये घेतल्या तर बरे होईल.

सभापती : मी लक्षवेधी सूचना किंवा इतर कोणताही कार्यक्रम लॅप्स करीत नाही. सन्माननीय सदस्यांचे प्रश्न, लक्षवेधी सूचना सभागृहामध्ये येण्यासाठी किती कष्ट पडतात याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे लक्षवेधी सूचना लॅप्स होणार नाही. आता प्रश्नोत्तरे घेण्यात येतील व त्यासाठी 45 मिनिटांचा अवधी देण्यात आलेला आहे. मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की, प्रश्नोत्तराचा तास यापुढे कधीही लॅप्स होणार नाही.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आजच्या लक्षवेधी सूचना लॅप्स करता कामा नये. आजच्या लक्षवेधी सूचनांसाठी विशेष बैठक घेण्यात यावी.त्याचबरोबर आजची प्रश्नोत्तरे आजच्या 40 मिनिटांमध्येच घेण्यात यावीत.

सभापती : ठीक आहे. आजच्या लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्यात येतील व त्या नंतर घेण्यात येतील. या नंतर प्रश्नोत्तरे घेण्यात येतील.

श्री.दिवाकर रावते : प्रश्नोत्तरे किती मिनिटे घेण्यात येणार आहेत ?

सभापती : प्रश्नोत्तरासाठी 60 मिनिटांचा वेळ असतो. त्यातील दहा मिनिटे सुरुवातीला गेलेली आहेत त्यामुळे प्रश्नोत्तरासाठी मी 45 मिनिटे देत आहे.

पू.शी.मु.शी : तोंडी उत्तरे (पुढे चालू)

सभापती : मघाशी पहिला प्रश्न पुकारण्यात आला होता .

श्री.केशवराव मानकर :सभापती महोदय, मी प्रश्न विचारण्यासाठी उभा होतो परंतु मला उपप्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली नाही.

सभापती : उप प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उभे राहिला नव्हता.

श्री.केशवराव मानकर : मी प्रश्न क्रमांक देखील पुकारला होता .

सभापती: ठीक आहे. आता आपण तारांकित प्रश्न क्रमांक 13519 चर्चेला घेऊ

गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आल्याबाबत

(१) * १३५१९ श्री.केशवराव मानकर , श्री.नितीन गडकरी , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्रीमती शोभाताई फडणवीस , श्री.नागो गाणार : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान राज्यातील आणेवारीत नागपूर विभागातील १४११ गावे दुष्काळग्रस्त असून खरीप पिकांसाठी तब्बल १४ हजार ३१७ गावांची आणेवारी ५० पैशांच्या वर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आणेवारीत गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आले आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात दरवर्षी सर्वात जास्त दुष्काळ पडणाऱ्या या तिन्ही जिल्ह्यांना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून वगळण्यासाठी आणेवारीची कोणती पध्दत शासनाद्वारे अवलंबण्यात आली आहे, सर्वेक्षणाचे वेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना याची माहिती पुरविण्यात आली होती काय,

(४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?

डॉ.पतंगराव कदम : (१) नागपूर विभागातील खरीप हंगामाच्या अंतिम पैसेवारी दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार एकूण ७८११ गावांपैकी १५११ गावातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे.

(२) होय.

(३) शासनाच्या प्रचलित पध्दतीनुसार सर्वेक्षण करून पैसेवारी निर्धारित करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही

श्री.एस.क्यु.जमा : सभापती महोदय, आता प्रश्नोत्तरे चर्चेला घेतली जातील हे मंत्री महोदयांना माहिती नसल्यामुळे ते आता येथे उपस्थित नाहीत.

सभापती : सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. आता मंत्री महोदय येथे उपस्थित असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आता मंत्री महोदय येथे का उपस्थित नाहीत हे मी विचारणार नाही. मी आता पुढचा प्रश्न घेतो.

श्री.केशवराव मानकर : हा प्रश्न महत्वाचा असल्यामुळे राखून ठेवावा.

सभापती : हा प्रश्न मी राखून ठेवणार नाही.

श्री.केशवराव मानकर : यामध्ये आमची काहीही चूक नाही.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

राज्यातील आश्रमशाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी

नॅपकिन्स खरेदी केले जात असल्याबाबत

(२) * १३७५७ डॉ.दीपक सावंत : सन्माननीय आदिवासी विकास मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) राज्यातील आश्रमशाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स खरेदी केले जातात, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, सदरहू सॅनिटरी नॅपकिन्स किती आश्रमशाळेत पुरवठा करण्यात आले आहेत,
- (३) अद्यापपर्यंत कोणत्याही आश्रमशाळेत हा पुरवठा झाला नसल्यास, त्यांची कारणे काय आहेत ?

श्री.बबनराव पाचपुते : (१) होय.

- (२) आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील सर्व ५५१ शासकीय आश्रमशाळांना सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे.
- (३) प्रश्न उद्भवत नाही

डॉ.दीपक सावंत :सभापती महोदय, आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यामध्ये 551 शासकीय आश्रमशाळा असून या शाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे असे उत्तर देण्यात आलेले आहे.ज्या ज्या वेळी मी आणि इतर आमदार आश्रमशाळेमध्ये भेटी देण्यासाठी जातो त्या त्या वेळी आश्रमशाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा होत नाही असे आमच्या निदर्शनास आले होते त्याचबरोबर आमच्या महिला कार्यकर्त्यांना देखील तसे सांगण्यात आलेले होते. या मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा केला जातो अशा प्रकारे आज जरी उत्तर देण्यात आलेले असले तरी त्यामध्ये संदिग्धता आहे.हे उत्तर संपूर्णपणे असत्य आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, राज्यामध्ये एकूण किती मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा करण्यात आला होता, 2009-2010 व 2010-2011 या वर्षांमध्ये यासाठी एकूण किती खर्च करण्यात आला होता ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, दिनांक 5 मे 2001 पासून आश्रमशाळेतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्स पुरविण्यात यावेत असा आदेश काढण्यात आला होता व त्यानुसार सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा केला जातो. त्या उत्तरामध्ये संदिग्धता आहे. असे सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले असून ते खरे आहे. त्यावेळी एकत्रित खरेदी करण्यात येत नसल्यामुळे वेगवेगळ्या भागातून स्थानिक पातळीवर सॅनिटरी नॅपकीन्सची खरेदी केली जात होती.त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकीन्सचा पुरवठा करित असतांना थोडी अडचण निर्माण झाली होती परंतु गेल्या

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

EE 5

VTG/ KGS/ KTG/

14:35

ता.प्र.क्र.13757 श्री.बबनराव पाचपुते..

वर्षामध्ये यात सुसुत्रता आणली असून एकत्रित खरेदी करून सॅनिटरी नॅपकीन्स पुरविण्यात येत आहेत व यासंबंधी स्वतंत्र रेकॉर्ड देखील मेन्टेन केले जात आहे. सहावी ते दहावीच्या मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्स पुरविण्यात येत असून ज्या शाळेतील मुलींना ते पुरविण्यात आले आहेत त्यासंबंधी माझ्याकडे शाळांची व जिल्हयाची सुध्दा माहिती आहे. त्याचबरोबर त्यासंबंधी व्यवस्थितपणे रेकॉर्ड मेन्टेन केले जात आहे. पूर्वी काय झाले होते याची मला माहिती नाही.

नंतर श्री.सरफरे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. बबनराव पाचपुते...

आता माझ्याकडे हा विभाग आल्यापासून मी यामध्ये बारकाईने लक्ष घातले आहे. तसेच, याकरिता 90 लाख 10 हजार 120 रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेमध्ये तीन महिन्यांचा स्टॉक असला पाहिजे असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. दुसरे असे की, नॅपकीनच्या पॅकेटचा पुरवठा करीत असतांना त्यामध्ये किती नॅपकीन आहेत याची संख्या त्या पाकिटावर दाखविली जाते. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या लहान मुलींना संभाळतो त्याप्रमाणे त्याठिकाणी अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे याबाबतीत आता कुठेही तक्रार राहिलेली नाही आणि जर तशी तक्रार असेल तर त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाईल. तसेच, यामध्ये त्या शाळेचे हेडमास्तर आणि शाळेतील महिला शिक्षिकेला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी त्या मुलींचे रेकॉर्ड मॅटेन केले पाहिजे आणि जर त्यांनी रेकॉर्ड मॅटेन केले नाहीतर त्यांच्यावर जबाबदारी फिक्स केली जाईल अशाप्रकारचे पत्रक काढण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे त्या शाळांमधील रेकॉर्ड तपासून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी रेकॉर्ड ठेवण्यात आलेले नाही त्याठिकाणी रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थीनींच्या मासिक पाळीचे स्वतंत्र रेकॉर्ड तयार करून ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यामध्ये आता संदिग्धता राहिलेली नाही.

डॉ. नीलम गोन्हे : सभापती महोदय, समाजामध्ये मुलींना त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या गोष्टी पुरेशा आहेत की नाहीत अशाप्रकारची विचारणा केली जाते. त्याबाबत मुलींकडून शिक्षकांना स्पष्टपणे सांगितले जाईल काय हाच खरा प्रश्न आहे? हा लहान मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. आपण आईच्या मायेने विचार करावयास लागलो तर या मुली चार-चौघामध्ये स्पष्टपणे बोलत नाहीत. माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी एका महत्वाच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये देखरेख करणे, निगराणी करणे हा महत्वाचा भाग आहे. तेव्हा प्रत्येक जिल्हयामध्ये महिला व बाल कल्याण समित्यांमध्ये महिला सदस्या आहेत, पंचायत समित्यांमध्ये महिला सदस्या आहेत. त्यांची मदत घेऊन प्रत्येक आदिवासी आश्रमशाळेमधील मुलींची नीटपणे देखभाल केली जात आहे की नाही याबाबत पहाणी करण्यासंबंधी सूचना देण्यात येतील काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सजेशन फॉर ॲक्शन.

श्रीमती शोभाताई फडणवीस : सभापती महोदय, आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींचा हा एकच प्रश्न नाही. आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये शिकणाऱ्या लहान मुलींना आंघोळीला पाणी मिळते की नाही, त्यासाठी बाथरूमची व्यवस्था आहे की नाही इत्यादी अनेक बारीक सारीक गोष्टींचा यामध्ये अंतर्भाव आहे. तसेच, त्या आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक किंवा महिला अधीक्षकांकडून प्रचंड दबाव येत असल्यामुळे भेदरलेल्या हरिणीसारखी तोंडे करुन त्या मुली उभ्या रहातात. मध्यंतरी आश्रमशाळांची पहाणी करण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील महिला आमदारांची मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या समितीच्या वतीने आश्रमशाळेमधील मुलींना वेळेवर आहार दिला जातो की नाही, त्यांना आंघोळीला गरम पाणी दिले जाते की नाही, इतर सोयी-सुविधा पुरविल्या जातात की नाही याची तपासणी करुन समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. तेव्हा तशा प्रकारची व्यवस्था या संदर्भात आपण करणार काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी चांगली सूचना केली आहे. यापूर्वी माननीय सदस्या डॉ. नीलमताई गोन्हे यांनी देखील चांगली सूचना केली त्याप्रमाणे त्या समितीकडे हे काम सुपूर्द केले जाईल. या कामामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे आणि या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. म्हणून मी या संदर्भात सांगितले आहे की, 551 शाळांमध्ये चार वर्षांचा कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यामध्ये यावर्षी 132 आश्रमशाळांकरिता अद्ययावत इमारती बांधण्यासाठी 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची तरतूद केली आहे. अशाप्रकारे येत्या पाच वर्षांमध्ये सर्व शासकीय आश्रमशाळा सर्व सोयींनीयुक्त उत्तम प्रकारच्या करणार आहोत. त्याचप्रमाणे मुलींच्या हॉस्टेलची सोय करणार आहोत, निवासस्थान उपलब्ध नाही म्हणून शिक्षक तेथे रहात नाहीत याकरिता त्यांच्या निवासाची सोय एकाच जागी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या संदर्भात पुन्हा चर्चा करण्याची गरज पडणार नाही. त्याचप्रमाणे महिला अधीक्षक नेमण्यासंदर्भात निर्णय घेतला असून येत्या जून महिन्यापासून महिला अधीक्षक नेमल्या जातील.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, हा एक अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे, अनेक आश्रमशाळांमध्ये गैर गोष्टी घडत असतात. याकरिता त्याठिकाणी महिला अधीक्षक असण्याची गरज आहे. आज अनेक आश्रमशाळांमध्ये महिला अधीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ज्या आश्रमशाळांमध्ये मुली शिक्षण घेत आहेत त्या सर्वच आश्रमशाळांमध्ये निवासी महिला अधीक्षकांची पदे निर्माण केली पाहिजेत ती आपण तातडीने करणार काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, येत्या जून महिन्यापासून सर्व शाळांमध्ये कंपल्सरी महिला अधीक्षकांची नेमणूक करणार आहोत.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.रमेश शेंडगे : सभापती महोदय, महिला अधीक्षकांचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. मी स्वतः आश्रमशाळेमध्ये जाऊन पहाणी केलेली आहे. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी याबाबतीत चांगल्या प्रकारचे उत्तर दिलेले आहे त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आश्रमशाळेमध्ये प्रथमोपचारासाठी एक बॉक्स ठेवण्यात येतो. आश्रमशाळेतील मुलांना खेळत असताना मार लागला तर औषध लावावे लागते किंवा ताप आल्यानंतर औषधे द्यावी लागतात. यासाठी औषधांच्या बॉक्समध्ये औषधे ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशा औषधांचा पुरवठा देखील व्यवस्थित करण्यात आल्याचे दिसत नाही. मला माननीय मंत्री महोदयांना विचारावयाचे आहे की, आश्रमशाळेतील प्रथमोपचारा साठी ठेवण्यात आलेल्या औषधांच्या बॉक्सची वारंवार तपासणी केली जाते काय ? जर तशी तपासणी केली जात असेल तर मग त्याठिकाणी औषधांचा तुटवडा का निर्माण होतो आणि जर तसे घडत असेल तर त्याठिकाणी औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित केला जाईल काय ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, याबाबतीत आश्रमशाळेतील प्रथमोपचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या औषधांच्या बॉक्सची तपासणी केली जाते.त्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदेतील डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली होती. पण आम्ही आता यामध्ये सुधारणा करित असून, आता त्याच ठिकाणी असलेले काही डॉक्टर, कंत्राटी डॉक्टर त्यांच्यावर याबाबतीत जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. कारण बाकीच्या इतर डॉक्टरांना तेथे येण्या-जाण्यासाठी अडचण होते. याकरिता एक समिती नेमण्यात आली असून, त्या समितीचा अहवाल आम्हाला प्राप्त होईल. पण सध्या तेथे तपासणी होत आहे परंतु ती रेकॉर्डपुरती होत आहे असे माझेही मत झालेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात तेथे जाऊन नियमित तपासणी झाली पाहिजे यासाठी स्वतंत्र अशी यंत्रणा उभी करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे.

श्रीमती शोभाताई फडणवीस : सभापती महोदय, मी मेळघाट परिसरामध्ये फिरत असताना माझ्या असे लक्षात आले की,तेथे पाण्याची अतिशय टंचाई आहे. त्याठिकाणी शासनाने जरूर बाथरूम बांधलेले आहे. परंतु बाथरूममध्ये आंघोळीसाठी पाणी नाही. तसेच मी एका आश्रमशाळेचे नाव घेत आहे. "जारीदा"आश्रमशाळेतील मुले आणि मुली एकत्र नदीवर आंघोळीसाठी जातात असे दृश्य मी पाहिले आहे. तेव्हा माननीय मंत्री महोदयांकडे बाथरूममध्ये पाण्याची सोय करण्यासाठी जेवढी प्रपोजल्स आली असतील त्यांना ताबडतोब मंजूरी देऊन तेथे पाण्याची व्यवस्था करणार आहात काय ?

ता.प.क्र.13757 . . .

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सजेशन फॉर ॲक्शन.

डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, राज्यातील आश्रमशाळेतील मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा पुरवठा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंडळातर्फे होतो. आमच्या असे लक्षात आले आहे किंवा जी आकडेवारी प्राप्त झाली आहे. ज्याप्रमाणे आश्रमशाळेसाठी धान्याचा दर, औषधांचा दर, स्वेटर, ब्लॅकेट्स, गणवेश इ.वस्तुंचा दर जास्त असतो, त्याचप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्सचा दर देखील जास्त आहे, असे आम्ही जेव्हा त्याठिकाणी भेटी दिल्या तेव्हा लक्षात आले आहे.याबाबतीत माननीय मंत्री महोदयांकडे काही उत्तर आहे काय, सॅनिटरी नॅपकिन्सचा दर बाजारभावा इतकाच आहे की त्यापेक्षा जास्त आहे ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, याठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी येथे घटनांचा उल्लेख केलेला आहे. याबाबतीत त्यांचे मत वेगळे आहे. पण ही समिती आयुक्त लेव्हलवर आहे आणि त्यामध्ये 4 सदस्य आहेत. माझ्याकडे काही सूचना आल्या. तेव्हा मी विचारणा केली की, सध्या लोकल मार्केटमध्ये काय भाव आहे? याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर त्या भावाबरोबर या भावाची तुलना केली तर असे दिसून येईल की, त्या भावाप्रमाणेच घेण्यात आलेले आहे. फक्त त्या मध्ये एक रुपया वाढवून दिलेला आहे आणि तो त्याठिकाणी पोहोच करण्यासाठी वाढविलेला आहे. त्यामुळे यामध्ये नियमित पुरवठा आणि नियमित वापर या दोन गोष्टींना महत्व दिलेले आहे.

. . . .2 जी-3

**राज्यात आकारास येत असलेल्या काही मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत**

(3) * 14062 श्री. एस. क्यू. ज़मा, श्री.विजय सावंत, श्री.हुसेन दलवाई : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(1) राज्यात आकारास येत असलेल्या सात मोठ्या प्रकल्पांमुळे (गोसेखुर्द, मिहान, एनटीपीसी मौदा, निम्न वर्धा योजना, बिरसी विमानतळ आदानी ऊर्जा आणि शिर्डी विमानतळ) विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्यास, राष्ट्रीय पुनर्वसन कायदा, 2007 प्रमाणे सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश दिनांक 23 डिसेंबर, 2010 च्या आसपास दिले होते, हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, आजपर्यंत किती प्रकल्पांकडून सदर प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत, असल्यास त्यावर शासनाने काय कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(3) तसेच उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त झाले नसल्यास संबंधित प्रकल्पांचे काम थांबविण्यासाठी शासनाने काय कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(4) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.प्रकाश सोळंके, डॉ.पतंगराव कदम यांच्याकरिता : (1) नाही.

(2), (3), (4) आजपर्यंत शासनाकडे 6 प्रकल्पांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाले आहेत. सदर सर्व प्रस्तावांवर शासनस्तरावर छाननीचे काम सुरु आहे.

श्री.सय्यद ज़मा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जबाब दिया है, वह स्पष्ट नहीं है. उत्तर में लिखा है कि 6 प्रकल्पों के प्रस्ताव आए हैं और उनकी छाननी चालू है. मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या ये वही प्रकल्प हैं जिनका जिक्र प्रश्न में किया गया है, अर्थात क्या गोसीखुर्द, मिहान, एनटीपीसी मौदा, निम्न वर्धा योजना, बिरसी विमानतळ आदानी ऊर्जा आणि शिर्डी विमानतळ प्रकल्पों के प्रस्ताव आपके पास आए है और उनकी छाननी चालू है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गोसीखुर्द और मिहान प्रकल्पग्रस्तों के बारे में निर्णय बहुत विलम्ब से हो रहे हैं. कार्गो हब में आने वाले लोग वापस जा रहे हैं. माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यह चिन्ता का विषय है. 3 मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन इस बारे में निर्णय नहीं हुआ है. गोसीखुर्द प्रकल्प के लिए सेन्द्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है. उसमें पानी का स्तर बढ़ने पर 2-3 महिलाएं बह गईं. क्या आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय अर्जेंट मीटिंग बुलाकर प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दों के बारे में चर्चा करके नीतिगत फैसले लेंगे ?

. . . नंतर श्रीमती थोरात.

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, आदानी ऊर्जा प्रकल्प, एनटीपीसी मौदा, गोसीखुर्द प्रकल्प नागपूर, बिरसी विमानतळ आणि मिहान कार्गोहब यांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्ता मार्फत दिनांक 27/12/2010 रोजी शासनाकडे प्राप्त झालेले आहेत. या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी ते प्रस्ताव परत विभागीय स्तरावर पाठविण्यात आलेले आहेत. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर ते प्रस्तावत प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी ठेवण्यात येतील. सन्माननीय सदस्यांनी प्राधिकरणाची बैठक घेण्याआधी एक बैठक घ्यावी अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे. मंत्री, मदत व पुनर्वसन यांच्याकडे ही बैठक आयोजित केली जाईल.

श्री. हुसेन दलवाई : सभापती महोदय, शासन सतत एक गोष्ट जाहीर करते की, प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधी पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविला जाईल त्यानंतर प्रकल्पाचे काम केले जाईल. पण महाराष्ट्रात कुठेही ही गोष्ट दिसत नाही. या प्रकल्पाच्या संदर्भात देखील काहीही सांगण्यात आलेले नाही. प्रस्ताव येणार मग त्याची छाननी होणार, त्यामध्ये बराचसा कालावधी जाणार आहे तोपर्यंत हा प्रकल्प थांबविण्यात येणार आहे काय, कारण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आधी पुनर्वसन मग प्रकल्प ही गोष्ट सतत सांगितलेली आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की, कोयना प्रकल्पाला 60 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. अजूनही चारही फेजच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न शिल्लक आहेत. त्यांचे प्रश्न मुळीच सुटलेले नाहीत असे मी म्हणणार नाही. काही प्रश्न सुटलेले आहेत तर काही प्रश्नांची आश्वासने सातत्याने दिली जात आहेत. त्या भागातील लोकांना पाणी देण्याचा प्रश्न आहे. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केल्या नंतर काही गावांना पाणीपुरवठा करण्यात आला पण त्यातून शिरगावला वगळण्यात आले, असे का करण्यात येते आहे हेच मला कळत नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना सामावून घेतले जाईल, त्यांना रोजगार दिला जाईल असे सांगितले जाते पण आजही तेथे 300 ते 350 लोक उपोषण करतात, धरणे धरतात पण त्यांना कामावर घेतले जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न ताबडतोबीने सोडविल्यानंतर प्रकल्प घेतले पाहिजेत अशी शासनाची भूमिका आहे की, दडपशाही करण्याची भूमिका आहे? यासंदर्भातील शासनाची नेमकी भूमिका सभागृहाला कळली पाहिजे.

...2...

ता.प्र.क्र.14062....

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, यासंबंधात शासनाचे धोरण प्रथम प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्प असेच आहे. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दि.27/12/2010 रोजी सदर प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झालेले आहेत. या प्रस्तावांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सन 1999 च्या धोरणानुसार हे प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झालेले आहेत. यासंदर्भात आता राष्ट्रीय धोरण जाहीर झाल्यामुळे या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यामुळे हे प्रस्ताव परत विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. त्रुटींची पूर्तता करून सदर प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी होऊन प्राधिकरणाच्या पुढील बैठकीमध्ये हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवले जातील. याठिकाणी कोयनेचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. तो या प्रश्नाच्या बाहेरचा आहे.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. हुसेन दलवाई यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे तोच प्रश्न मला या ठिकाणी विचारण्याचा होता. त्यामुळे मी या प्रश्नाच्या संदर्भात थोडे व्यापकतेने विचारू इच्छितो. आतापर्यंत या राज्यात जे प्रकल्प झाले त्यातील किती प्रकल्पग्रस्तांचे 100 टक्के पुनर्वसन झाले, किती प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अपूर्ण आहे. सभापती महोदय, आपण स्वतः कोयना प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात काम करणारे कार्यकर्ते आहात. मी या संदर्भात आपल्या चेंबरमध्ये येऊन अनेक वेळा प्रश्न विचारलेले आहेत. आपण स्वतः यासंदर्भात बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांची दुःखे माडली आहेत तसेच अनेक वेळा आपला संताप आणि नाराजी शासनाकडे व्यक्त केलेली आहे. शासन याबाबतीत पुन्हा विचार करणार आहे काय? पहिल्यांदा पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्प असे असले तरी प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये पुनर्वसनासाठी फक्त दोन टक्के खर्चाची तरतूद असते. माननीय अर्थमंत्री या ठिकाणी बसलेले आहेत.

यानंतर श्री. बरवड....

ता. प्र. क्र. 14062

श्री. जयंत प्र. पाटील

शासन ज्या गतीने आज औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत किंवा बाकीच्या बाबतीत विकास करावयास मागत आहे त्यामध्ये पहिल्यांदा पुनर्वसन करून मग पुढे प्रकल्प सुरु करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण करणार काय ? यामध्ये आपण चायनाच्या गतीने जावयास मागत आहोत. चायनामध्ये मी तीन चार वेळा गेलो. या वर्षात मी दोन वेळा चायनाला गेलो होतो. त्या ठिकाणी प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधी पुनर्वसन केले जाते. आपले अधिकारी दौऱ्यावर जातात, मंत्री दौऱ्यावर जातात, त्यांचा काय अभ्यास होतो ? प्रकल्पाच्या पुढील 60 किलोमीटरपर्यंतच्या सगळ्या गावांचे पुनर्वसन पुढच्या 100 वर्षाची डेव्हलपमेंट गृहीत धरून त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होते. त्यामुळे चायनाचे धोरण डोव्यासमोर ठेऊन शासन हे धोरण ठरविणार का ?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भाषणातून ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्याचा जरूर विचार केला जाईल.

डॉ. नीलम गोऱ्हे : सभापती महोदय, शासनाकडून या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनामध्ये जी दिरंगाई होते त्याचा परिणाम असा होतो की, बहुतेक प्रकल्पाच्या आसपासच्या जमिनी वेगवेगळे श्रीमंत लोक पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून शेतकऱ्यांकडून ताब्यात घेऊन ठेवतात आणि जमिनीचा भाव वाढेपर्यंत एका बाजूला विलंब होत असतो आणि जे खरे शेतकरी आहेत त्या लोकांना मात्र जमिनीचे जुनेच भाव मिळतात, अशी त्यांची बऱ्याच ठिकाणी तक्रार असते. सहा प्रकल्पांचे प्रस्ताव आलेले आहेत असे शासनाने उत्तरामध्ये म्हटले आहे. नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मिहान प्रकल्पाबाबत आम्हाला कागदोपत्री अगदी व्यवस्थित उत्तर देण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रकल्पाग्रस्तांचे जे संपूर्ण वारसदार आहेत त्यांना या प्रकल्पांचे शेअर्स सुध्दा मिळतील असे त्या प्रस्तावांचे स्वरूप होते. त्यामुळे हे जे प्रस्ताव आलेले आहेत त्यांचे स्वरूप काय आहे ? सन्माननीय सदस्य श्री. हुसेन दलवाई तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. पाटील यांनी या ठिकाणी मुद्दे मांडले. मला असे विचारावयाचे आहे की, सर्व सहा विभागांमध्ये पूर्वी जे प्रकल्प झालेले आहेत त्यांचे पुनर्वसन किती झाले याची श्वेतपत्रिका शासन सादर करणार काय ? कारण प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा मोर्चा मंत्रालयावर आला होता. आपण त्यांना आश्वासने दिली पण त्याची काहीही

RDB/ MMP/ KGS/ D/ KTG

ता. प्र. क्र. 14062

डॉ. नीलम गोन्हे

अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शासनाने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे या प्रस्तावांचे स्वरूप काय आहे ते सांगावे.

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, या ठिकाणी मिहान कार्गोहबचा प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला आहे. त्यामध्ये जे पॅकेज दिलेले आहे त्यात साधारणतः बाधित गावठाणातील कुटुंबांना 300 चौ.मी.चा विकसित भूखंड व त्यावर 300 चौ.मी.बांधकाम असलेले घर देण्यात येईल. बाधित गावठाणातील बाधित कुटुंबांना 150 चौ.मी.चा विकसित भूखंड व त्यावर 150 चौ.मी. बांधकाम असलेले घर देण्यात येईल. सदरील प्रकल्पग्रस्तांना जी काही जमीन किंवा भूखंड वाटप करणार त्यावर कोणतेही अतिक्रमण असणार नाही. सदर जमीन पती आणि पत्नी या दोघांच्याही नावाने संयुक्तपणे करून देता येईल. कंपनीकडून गोठे बांधण्यासाठी किमान 15 हजार रुपये देता येतील. गावठाणातून सामान हलविण्यासाठी 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाईल. छोटे कारागीर, छोटे व्यापारी स्वतःचा व्यवसाय असणारी व्यक्ती यांना दुकाने व शेड बांधण्यासाठी एकरकमी 25 हजार रुपये देण्यात येईल. शासनाच्या मान्यतेने शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. बाधित व्यक्तींना किंवा त्यांचा समूह किंवा सहकारी यांना प्रकल्पाच्या ठिकाणी कंत्राटी कामे, दुकाने, आर्थिक उत्पन्नाची साधने प्राधान्याने उपलब्ध करून देता येतील. भूमिहीन शेतकऱ्यांना व बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पाच्या बांधकामावर मजूर म्हणून काम देण्यात येईल. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमीन अथवा नोकरी देता येणार नाही अशा प्रकल्पग्रस्त कुटुंबास 750 दिवस एवढी किमान कृषी मजुरी इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल. कंपनी शेअर्स किंवा डिबेंचर्स इश्यू करीत असल्यास प्रकल्पग्रस्त कुटुंबास मिळालेल्या पुनर्वसन अनुदानाच्या 20 टक्के पर्यंत शेअर्स किंवा डिबेंचर्स घेण्यास मुभा राहिल. कंपनीच्या इच्छेनुसार जमिनीचे संपादन होत असल्याने कंपनी पहिल्या वर्षी दरमहा 25 दिवसाएवढी कृषी मजुरी उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून देईल.

यानंतर श्री. खंदारे ...

ता.प्र.क्र.14062....

श्री.प्रकाश सोळंके.....

बाधित पात्र असलेल्या आश्रित परित्यक्ता.....सभापती महोदय, या पॅकेजची माहिती मोठी असल्यामुळे मी ही माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवू इच्छितो.

सभापती : ठीक आहे.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, मिहान प्रकल्पाने चांगले पॅकेज दिलेले आहे. परंतु त्यात काही त्रुटी आहेत, त्या त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर त्याला मान्यता देण्याचे काम पुढील बैठकीत केले जाईल. सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोन्हे यांनी दुसरा प्रश्न अतिशय व्यापक स्वरूपात विचारला आहे.

श्रीमती शोभा फडणवीस : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी मिहान व एनटीपीसी प्रकल्पातील पॅकेजची माहिती सभागृहाला दिली आहे. गोसीखूर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले आहे. पण त्या लोकांना त्या गावात जबरदस्तीने नेऊन बसविले आहे. त्याठिकाणी रस्ते नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. जेथे गेल्यावर ते गाव आहे की गावाबाहेरील वस्ती आहे ते समजत नाही. त्या लोकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचे हाल होत आहेत. पुनर्वसित गावात प्रकल्पाचे पाणी शिरण्याचा धोका आहे. म्हणजे एकीकडे पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही व दुसरीकडे गावात पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. माणसांना जगता येईल अशा प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. त्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी पैशाची अडचण असल्याचे वाटत नाही. त्यांना रस्ते पाहिजेत, सिंचनाची सोय पाहिजे, पिण्याचे पाणी पाहिजे. मंत्री महोदयांनी आता सांगितले की, त्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने निधी दिलेला आहे. परंतु मी शासनाच्या निदर्शनास आणू इच्छिते की, चंद्रभागा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन ज्या गावात झाले आहे त्या गावापासून शाळा 10 कि.मी.अंतरावर आहे. म्हणून मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे शासनाला प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावयाचे असेल तर ते व्यवस्थित करावे, जेणे करून लोक तेथे राहण्यास जातील. गोसीखूर्द प्रकल्पग्रस्तांचे व अन्य प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे केले जाईल काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : होय.

2....

श्री.हुसेन दलवाई : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी दिलेले उत्तर ऐकून फार बरे वाटले. महाराष्ट्रामध्ये आता पुनर्वसनाच्या बाबतीत काही तरी होईल असे मला वाटते. परंतु यावर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. गेल्या 60 वर्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आजही तसेच शिल्लक आहेत. माझा प्रश्न कोयनानगर प्रकल्पग्रस्तांसंबंधीचा आहे. त्यांच्याबाबत पुढील आठवड्यामध्ये मंत्री महोदय बैठक घेतील काय ? कारण ते लोक सोमवारपासून धरणे धरण्यासाठी बसणार आहेत, आंदोलन करणार आहेत. माननीय सभापतींना आपल्या प्रश्नांची जाण असल्यामुळे ते आपला प्रश्न नक्कीच सोडवतील असे आपल्यावतीने मी त्यांना सांगितले आहे.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या सूचनेप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांची एक बैठक आयोजित केली जाईल.

सभापती : यापूर्वीच्या काळात प्रकल्पासाठी भूसंपादन करून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातामध्ये पैसे देऊन त्यांना पिटाळून लावले जात होते अशी दुर्दैवी परिस्थिती होती. राज्यात 1976 साली पुनर्वसन ॲक्ट अस्तित्वात आला आहे. त्यानंतर या ॲक्टमध्ये अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पुनर्वसित गावात जे प्रकल्पग्रस्त राहतात त्यांच्याबाबतीत असा गैरसमज आहे की, त्यांना 2 टक्के किंवा 3 टक्के रक्कम दिली की आपण मोकळे झालो. खरे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे नवीन गावठाणात पुनर्वसन करणे, नवीन रस्ते तयार करणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे या सगळ्या बाबी पुनर्वसनात अंतर्भूत आहेत. या बाबींची पूर्तता होत आहे की नाही हे शासनाला डोळ्यात तेल घालून पहावे लागेल. 45 वर्षापूर्वी मी पुष्कळ अंशी पुनर्वसनाचे काम केलेले आहे.मी एखाद्या दिवशी माननीय सदस्यांबरोबर माझ्या दालनात यासंदर्भात जरूर बैठक बोलवितो. प्रकल्पग्रस्तांचे कितीही चांगले पुनर्वसन केले तरी मूळ गावातील माणसे शेकडो वर्षे त्या गावात राहिलेली असतात. त्यांना तेथून दुस-या ठिकाणी राहण्यासाठी जावे लागते त्यांच्या दुःखाबाबत कोणी कितीही वर्णन केले तरी ते न समजण्यासारखे आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांना रिलिफ देण्यासाठी शासनाने ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. या प्रश्नासंबंधी माझ्या चेंबरमध्ये एक बैठक घेऊन तेथे आपल्याला याबाबत चर्चा करता येईल. पुनर्वसनाच्या धोरणाबाबत मंत्री महोदय पाठपुरावा चांगल्या प्रकारे करतील, कारण आपण जे उत्तर दिले आहे ते ऐकल्यानंतर माझी व या सदनाचीही खात्री झालेली आहे.

3....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

JJ-3

NTK/ D/ KTG/ KGS/ MMP/

सभापती.....

यानंतर आजच्या कामकाजपत्रिकेवरील क्रमांक 1 वरील प्रश्न शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्यामुळे तो चर्चेसाठी घ्यावयाचा का असे मी सदनाला विचारु इच्छितो.

(दोन्ही बाजूचे अनेक सन्माननीय सदस्य होकार दर्शवितात.)

यानंतर श्री.शिगम....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आल्याबाबत

(१) * १३५१९ श्री.केशवराव मानकर , श्री.नितीन गडकरी , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्रीमती शोभाताई फडणवीस , श्री.नागो गाणार : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान राज्यातील आणेवारीत नागपूर विभागातील १४११ गावे दुष्काळग्रस्त असून खरीप पिकांसाठी तब्बल १४ हजार ३१७ गावांची आणेवारी ५० पैशांच्या वर आहे, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, सदर आणेवारीत गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यातील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी नसल्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून हे तिन्ही जिल्हे वगळण्यात आले आहे काय,
- (३) असल्यास, राज्यात दरवर्षी सर्वात जास्त दुष्काळ पडणाऱ्या या तिन्ही जिल्ह्यांना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून वगळण्यासाठी आणेवारीची कोणती पध्दत शासनाद्वारे अवलंबण्यात आली आहे, सर्व्हेक्षणचे वेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना याची माहिती पुरविण्यात आली होती काय,
- (४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. प्रकाश सोळंके, डॉ.पतंगराव कदम : (१) नागपूर विभागातील खरीप हंगामाच्या अंतिम पैसेवारी दिनांक १५ जानेवारी, २०११ वा त्या दरम्यान जाहीर करण्यात आली असून त्यानुसार एकूण ७८११ गावांपैकी १५११ गावातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे.

(२) होय.

(३) शासनाच्या प्रचलित पध्दतीनुसार सर्व्हेक्षण करून पैसेवारी निर्धारित करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री. केशवराव मानकर : सभापती महोदय, इंग्रजांच्या काळातील आणेवारीची पध्दत आज देखील तशीच कायम आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय. विदर्भातील ४ जिल्ह्यातील दिलेली आणेवारी अत्यंत दुर्दैवी आहे असेच म्हणावे लागेल. या सभागृहामध्ये अवकाळी पावसाबाबत खूप मोठी चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेमधून शेतकऱ्याला न्याय मिळेल असे वाटत होते. गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांची आणेवारी शून्य दाखविलेली आहे. ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी दाखविलेली आहे. तिरोडा तालुक्यातील किती गावांची आणेवारी ५० पैशापेक्षा खाली आहे हे गोंदिया जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या मिटींगमध्ये ठरलेले आहे. असे असताना गोंदियाची आणेवारी ५० पैशापेक्षा खाली दाखविलेली आहे. सर्व्हे रिपोर्टची ही माहिती आहे. चंद्रपूरला देखील ५० पैशा पेक्षा कमी आणेवारी दाखविलेली आहे. तेव्हा चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या ४ जिल्ह्यांची पुनर्तपासणी करून तेथील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल

..2..

ता.प्र.क्र.13519.....

श्री. केशवराव मानकर

काय ? आधुनिक कृषी अवजारे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यामुळे भरपूर उत्पन्न यावयास लागले आहे.

सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री. केशवराव मानकर : माझा प्रश्न असा आहे की, आणेवारीची जुनी पध्दत बदलून नवीन पध्दत शासन अवलंबिणार आहे काय, जेणे करुन शेतक-याला न्याय मिळू शकेल ?

श्री. प्रकाश सोळंकी : भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी अंतिम पैसेवारी जाहीर झालेली आहे. सन्माननीय सदस्य सांगतात ती वस्तुस्थिती आहे. 50 पैशाच्या आतील गावे नाहीत. सर्व गावांची पैसेवारी 50 पैशाच्या वर आहे. प्रचलित पध्दती अनुसार पैसेवारी जाहीर झालेली आहे. पीक कापण्याच्या वेळी पैसेवारी जाहीर केली जाते. आता हंगाम संपूर्ण गेलेला असल्यामुळे त्याबाबतीत काही करता येणार नाही. पैसेवारी बाबत जेथून तक्रारी येतात तेथे पुनर्तपासणी केली जाते. परंतु या जिल्ह्यातून कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. यासंदर्भात गावपातळीवर स्थापन केलेल्या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींचा देखील समावेश केलेला आहे. सेवा सहकारी सोसायटीचे चेअरमन, प्रगतिशील शेतकरी, अत्यल्प भूधारक अशा लोकांचा समितीमध्ये समावेश असतो. मंडळ अधिकारी हे त्या समितीचे अध्यक्ष असतात. प्रत्येक गावात 12 प्रयोग केले पाहिजेत अशी अट घातलेली आहे. समितीचा अहवाल लेखी स्वरूपाचा असावयास पाहिजे. त्या अहवालावर सर्वांच्या स्वाक्ष-या घेणे बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी पैसेवारी जाहीर केली जाते तेथील लोकांच्या तक्रारी आल्या तर पुन्हा पैसेवारी काढली जाते. एखादी स्पेसिफिक तक्रार प्राप्त झाली तर फेर चौकशी करण्यात येईल.

श्रीमती शोभा फडणवीस : अवर्षण, अतिअवर्षण आणि अवकाळी पाऊस यावर झालेल्या चर्चेच्या वेळी मी सांगितले होते की, आपण जी आणेवारी काढलेली आहे त्यामुळे शेतक-यांना न्याय मिळणार नाही.

...नंतर श्री. गीते...

ता.प्र.क्र.13519....

श्रीमती शोभा फडणवीस...

याचे स्पष्टीकरण दिले गेले की, अवकाळी पावसामुळे धानाची शेती खराब झाली होती. कापलेला धान आडवा पडला होता. तुम्हाला उभा असलेला धान आणेवारी काढण्यासाठी मिळणार नाही. अवकाळी पावसाच्या संदर्भात वेगळी चौकशी करू आणि शेतकऱ्यांना न्याय देऊ असे सांगितल्यानंतर महसूल विभागाने ही आणेवारी पध्दत कोठून काढली ? नोव्हेंबर महिन्याच्या आधी अवकाळी पाऊस पडलेला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात धान कापल्यानंतर हा अवकाळी पाऊस पडलेला आहे. या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या कापलेल्या धानाचे नुकसान झालेले आहे, त्याबाबतीत शासनाने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही. आता शेतकऱ्यांच्या शेतात कोणत्याही प्रकारचे पीक नाही. यासंदर्भात मी जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी स्वरूपात पत्र दिलेले आहे. त्यांच्या पत्रात देखील उल्लेख केला आहे की, अवकाळी पावसामुळे धान पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला शासनाकडून दिला गेलेला नाही, त्यांचेवर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्हयास दुष्काळी जिल्हा म्हणून जाहीर करावा. परंतु याबाबतीत देखील शासनाकडून कार्यवाही केली गेलेली नाही. शासनाने आम्हाला अवकाळी पावसाच्या संदर्भात शब्द दिलेला आहे तो शब्द पाळून चंद्रपूर हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात येईल काय ?

श्री. प्रकाश सोळंखे : सन्माननीय सदस्यांनी ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला ती जनरल तक्रार आहे. आता गाव हे घटक धरून आणेवारी काढली जाते. यासंदर्भात सन्माननीय सदस्यांची स्पेसिफिक तक्रार असेल तर त्याबाबतीत निश्चितपणे विचार करता येईल.

श्रीमती शोभा फडणवीस : यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेबरोबर पत्रव्यवहार केलेला आहे. त्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात शासनाकडून काहीही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. या संदर्भात शासन आदेश पाठविणार नसेल तर आमच्या तक्रारींची दखल कोण घेणार ? स्थानिक जिल्हयातील आमदारांनी तसेच अनेक गावकऱ्यांनी याबाबतीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वारंवार सांगण्यात येते की, आम्हाला यासंदर्भात शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. माझे तर असे म्हणणे आहे की, चंद्रपूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांची शासनाने फसवणूक केलेली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने

2..

श्रीमती शोभा फडणवीस...

ता.प्र.क्र.13519....

चौथऱ्यावर नेऊन बसविले आहे. म्हणून चंद्रपूर जिल्हा हा सरसकट दुष्काळी जिल्हा म्हणून जाहीर करणार आहात काय ?

श्री. प्रकाश सोळंखे : महोदय, आणेवारी कशा पध्दतीने काढावयाची यासंबधी जी.आर.काढलेला आहे. आणेवारी संदर्भात पुन्हा पुन्हा आदेश देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. यासंदर्भात स्टॅन्डींग ऑर्डर देण्यात आलेल्या आहेत. दरवर्षी आणेवारी काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते आणि अंतिम आणेवारी दिनांक 15 डिसेंबरला जाहीर करतो. नोव्हेंबर नंतर अवकाळी पाऊस आला व अन्य कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाले असेल, नोव्हेंबर नंतर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले इत्यादी सर्व बाबींचा विचार करून 15 डिसेंबरला अंतिम आणेवारी जाहीर करतो. ज्या ठिकाणी 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आलेली आहे, त्या ठिकाणी टंचाईग्रस्त विभाग म्हणून जाहीर करित असतो. नागपूर विभागातील 1511गावात टंचाईग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या टंचाईग्रस्त गावांसाठी योग्य ते आदेश काढले जातील.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या बाबतीत थोडीशी गल्लत होत चालली आहे. गल्लत अशी आहे की, प्रचलित आणेवारी पध्दत ही या राज्यात ब्रिटीश काळापासून सुरु आहे. सभापती महोदय, आपण देखील या सभागृहात होतात, 1978 साली कै.वसंतरावदादा पाटील यांनी भगवंतराव गायकवाड कमिटी नेमली होती. या कमिटीने आपला अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे. यासंदर्भात पुन्हा सुब्रम्हण्यम समिती नेमली गेली, त्या समितीने देखील आपला अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे. परंतु या दोन्ही कमिटीयांचे रिपोर्ट शासन दरबारी धूळ खात पडलेले आहेत. या रिपोर्टवर शासनाने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही. ब्रिटीशांच्या काळापासून सुरु असलेली आणेवारी काढण्याची पध्दत आजही चालू आहे. निसर्ग बदलत चालला आहे. वर्षानुवर्षे परिस्थिती बदलत चालली आहे. आपण इंग्रजांच्या काळापासून सुरु असलेली आणेवारी काढण्याची पध्दत सुरु ठेवली तर राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. आणेवारी काढण्याच्या पध्दतीमध्ये अवकाळी पावसाचा उल्लेख नाही. या ठिकाणी आणेवारीचा प्रश्न यासाठी उपस्थित झाला की, शासनाने प्रचलित पध्दतीप्रमाणे आणेवारी काढली. अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे ज्या गांवाची पिके नष्ट झाली त्या पिकांचा समावेश या आणेवारीत केला नाही. त्यामुळे आणेवारीमध्ये कमी गावांचा समावेश झाला. अवकाळी पावसामुळे उद्ध्वस्त झालेली पिके

3..

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

LL-3

ता.प्र.क्र.13519....

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

आणि प्रचलित आणेवारी काढण्याची पध्दत यात तफावत आहे. ही तफावत दूर करून अवकाळी पावसात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदत जाहीर करावयास पाहिजे होती. परंतु शासनाने आणेवारीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना डावलले आहे. त्या डावललेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल काय? ब्रिटीशांच्या काळापासून प्रचलित असलेली आणेवारी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बदलली जाणार आहे काय ?

यानंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाले होते त्याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन, अहवाल घेऊन, गाव पातळीवर समित्या नेमून आकडेवारी गोळा केली होती. ज्याठिकाणी 50 टक्क्यापेक्षा जास्त पिकाचे नुकसान झाले अशा ठिकाणी मदत जाहीर केली. यासाठी शासनाने आणेवारीची वाट पाहिलेली नाही. पंचनामे करुन ही मदत दिली गेली आहे. त्यामुळे पैसेवारीमुळे मदत थांबली असे म्हणणे योग्य होणार नाही.....(अडथळा)...

श्रीमती शोभा फडणवीस : पंचनामे झालेले नाहीत.

सभापती : माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर पूर्ण होऊ द्यावे.

श्री.प्रकाश सोळंके : अवकाळी पावसामुळे जे नुकसान झाले त्या संदर्भात आणेवारीचा विषय घेत नाही. प्रत्यक्ष पाहणी करुन शासनाने आदेश दिले आहेत. वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 1088 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले गेले. सन्माननीय सदस्यांनी आणेवारीच्या पध्दतीमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे असे सांगितले आहे. निश्चितपणे आणखी काय सुधारणा करता येतील याबाबत शासन स्तरावर विचार केला जाईल.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, यापूर्वी आणेवारीचा विषय सभागृहात चर्चेला आला होता. आपण स्वतः शासनाला निदेश दिले होते. सूचना केली होती की, ही पध्दत बंद करुन यामध्ये सुधारणा करावी. तत्कालीन महसूल मंत्री श्री.नारायण राणे यांनी देखील ही पध्दत बदलली पाहिजे असे सांगितले होते. माननीय उप मुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी देखील ही पध्दत कालबाह्य झालेली असून नवीन पध्दत सुरु केली पाहिजे असे सांगितले होते. आम्ही हे अनेकदा ऐकत आहोत. शेती महामंडळाच्या जमिनी परत देण्यासाठी शासनाने ताबडतोबीने सभागृहापुढे विधेयक मांडले होते. कंत्राटी पध्दतीने शेती करण्याबद्दलचे विधेयक ताबडतोबीने सभागृहापुढे मांडण्यात आले होते. पैसेवारीच्या कालबाह्य पध्दतीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना ही पध्दत सुधारण्यासाठी विधेयक का आणले जात नाही? हा प्रश्न मंत्री महोदयांसहित तुमच्या आमच्या मनात निर्माण झाला आहे. सभापती महोदय, आपण निदेश दिले होते त्यावेळी आम्ही आपले अभिनंदन केले होते. किमान या पध्दतीमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सभागृहामध्ये आणले गेले तर काय बदल घडणार आहेत हे कळेल. प्रत्येक वेळी या पध्दतीने बदल केला पाहिजे असे म्हटले जाते. परंतु कृती का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे.

..2..

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी जी भावना व्यक्त केली त्याबाबत मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या पध्दतीमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाच्या वतीने जे काही करणे आवश्यक आहे ते निश्चितपणे केले जाईल.

सभापती : सन्माननीय राज्यमंत्री महोदय, सद्नाची भावना अशी आहे की, आणेवारी किंवा पैसेवारीची ही जुनी पध्दत ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आहे. ही पध्दत आपण बदलली किंवा दुरुस्त केली तर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकतो, ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची भावना आहे. सन्माननीय महसूल मंत्री सभागृहात उपस्थित झाले आहेत. माझी त्यांना अशी सूचना आहे की, यापूर्वी शासनाने भगवंतराव गायकवाड समिती नेमली होती, इतरही समित्या नेमल्या होत्या. त्या समित्यांचे जे निष्कर्ष आहेत त्यांचा अभ्यास करून तातडीने आणेवारीची पध्दत नव्याने तयार करावी. अवेळी पाऊस हा राज्याच्या प्रत्येक भागामध्ये पडला. अवेळी पाऊस काही ठिकाणी एवढा पडला की, धान किंवा अन्य पिके काढण्यापूर्वी मातीत मिसळून गेली. मातीत मिसळल्यामुळे पिके मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पिके मातीत मिसळली गेली त्यापूर्वी पैसेवारीचा निर्णय घेतला असल्यास अन्याय होण्याची शक्यता आहे अशी माननीय सदस्या श्रीमती शोभा फडणवीस, माननीय विरोधी पक्षनेते श्री.पांडुरंग फुंडकर, माननीय सदस्य श्री.हुसेन दलवाई यांची भावना आहे. त्यांचे असे मत आहे की, या अवेळी पावसामुळे जो परिणाम झाला त्याचा विचार करून आणेवारी निश्चित करावी. त्यामुळे नागपूर विभागातील एकूण 7811 गावांपैकी 1511 गावातील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा जास्त असावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. माझ्या मते त्यांचे हे म्हणणे योग्य आहे. कारण मी माझ्या भागात परिस्थिती पाहिली आहे. माझ्या शेतात प्रत्यक्ष पाहिले आहे.

नंतर 2एन.1..

सभापती

तेव्हा मला असे दिसून आले की, शेतातील पीक येण्यापूर्वीच ते झडून मातीमोल झाले. या गोष्टीचा विचार करून मंत्री महोदयांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, आपण केलेल्या सूचनांची नोंद घेतली जाईल.

(विरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात)

श्री. दिवाकर रावते : महोदय, आणेवारीची जुनी पध्दत बदलण्यासंबंधीचे विधेयक शासन गेल्या दोन वर्षांपासून आणू असे म्हणत आहे पण अजूनही असे विधेयक सभागृहात मान्यतेसाठी आणले जात नाही आणि आपण केलेल्या महत्वाच्या सूचनांना मात्र एकाच वाक्यात मोघम स्वरूपाचे उत्तर देत आहेत, हे योग्य नाही.

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, पीक पैसेवारीच्या विषयावर वर्षानुवर्षे सभागृहात चर्चा होत असते. त्या माध्यमातून आणेवारीची जुनी पध्दत बदलून नवीन पध्दत आणावी अशी अपेक्षा देखील सातत्याने सभागृहात व्यक्त केली जात आहे. पूर्वीच्या काळात या आणेवारीच्या संदर्भात शासनाने भगवंतराव गायकवाड व सुब्रह्मण्यम समिती अशा दोन समित्या नेमल्या होत्या. तसेच अनेक वेळा वेगवेगळ्या माध्यमातून सभागृहात चर्चाही झाल्या पण अद्यापही निष्कर्ष निघालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीचा विचार करता आपण ज्या सूचना केलेल्या आहेत तसेच सभागृहाच्या माध्यमातून जी मागणी केली त्या सर्व बाबींचा विचार निश्चितपणे केला जाईल. आणखी एक सूचना आपण अशी केलेली आहे की, 50 पैशाच्या वर मूळ आणेवारी लागली आणि नंतर अतिवृष्टी होऊन नुकसान झाले आणि त्याचे पंचनामे होऊन 50 टक्क्यांच्या वर हे नुकसान झाले असेल तर त्याबाबतीत शासनाने मदत जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त आपण केलेल्या सूचना तपासून निर्णय घेतला जाईल.

(विरोधी पक्षाचे माननीय सदस्य बोलत असतात)

सभापती : मंत्री महोदयांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्यांच्या ज्या अडचणी व सूचना आहेत त्यासंदर्भात आपण आपल्या दालनात त्यांची एक बैठक आयोजित करावी व तातडीने हा प्रश्न कसा सुटेल यावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा.

प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे.

....2

पृ.शी./मु.शी.: औचित्याचे मुद्दे

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. रमेश शेंडगे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

श्री. रमेश शेंडगे : महोदय, मी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून एका गंभीर विषयाकडे आपल्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करित आहे. तो मुद्दा असा आहे की, आज सकाळी विधान भवनात प्रवेश करित असताना माझी बॅग माझ्या स्वीय सहायकाकडे होती. आत येताना मेटल डिटेक्टर मशिनमधून त्या बॅगेची तपासणी केल्यामुळे स्वीय सहायकाला येण्यास उशीर झाला. मी त्याला उशीर का लागला म्हणून विचारणा केली असता त्याने सांगितले की, मेटल डिटेक्टर मशिनमध्ये आपल्या बॅगेत रिव्हॉल्वर असल्याचा संशय आला म्हणून बॅगेची तपासणी करण्यासाठी उशीर झाला. त्यासंदर्भात मी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्यासाठी गेलो असता मला असे सांगण्यात आले की, कोणाच्या बॅगेत हत्यार वगैरे असेल, रिव्हॉल्वर वगैरे असेल तर ते दिसण्याची सोय या मशिनमध्ये केलेली आहे. अशा प्रकारचे हत्यार दिसून आले तर आम्ही ती बॅग तपासतो, अशी या मशिनमध्ये सोय केलेली आहे. वास्तविक अशा प्रकारे तपासणी करून बॅगेत रिव्हॉल्वर असल्याचे मशिनमध्ये दिसून आले आणि त्याचा वर्तमानपत्रात दुसऱ्या दिवशी फोटो छापून आला तर त्या आमदाराची बदनामी होऊन त्याला घरी गेल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. यासंदर्भात मी सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडे जाऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मला सांगितले की, बॅगेची तपासणी करण्यासाठी जे सुरक्षा रक्षक बसलेले असतात ते सतर्क आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी ही सोय केलेली आहे. पण अशी सोय करून एखाद्या आमदारावर बदनामीची वेळ येऊ शकते, त्यादृष्टीने ही बाब योग्य नाही. त्याची आपण तपासणी करून घ्यावी, अशी माझी विनंती आहे.

सभापती : यासंदर्भात मी मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना जरूर देईन. पण त्याचबरोबर या सभागृहात येत असताना प्रत्येकाची सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तपासणी होणे हे देखील अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या बाबतीत जो प्रश्न निर्माण झाला ती बाब मी स्वतः सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेईन व आपल्याला तसे कळविण्यात येईल.

यानंतर श्री. जुन्नरे

हरकतीच्या मुद्याबाबत

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी सुरक्षारक्षकांच्या संदर्भात जे वक्तव्य केलेले आहे ते चूक आहे असे माझे म्हणणे नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्या प्रमाणे आपले सुरक्षा अधिकारी सतर्कता ठेवत आहेत असे दिसते. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचे कौतुक करण्यास काहीच हरकत नाही एवढ्यापुरताच माझा हरकतीचा मुद्दा होता.

...2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ.शी./मु.शी.: अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचा अहवाल सादर करणे व संमत करणे.

श्री. दीपकराव साळुंखे (समिती प्रमुख) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचा अहवाल सभागृहाला सादर करतो.

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 रोजीच्या कामकाजाच्या क्रमात दाखविण्यात येणा-या अशाकीय ठरावांना द्यावयाचा वेळ ठरविण्याकरिता गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 रोजी समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजासाठी एकूण 150 मिनीटांचा वेळ उपलब्ध आहे. अशासकीय ठरावांना खालीलप्रमाणे वेळ देण्यात यावा अशी शिफारस समितीने केली आहे.

गतसत्रातील पुढे ढकलण्यात आलेला अशासकीय ठराव

- 1) श्री. दिवाकर रावते, वि.प.स. यांचा ठराव क्रमांक 80- 40 मिनीटांपेक्षा जास्त नाही.
- 2)

बॅलेटद्वारा ठरविलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार अशासकीय ठराव

- 1) डॉ. सुधीर तांबे, वि.प.स. यांचा ठराव क्रमांक 99 -40 मिनीटांपेक्षा जास्त नाही.
- 2) डॉ. नीलम गोन्हे, वि.प.स. यांचा ठराव क्रमांक 18 -35 मिनीटांपेक्षा जास्त नाही.
- 3) डॉ. दीपक सावंत, वि. प. स. यांचा ठराव क्रमांक 22 -35 मिनीटांपेक्षा जास्त नाही.

यापैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्यापुढील क्रमांकाच्या ठरावास देण्यात यावा, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.

सभापती : अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचा अहवाल सभागृहास सादर झाला आहे.

श्री. दीपकराव साळुंखे (समिती प्रमुख) : सभापती महोदय, अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचा अहवाल सभागृहाला संमत आहे, असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो.

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला.

--

..3..

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे. गंभीर विषय असा आहे की, महाराष्ट्रातील एक जवान आसाम मध्ये शहीद झालेला आहे. सातारा जिल्ह्यातील कवठे तालुक्यातील भुईज वाई या ठिकाणचा प्रवीण ढेरे हा जवान 11 मार्च, 2011 रोजी आसाम येथील सुरंग स्फोटात ठार झालेला आहे. त्यांचा मृतदेह बुधवारी घरी येईल असे सैन्य दलाकडून सांगण्यात आल्यामुळे सर्व प्रकरची तयारी करण्यात आली होती परंतु संबंधित जवानाचा मृतदेह अद्याप पर्यंत आलेला नसल्यामुळे संपूर्ण गावात असंतोष आणि संतापाचे वातावरण पसरलेले आहे. काल या ठिकाणी रस्ता रोको सुध्दा झाला होता. ही सर्व माहिती दूरदर्शन वरून दाखवण्यात आली होती. जवानाच्या मृतदेहाची अशा प्रकारे विटंबना झाल्यामुळे जनमाणसात तीव्र संताप निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे माझी आपल्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रात काम केलेले आहे त्यामुळे त्यांनी त्यांचा अधिकार वापरून सदर शहीद जवानाचा मृतदेह तातडीने घरी कसा पोहचेल याची व्यवस्था करावी एवढेच मला औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून सांगावयाचे होते.

सभापती : सन्माननीय महसूल मंत्री येथे उपस्थित असल्यामुळे मी त्यांना सांगू इच्छितो की, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय महत्वाचा असून तो शहीद जवानाच्या बाबतीतील आहे. त्यामुळे या विषयाच्या बाबतीत आपण केंद्रीय संरक्षण मंत्र्याकडे चौकशी करून सदर शहीद जवानाचा मृतदेह तातडीने साता-यात कसा येईल या दृष्टीने शासनाने जरूर ते प्रयत्न करावेत.

तसेच जिल्हाधिका-यांनी सुध्दा या शहीद जवानाचा शासकीय इतमामाने अंतिम संस्कार कसा होईल ते पहावे.

श्री. बाळसाहेब थोरात : ठीक आहे.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

पु.शी./मु.शी. : नियम 93 अन्वये सूचना

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी "पंचायत समिती मानोरा, जि.वाशिम येथील गट शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्यामुळे पंचायत समितीचे सभापती, उप सभापती व समिती सदस्य यांनी जिल्हा परिषद,वाशिम कार्यालया समोर दिनांक 18 मार्च,2011 रोजी उपोषणास बसण्याचा घेतलेला निर्णय " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य श्री परशुराम उपरकर यांनी "मौजे कल्याण, तालुका अंधेरी येथील ए.एच.वाडिया या ट्रस्टच्या मालकीची जमीन शासनाने सामाजिक उपक्रमासाठी नाममात्र रकमेला दिली असतांना या ट्रस्टने विविध कंपन्या व विकासाकांना व्यापारी तत्वावर विकणे " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री रामनाथ मोते, भगवान साळुंखे,संजय केळकर, विनोद तावडे, चद्रकांत पाटील यांनी " माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळाच्या हलगर्जीपणामुळे दहावी व बारावीच्या परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, विनोद तावडे, रामनाथ मोते यांनी " ठाणे जिल्हयाचा विस्तार व मोठया प्रमाणात होणारे नागरीकरण विचारात घेऊन ठाणे जिल्हयाची विभागणी करण्याची नितांत आवश्यकता "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी "टागोर नगर, विक्रोळी, मुंबई येथील बैठया चाळीचे पुनर्विकास करण्याकरिता मल्टीपल ऑप्शन्स यांच्याद्वारे निविदा मागविण्याच्या प्रकरणात म्हाडा रहिवाशांची झालेली फसवणूक " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे

तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्या डॉ नीलम गो-हे यांनी " पुणे शहरातील हडपसर येथील अमनोरा पार्क टारुनमध्ये पवार पब्लिक स्कूलच्या बसमधून साडे तीन वर्षाचा मुलगा पडून चाकाखाली चिरडून मुलाचा झालेला मृत्यू "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे ,भगवानराव साळुंखे,धनंजय मुंडे यांनी " दिनांक 13.12.2011 रोजी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेच्या वेळी झालेला गोंधळ, उमेदवाराच्या नावासमोर वेगळीच छायाचित्रे असणे, ठाण्यात प्रश्न पत्रिका संच बदलणे, अनुक्रमांक बदलणे इत्यादी झालेले प्रकार "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री विनोद तावडे, रामनाथ मोते संजय केळकर, चंद्रकांत पाटील यांनी " जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात काम करणा-या प्रगणकांसाठी केन्द्र सरकारने मुंबई महापालिकेतील आवश्यक तो निधी जमा केला असताना देखील त्यांना तो अद्याप न मिळणे "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य डॉ दीपक सावंत यांनी "सेंट जॉर्जेस रुग्णालयाचे मेडीकल सुपरिटेन्डन्ट डॉ. चंद्रकांत गायकवाड यांनी गरीब रुग्णाचा निधी स्वतःच्या खाजगी कामासाठी वापरणे परिणामी गरीब रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणे तर काही दगावणे "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य श्री पांडुरंग फुंडकर यांनी " वर्णा ,तालुका खामगाव, जिल्हा बुलढाणा येथील महाजल योजनेअंतर्गत जुन्या विहिरीचा खर्च रु 5 लाख 55 हजार 583 एवढा दाखविण्यात येणे या योजनेत झालेला भ्रष्टाचार संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

या नंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री गोपीकिसन बाजोरिया, दिवाकर रावते, किशनचंद तेनवाणी यांनी " वाशिम जिल्हयाचा विकास आराखडा मंजूर होऊन 22 वर्षे झाली तरी त्यावर कोणतीही कार्यवाही न होणे " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

अन्य नियम 93 च्या सूचनांना माझ्या दालनात मी अनुमती नाकारली आहे.

लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्या संबंधी

सभापती : आजच्या कामकाजपत्रिकेमध्ये दाखविण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना आज होणार नाहीत या लक्षवेधी सूचना लॅप्स न करता नंतर जरूर घेण्यात येतील. त्याचबरोबर आज विशेष उल्लेख देखील घेण्यात येणार नाहीत. आता माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सुरुवात करू या.

नंतर श्री.सरफरे

पृ.शी.: राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा

मु.शी.: राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दलच्या आभारप्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर चर्चा

सभापती : राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभारप्रदर्शनाचा प्रस्ताव श्री.अशोक उर्फ भाई जगताप, वि.प.स. यांनी मांडला असून श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. यांनी अनुमोदन दिले आहे. सदरहू प्रस्ताव प्रस्तुत झालेला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेकरिता आज गुरुवार, दिनांक 17 मार्च व शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराचा एक तास धरून सात तास चर्चेकरिता उपलब्ध आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरादाखल भाषणाचा एक तास सोडून उर्वरित सहा तासांचा वेळ सदस्यांना भाषणाकरिता उपलब्ध राहिल. प्रस्तावकांना 15 मिनिटे देण्यात येतील आणि प्रस्तावाला पाठिंबा देणारे अनुमोदक 10 मिनिटे भाषण करतील. तसेच विरोधी पक्षनेत्यांच्या भाषणासाठी 20 ते 30 मिनिटे देण्यात येतील. ज्या सन्माननीय सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यावयाचा आहे त्यांनी आपली नावे आपल्या पक्ष प्रतीदामार्फत माझ्याकडे 10 मिनिटात पाठवावीत. नावे प्राप्त झाल्यानंतर वेळेचे बंधन घालावे काय, याचा विचार करता येईल.

या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावास सदस्यांकडून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. सुधारणांची एकत्रित यादी माननीय सदस्यांना मिळाली आहे असे मी समजतो. तसेच माननीय सदस्यांना सुधारणा मांडावयाच्या नाहीत असेही मी समजतो.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आपण आता माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी जे निदेश दिले आहेत त्याबाबत मला एकच विनंती करावयाची आहे. या सभागृहामध्ये मागण्यांवरील चर्चेच्या माध्यमातून आम्ही जे प्रश्न उपस्थित करतो त्याची उत्तरे मंत्री महोदयांकडून मिळत नाहीत आणि मग या सभागृहामध्ये उशीर झालेला असतो म्हणून घाई-घाईत मागण्या मंजूर कराव्यात अशी विनंती करून त्या मंजूर केल्या जातात. या सभागृहामध्ये आम्ही तासनतास बसून चर्चेच्या माध्यमातून विषय मांडतो त्यावर शासनाकडून उत्तरे येणे अपेक्षित आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की, आम्ही मांडलेल्या विषयाची नोंद घेतली पाहिजे. आज विधानसभेचे सभागृह बंद आहे. खालच्या सभागृहामध्ये जायचे आहे अशा प्रकारची प्रत्येक वेळी मंत्री महोदयांकडून कारणे सांगितली जातात आणि आमची दिशाभूल केली जाते. प्रत्येक वेळी आम्ही त्यांची विनंती मान्य कां करावी? कृपा करून आपण या सभागृहाची गरिमा खतम करू नका.

श्री. भाई जगताप : गरिमा कायम आहे...

श्री. दिवाकर रावते : नाही तर आम्ही प्रत्येक मागण्यांच्या वेळी "पोल" मागू. ही पध्दत योग्य नाही. आज विधानसभेचे कामकाज स्थगित झाले आहे. त्यामुळे या सभागृहामध्ये संबंधित राज्यमंत्र्यांनी येऊन बसले पाहिजे.

श्री. भाई जगताप : संबंधित कॅबिनेट मंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत.

श्री. दिवाकर रावते : मी याठिकाणी कॅबिनेट मंत्र्यांचा विषय मांडलेला नाही, आपण मला समजून घेतले पाहिजे.

सभापती : माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केलेला विषय योग्य आहे असे मला वाटते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे विधानसभेचे आजचे कामकाज स्थगित झाले आहे. त्यामुळे याठिकाणी होणाऱ्या चर्चेच्या अनुषंगाने संबंधित मंत्री किंवा राज्यमंत्री उपस्थित राहिले तर त्यांना उत्तर देणे सुकर होईल. त्यादृष्टीने माननीय सदस्यांनी सूचना केली आहे.

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, मी मुद्दे लिहून घेणार आहे त्यामुळे आपण चर्चेला सुरुवात करावी अशी मी विनंती करते.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, सभागृहामध्ये अनेक विषयांशी संबंधित चर्चा होणार आहे, अनेक खात्याच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. एखादा विषय याठिकाणी उपस्थित झाला आणि संबंधित मंत्री जर अनुपस्थित असतील तर त्या प्रश्नाला आपण उत्तर देणार आहात काय? आपण जर उत्तर देणार नसाल तर विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी सभागृहामध्ये उपस्थित असले पाहिजे. आज याठिकाणी कृषी मंत्री उपस्थित नाहीत, आम्हाला शेतकऱ्यांच्या विषयासंबंधी फार मोठा प्रश्न उपस्थित करावयाचा असेल तर त्याला उत्तर कोण देणार आहे?

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

RR-1

APR/ D/ MMP/

पूर्वी श्री.सरफरे . . .

15:40

सभापती : आपल्या सदनामध्ये आजच्या चर्चेच्या अनुषंगाने संबंधित माननीय कॅबिनेट मंत्री किंवा माननीय राज्यमंत्री उपस्थित रहातील यादृष्टीने त्यांना निरोप देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.चरणसिंग सप्रा यांनी लक्ष द्यावे.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माननीय कॅबिनेट मंत्री प्रा.(श्रीमती) वर्षा गायकवाड यांनी असे सांगू नये की, मी येथे उपस्थित आहे आणि मी सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणातील सगळे मुद्दे लिहून घेत आहे. ही आपली जबाबदारी नाही.

सभापती : तसे होणार नाही.

सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप यांनी आपला प्रस्ताव मांडावा.

. . . .2 आर-2

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

RR-2

श्री.भाई जगताप (मुंबई स्थानिक प्राधिकारी संस्था) :सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, हे आभार व्यक्त करीत असताना माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये हे वर्ष विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे काही दिशानिर्देश दिलेले आहेत आणि हे दिशानिर्देश देत असताना, त्याबाबत मी जर असे म्हटले की,

(अनेक सन्माननीय सदस्य खाली बसून एकदम बोलतात.)

सभापती महोदय, काही अडचण आहे काय ? आपण आम्हाला संरक्षण द्यावे.

सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी माझ्याकडे पाहून बोलल्यानंतर त्यांना निम्मे संरक्षण मिळेल.

श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, भाईचा आवाज एवढा मोठा आहे की, तो तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर आवाज तरी येतो. विधिमंडळाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने माननीय राज्यपालांनी येणाऱ्या वर्षभरामध्ये विकासाचा मार्ग काय असावा, त्याची दिशा काय असावी यादृष्टीने एक दिशादर्शक अभिभाषण केलेले आहे असे मी म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होऊ नये. याचे कारण असे की, या अभिभाषणामध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टी, ऐतिहासिक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. मानव विकास निर्देशांकाच्या आधारावर जिल्ह्यांचा गुणक्रम ठरविण्याच्या संबंधातील पध्दत यापूर्वी कधीही नव्हती. आपण याठिकाणी विकासाच्या बाबतीत, मागासलेल्या जिल्ह्यांच्या विकासा बाबत चर्चा करतो. मग ते नक्षलग्रस्त जिल्हे असतील किंवा डोंगरी विभाग असेल आणि राज्यामध्ये असे अनेक जिल्हे आहेत की जे मागासलेलेच राहिले आहेत. याबाबतीत सदनामध्ये अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. म्हणून मानव विकास निर्देशांकाच्या आधारावर जिल्ह्यांचा गुणक्रम ठरविण्याची एक अभिनव संकल्पना अभिभाषणाच्या माध्यमातून माननीय राज्यपालांनी विदित केलेली आहे.

सभापती महोदय, अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये आपल्या सर्वांच्या निदर्शनास एक गोष्ट येते की, प्रादेशिक असमतोलाबाबत दोन्ही सभागृहामध्ये भाषणे झाली आणि वर्षभराच्या काळामध्ये विधानसभेची जी तीन अधिवेशने होतात, त्यावेळी या विषयाबाबत अनेक वेळा चर्चा होते. पण याबाबतीत नेमके काय केले पाहिजे यादृष्टीने माननीय विरोधी पक्षनेत्यांकडून किंवा विरोधी बाकावरील सन्माननीय सदस्यांकडून, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य किंवा सत्ताधारी बाकावरील

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

RR-3

APR/ D/ MMP/

15:40

श्री.भाई जगताप

सन्माननीय सदस्यांकडून कित्येक वेळेला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. पण त्याबाबत किती अंमलबजावणी केली जाते याविषयी नेहमीच आम्ही सर्वजण शंका उपस्थित करित असतो.

(सभापतीस्थानी - माननीय उप सभापती)

यानंतर कु.थोरात

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. भाई जगताप....

प्रादेशिक असमतोलाच्या दृष्टीने अनुशेष असेल किंवा विकास खर्चाचे समान वितरण असेल या दोन्ही महत्वांच्या गोष्टींसाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा प्रकारचे निर्देश माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिले आहेत, ते खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहेत. आतापर्यंत विदर्भाच्या बँकलॉगच्या संदर्भात, नक्षलग्रस्त भागाच्या बँकलॉगच्या संदर्भात, आदिवासी विकास विभागाच्या बँकलॉगच्या संदर्भात किंवा समाजकल्याण विभागाच्या बँकलॉगच्या संदर्भात या सदनात अनेक वेळा चर्चा करण्यात आलेली आहे. परंतु समतोल विकास कसा करावा यादृष्टीने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे ऐतिहासिक निर्देश देण्याचे काम माननीय राज्यपालांनी केलेले आहे म्हणून मी या ठिकाणी माननीय राज्यपालांचे मनापासून आभार मानतो.

सभापती महोदय, डी.पी.डी.सी. हा विकासाचा आत्मा आहे. एकेकाळी या देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये प्रशासन मंत्रालयांतून चालत होते परंतु सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले. विकास अती गतीशील होण्याच्या दृष्टीकोनातून अर्थात डी.पी.डी.सी. तेव्हाही होती पण डी.पी.डी.सी.ला तेवढे अधिकार नव्हते. त्यानंतर डी.पी.डी.सी.ला अधिकार देण्यात आले. डी.पी.डी.सी.मुळे त्या त्या विभागातील आणि जिल्ह्यातील कारभाराला व विकास कामाला गती मिळाली. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात "विकास कार्यांच्या विकेंद्रीत अंमलबजावणीच्या उत्साहवर्धक अनुभवातून शासनाने मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 53 टक्के इतकी वाढ करून जिल्हा योजना 2010 करिता 3828 कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत." असे म्हटले आहे. ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांचे स्वागत केलेच पाहिजे. आम्ही ज्यावेळी एखाद्या गावातील पाणी पुरवठ्याचा, तेथील आरोग्याचा विचार करतो त्यावेळी त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणला जाणार आहे? सत्तेचे विकेंद्रीकरण या माध्यमातून सत्ता गरिबांपर्यंत पोहचविण्याची भूमिका शासनाने घेतली त्या दृष्टीने हा एक रोडमॅप आहे, असे मी म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. आज जवळ जवळ 3828 कोटी रुपयाची प्रोव्हिजन डी.पी.डी.सी.च्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे त्याबद्दल मी मनापासून शासनाचे आणि माननीय राज्यपालांचे आभार व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, जिल्हा विकास योजनेच्या बाबतीत आणखी एक नवीन बाब आपल्या सगळ्यांच्या निदर्शनास येते. नियतव्यय जितका असेल त्यापैकी 4.5 टक्के इतका निधी नावीन्यपूर्ण

..2..

श्री. भाई जगताप.....

योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. हे अतिशय महत्वाचे आहे, याचे कारण असे की, अर्थसंकल्पावर साधक-बाधक चर्चा झाल्यानंतर अर्थसंकल्प पारित झाल्यानंतर परिस्थितीनुसार वर्षभरामध्ये अनेक नवीन योजना तयार होतात परंतु त्या योजनांसाठी नियतव्यय मिळत नाही याकरिता एक नवीन सुरुवात या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुरु झालेली आहे. 4.5 टक्के नियतव्यय हा या नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी वापरला जाणार आहे. म्हणून मी शासनाचे आणि माननीय राज्यपालांचे सुध्दा आभार व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, गडचिरोली, गोंदिया या सारख्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाने तयार केलेली एकात्मिक कृती योजना राबविण्यात येणार आहेच पण "वनक्षेत्र परिसरातील नक्षलवादी कारवाया सक्षमतेने हाताळण्यासाठी पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण देण्याकरिता नागपूर येथे "अल्फा हॉक अकादमी" कार्यान्वित करण्यात येत आहे." ही काळाची गरज आहे. नक्षलवादी कारवाया दुर्दैवाने वाढलेल्या आहेत. आतंकवादी कारवायांच्या बरोबरच नक्षलवादी कारवायांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही पण या नक्षलवादी कारवाया थांबविणार कशा? आपल्याकडे अशी एक म्हण होती की, कोणाला जर शिक्षा द्यावयाची असेल तर त्याला गडचिरोलीला पाठवा. नक्षलग्रस्त भागात पाठवा, अशा प्रकारची खऱ्या अर्थाने ती वाईट म्हण होती पण ती दुर्दैवाने या महाराष्ट्रात प्रचलित झाली. तेथे जाणारा जो पोलीस आहे तोही माणूस आहे. त्याच्यामागे त्याचे कुटुंब आहे.

यानंतर श्री. बरवड....

श्री. भाई जगताप

त्या ठिकाणी अनेक पोलीस शहीद झालेले आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज होती. कारण त्या ठिकाणी प्रशिक्षित फोर्स गेला तर नक्षलवादी कारवायांना कोठे तरी आळा घालण्याच्या दृष्टीने मदत होऊ शकेल. त्यामुळे नागपूर येथे 'अल्फा हॉक अकादमी' कार्यान्वित करण्यात आली आहे त्याबद्दल मी शासनाचे आभार व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, अलीकडच्या काळामध्ये देशात झालेले आतंकवादी हल्ले असतील किंवा देशाच्या लोकसभेवर झालेला हल्ला असेल किंवा मुंबईवर झालेला 26/11 चा हल्ला असेल, अशा प्रकारच्या आतंकवादी कारवाया वाढलेल्या आहेत. या कारवाया करण्यासाठी त्यांनी काही विशिष्ट ठिकाणे निवडलेली आहेत की काय अशी शंका मनामध्ये तयार झालेली आहे. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आणि या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला झाल्यानंतर शासनाने काही पावले उचलली होती आणि सागरी किनारा सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीने मुंबईमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये 12 सागरी पोलीस ठाणी व 32 तपासणी चौक्या कार्यान्वित केल्या होत्या. आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 7 अतिरिक्त पोलीस ठाणी आणि त्या पोलीस ठाण्यांच्या दिमतीला गस्तीसाठी 57 नौका शासन उपलब्ध करून देणार आहे. त्यापैकी 28 नौका प्राप्त झालेल्या आहेत. मला मुद्दाम सांगावेसे वाटते की, आपल्या महाराष्ट्राला जवळजवळ 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. पण दुर्दैवाने यापूर्वी जे आरडीएक्स उतरले ते शेखाडीच्या किनाऱ्यावर उतरले तसेच मुंबईवर जो आतंकवादी हल्ला झाला तो किनाऱ्यावरून झाला. त्या दृष्टीने अशी उपाययोजना करणे ही काळाची गरज होती. म्हणून शासनाने पहिल्या टप्प्यामध्ये काही पावले उचलली आणि आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांना आवश्यक असणारी यंत्रणा किंवा इन्फ्रॉस्ट्रक्चर मग त्यामध्ये नौका असतील, पोलीस ठाणी असतील, त्यांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण असेल, या सगळ्या बाबतीत माननीय राज्यपालांनी या अभिभाषणामध्ये निर्देश दिलेले आहेत. म्हणून मी म्हटले की, हे अभिभाषण पथदर्शक झालेले आहे. म्हणून मी माननीय राज्यपालांचे या सभागृहाच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, शासनाने रायगड जिल्ह्यामध्ये सागरी पोलीस प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. पोलीस प्रशिक्षण आणि विशेषतः सागरी पोलीस प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

RDB/ MMP/ D/

श्री. भाई जगताप

कारण हे विशेष प्रकारचे काम आहे. नक्षलवादी भागामध्ये आमच्या पोलिसांनी कशा प्रकारे सुरक्षा केली पाहिजे याचे पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नागपूर येथे जशी 'अल्फा हॉक अकादमी' कार्यान्वित केली त्या पध्दतीने पोलिसांना जे सागरी प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक होते त्यासाठी रायगड जिल्ह्यामध्ये सागरी पोलीस प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. आपण नेहमी उल्लेख करतो की, महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभलेला आहे. त्या ठिकाणी मच्छिमार बांधव पिढ्यानपिढ्या आपला उदरनिर्वाह करतात. सुरक्षितेसाठी उपाययोजना करित असताना त्यांना जर त्यापासून वंचित ठेवले तर त्या मच्छिमार समाजावर अन्याय होईल. त्यामुळे सुरक्षितेच्या दृष्टीने त्यांना आयडेंटिफाय करण्यासाठी तेथील 75 हजार 558 मच्छिमारांना आतापर्यंत स्मार्ट कार्ड देण्यात आलेली आहेत. जोपर्यंत त्यांना या टीममध्ये समाविष्ट करित नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने आपल्याला तिकडच्या कारवायांचा अजिबात थांगपत्ता लागणार नाही. ज्या ठिकाणी कसाब आणि त्यांचे साथीदार उतरले त्यावेळी तेथील स्थानिक लोकांनी त्याबाबतीत काही गोष्टी पोलिसांना कळविल्या. परंतु दुर्दैवाने त्या गोष्टींचा तितकासा अंदाज घेता आला नाही आणि त्यामुळे पुढे घडलेला दुर्दैवी प्रसंग आपणा सर्वांना माहित आहे. असे प्रसंग मुंबईवर, महाराष्ट्रावर आणि आपल्या देशावर येऊ नयेत म्हणून या गोष्टीची नोंद घेऊन शासनाने पावले उचलली आणि 75 हजार 558 मच्छिमारांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आली. यापुढे अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्या आणि त्या बाबत त्यांनी पोलिसांपर्यंत माहिती पाहोचविली तर आपल्याला त्या बाबतीत काही तरी नियंत्रण करता येईल किंवा सावधगिरीच्या उपाययोजना करता येतील.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.भाई जगताप.....

आपल्याकडे 720 कि.मी.इतका समुद्र किनारा आहे, त्याचे आपण संरक्षण कसे करणार आहोत ? केवळ 58 बोटी घेऊन किंवा 29 बोटी घेऊन होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे आहे. शासनाने 22,946 मच्छिमार बोटी व 1,434 बिगर मच्छिमार बोटींची नोंदणी केलेली आहे. या बोटींची नोंदणी केली असल्यामुळे जर एखादी अनोळखी बोट समुद्रात आली तर ती ताबडतोब लक्षात येईल आणि त्याबाबत आपल्याला काळजी घेता येईल.

सभापती महोदय, 'महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव' या योजनेने राज्यात नव्हे तर देशात एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. राज्यामध्ये अनेक खटले 10 वर्षांपासून, 15 वर्षांपासून, 20 वर्षांपासून प्रलंबित रहात होते. संबंधित गावातील लोकांना, शेतकऱ्यांना त्यांचे वय झाले तरी कोर्टात सातत्याने जावे लागत होते. माणूस म्हातारा झाला तरी त्याला कोर्टात चकरा माराव्या लागत होत्या. आपल्या देशाची संस्कृती अशी आहे की, झाडाच्या पारावर बसून न्यायनिवाडा दिला जात होता. त्याप्रमाणे ही तंटामुक्त गाव योजनेची संकल्पना आहे. ही योजना राज्यात चांगल्याप्रकारे राबविली गेली. त्यामुळे मला शासनाचे अभिनंदन करावयाचे आहे. या योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षात अनुक्रमे 2,325 व 2,891 गावे तंटामुक्त गावे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. जवळजवळ 5,500 गावे तंटामुक्त म्हणून घोषित झालेली आहेत, एवढी मोठी कामगिरी या योजनेमुळे झाली आहे. या योजनेच्या तिसऱ्या वर्षात 4,247 गावे तंटामुक्त गावे म्हणून घोषित करण्यात आली असून यापैकी 360 गावे 'विशेष शांतता पुरस्कारासाठी' पात्र ठरली आहेत. हे या योजनेमुळे साध्य झालेले आहे. राज्यामध्ये कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे हे महत्वाचे नाही. या महाराष्ट्रातील प्रत्येक निर्णयाकडे संपूर्ण देश पहात असतो. आज जी गावे 'विशेष शांतता पुरस्कारासाठी' पात्र ठरली आहेत ती अभिनंदनास पात्र आहेत. त्या गावातील सरपंच, तेथील यंत्रणांचे मला अभिनंदन केले पाहिजे. अशाप्रकारच्या गावांमध्ये जास्तीत जास्त वाढ व्हावी अशी इच्छा मी व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, राज्यातील बंदरांचा विकास करण्याचा महत्वाचा विषय या अभिभाषणामध्ये आलेला आहे. राज्यातील बंदरांचा विकास करावयाचा असला तरी सरकारकडे

2...

श्री.भाई जगताप.....

मर्यादित निधी आहे. राज्यातील 720 कि.मी.वरील बंदरे या अपुन्या निधीतून विकसित होणे अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाने खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन बंदर धोरण जाहीर केले आहे. त्यासाठी 827 कोटी रुपयांच्या 'शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पाला' शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत पाटील यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील एक जेष्टी अत्याधुनिक पध्दतीने विकसित केलेली आहे. त्यामुळे मी त्यांचे कौतुक करतो. त्याप्रमाणे शासनाने बंदरे विकसित करण्याचे ठरविले, ईप्सित साध्य करण्याचे ठरविले तर या कामासाठी मोठी मदत होईल.

सभापती महोदय, ज्यावेळी राज्याच्या तसेच देशाच्या विकासाची संकल्पना म्हणतो त्यावेळी शेतकरी, कष्टकरी व इतर नागरिक यांच्याशिवाय विकास होऊ शकत नाही. मागील 2-3 वर्षांपासून भारतामध्ये सगळ्यात जास्त दुर्दैवी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. या सत्यापासून तुम्हा आम्हाला दूर जाता येणार नाही. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने मदत केलेली आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने 72 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे, त्याबद्दलही दुमत नाही. भविष्यातही अशा प्रकारची योजना शासनाला करावी लागेल. त्या योजनांचा मार्गदर्शक तक्ता या अभिभाषणामध्ये आलेला आहे, म्हणून मी माननीय राज्यपालांचे आभार व्यक्त करतो.

यानंतर श्री.शिगम.....

या तक्त्याच्या अनुषंगाने जोपर्यंत शेतक-यांना आपण अधिक काही देणार नाही तोपर्यंत शेतक-याला दिलासा मिळणार नाही. सिंचनासाठी 7919 कोटी रुपये दिलेले आहेत. आजपर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प मांडण्यात आले त्यातील कोणत्याही अर्थसंकल्पामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी दिल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. म्हणून मी या शासनाचे मनापासून आभार व्यक्त करीत आहे. सभापती महोदय, जो प्रश्न आपणा सर्वांना नेहमी मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थ करीत असतो, जो बळीराज्याचा प्रश्न आहे, दोन्ही सभागृहामध्ये ज्या प्रश्नावर सातत्याने चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातात त्यावर शाश्वत अशा प्रकारची उपयायोजन करणे गरजेचे होते म्हणून या प्रश्नाला प्राधान्य दिले गेले आहे. सिंचनासाठी 7919 कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यामुळे जवळ जवळ 1.75 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सभापती महोदय, या ठिकाणी बळीराज्याच्या बाबतीत, शेतक-यांच्या बाबतीत, कष्टक-यांच्या बाबतीत नेहमी बोलले जाते. मला आणखी एका गोष्टीकडे या सभागृहाचे लक्ष आकर्षित करावयाचे आहे. या सभागृहामध्ये कित्येक वेळा असा प्रश्न विचारला जातो की, केन्द्रामध्ये तुमचे सरकार असताना तुम्ही काय दिले ? मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की, केन्द्राकडून गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत 8039 कोटी रुपये इतके सहाय्य प्राप्त झालेले आहे. या देशात केन्द्राने इतका निधी कोणत्याही राज्याला दिलेला नाही. त्यासाठी मी राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आणि माननीय राज्यपालांचे मनापासून आभार मानतो. सभापती महोदय, मी जेव्हा बळीराज्याचा उल्लेख केला त्यावेळी काही सन्माननीय सदस्य हसले..

श्री. दिवाकर रावते : सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप चांगले भाषण करीत आहेत. त्यांचे भाषण आम्ही शांतपणे ऐकत आहोत. परंतु आम्ही कुणीही हसलो नाही.

श्री. भाई जगताप : मी अपणाबद्दल बोललो नाही. आमच्या सत्ताधारी पक्षाकडील काही सन्माननीय सदस्य हसले...

सभापती महोदय मी सुरुवातीला सांगितल्या प्रमाणे शेतक-यासाठी, कष्टक-यासाठी, सर्वसामान्य जनतेसाठी, विकास कामासाठी एक वर्षभराचा रोडमॅप महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातून मांडलेला आहे. जेव्हा शेतक-यांच्या गोष्टी बोलल्या जातात त्यावेळी काही गोष्टी समजून घेण्याची आवश्यकता असते. भविष्यामध्ये सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी,

..2..

श्री. भाई जगताप...

आणखी सुखसोई उपलब्ध होण्यासाठी, शेतक-यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी जे जे काही करणे आवश्यक होते ते सर्व केलेले आहे. अवकाळी पावसासंबंधी या सदनमध्ये लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून चर्चा झाली. त्यावेळी स्वातंत्र्यानंतरच्या 63 वर्षात कधी दिले नाही एवढे 1088 कोटी रुपयाचे पॅकेज देण्यात आले.

...नंतर श्री. गिते...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. भाई जगताप....

माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या सदनात ज्यावेळी पॅकेज जाहीर केले, त्यावेळी काही सन्माननीय सदस्यांकडून शंका उपस्थित केल्या गेल्या. पॅकेजचे पैसे कसे मिळणार, ते पैसे पूर्णपणे मिळणार काय ? अशा स्वरूपाच्या शंका उपस्थित केल्या गेल्या. ज्या शंका उपस्थित केल्या गेल्या त्याबाबतीत दुमत असण्याचे कारण नाही. कोणी त्यापासून वंचित रहावे असा माझा मुळीच उद्देश नाही. 1 हजार 88 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून त्याचे वाटप 31 मार्च, 2011 च्या आत झाले याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. बऱ्याच वेळा शासनाकडून पॅकेजेस जाहीर केले जातात, परंतु त्याचा निधी मात्र उपलब्ध होत नाही, निधीचे वाटप त्या प्रमाणात होत नाही असे कधी तरी होत असते. परंतु 1 हजार 88 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून त्याचे वाटप वेळेच्या आत केले व विभागास न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो.

राष्ट्रीय कृषी योजने अंतर्गत शेताततील मातीचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यातील सर्व गावांचा टप्प्याटप्प्याने " गाव सुपीकता निर्देशांक" तयार करण्यासंबंधीची योजना शासनाने हाती घेतलेली आहे. आम्ही शेतांमधून परंपरागत पिके घेत आलेलो आहोत. शेतकरी हा सुशिक्षित आहे, परंतु पूर्ण शिक्षित नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीमध्ये कोणती पिके घेतली पाहिजे, त्यांच्याकडे यंत्रणा नाहीत, जमिनीचा पोत तपासावयाचा असेल, त्यास जमिनीचे संशोधन करावयाचे असेल तर त्यासंबंधी त्यांच्याकडे यंत्रणा उपलब्ध नसते, ही संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या घरांपर्यंत " गाव सुपीकता निर्देशांक" योजना नेण्याचे शासनाने ठरविलेले आहे. हे एक ऐतिहासिक पाऊल शासनाने उचललेले आहे. हरित क्रांती होण्यासाठी शासनाने अशा प्रकारचे पाऊल उचललेले आहे असे म्हटले तर ते अतिशयोक्ती होणार नाही.

मी कोकण विभागातील पिकांच्या संदर्भातील माहिती सांगू शकतो. रत्नागिरीचा हापूस आंबा एवढेच पीक आम्हाला माहिती आहे. तो सुरुवातीला आल्यानंतर तो मार्केटमध्ये 800 रुपये किंमतीने विकला जातो. नंतर मात्र तो आंबा 80 रुपये किंमतीने विकला जातो. आम्हाला याचे एकच कारण माहिती आहे की, दहा आंब्यांची झाडे लावली तर आपल्याला त्याचा फायदा होतो. परंतु ही गोष्ट माहिती नाही की, आंबा पीक हे एक वर्षाआड येत असते. दरवर्षी आंब्याच्या झाडाला आंबे येत नाहीत. आम्हाला आंब्यांचे पिकापासून 1 रुपया उत्पन्न अपेक्षित असते, परंतु आम्हाला फक्त 20

2...

श्री.भाई जगताप...

पैसे उत्पन्न मिळते. खरे तर आंब्याचे पीक हे फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात यावयास पाहिजे.परंतु निसर्गाच्या वातावरणामुळे आंब्याचे पीक मे, जून महिन्यात मिळते. मे आणि जून महिन्यात पाऊस पडतो, त्यामुळे आंबा फळाला कीड लागते, आंबा खराब होतो. पर्यायाने उत्पन्न कमी मिळते आणि म्हणून "गाव सुपीकता निर्देशांक" योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल की, तुमच्या जमिनीत तुम्हाला कोणते पीक घेता येईल. तुम्हाला काय बदल करावा लागेल ही माहिती शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. या ठिकाणी मी फळबागाबद्दल बोललो म्हणून कोणी सदस्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये. फळबागा ह्या नगदी पिकात मोडतात. आपल्याकडे जे ऋतू आहेत, ते शेतकऱ्याला कळावे, कोणत्या ऋतूत कोणती पिके घ्यावीत याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांच्या धरापर्यंत पाहोचविण्यासाठी "गाव सुपीकता निर्देशांक" योजना राबविली जाणार आहे. 2010-11 या वर्षात राज्यातील 43 हजार 711 गावांपैकी 6312 गावांची निवड करण्यात आली असून त्याचा जवळपास 12.94 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यासंदर्भात फक्त जाहिरात केली, घोषणा केली असे नाही. 6312 गावांची निवड करण्यात आलेली आहेत. शेतकरी हा ठराविक कालावधीत ठराविक पिके घेतो. परंतु सध्या नैसर्गिक वातावरणामुळे पिकांवर किडींचा प्रचंड प्रादुर्भाव होत असतो. या किडीमुळे चांगले पीक खराब होते. मी आंब्याचे उदाहरण मुद्दाम दिले. कोकणात आंब्याच्या झाडांना मोहोर मोठ्या प्रमाणात येतो, आम्हाला वाटते की, या वर्षी आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल. परंतु मध्यंतरी पाऊस झाला की, आंब्याचे उत्पादन 20 टक्क्यावर येऊन पोहोचते. म्हणून यासंदर्भात "किडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प" राबवित आहे. कापूस असेल, सोयाबीन असेल, तूर असेल, हरभरा असेल या पिकांवर किडरोगाची लागण होण्यापूर्वीच त्याचा शोध लावून त्यासंदर्भात एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना माहिती कळविण्याचे काम सुरु केलेले आहे असे एतिहासिक काम शासनाने या योजनेच्या माध्यमातून करण्याचे योजले आहे.

यानंतर श्री. भोगले...

श्री.भाई जगताप.....

मी सरकारचे मनापासून आभार मानतो. खऱ्या अर्थाने या कृषीप्रधान देशामध्ये आज जे शहरीकरण वाढत चालले आहे त्यामुळे बळीराजा उपेक्षित राहतो की काय, वंचित राहतो की काय? अशा प्रकारची भावना तुमच्या आमच्या मनामध्ये तयार झाली होती. परंतु माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे अंतर्भूत झालेले आहेत. किड रोग सर्वेक्षण आणि सल्ला प्रकल्प राबविण्याचे पवित्र आणि ऐतिहासिक काम सरकारने हाती घेतले आहे.

सभापती महोदय, मागील वर्षी खतासाठी झालेली आंदोलने, खत वितरणाच्या वेळी शेतकऱ्यांची उडालेली झुंबड, त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार, शेतकऱ्यांवर नोंदविण्यात आलेले गुन्हे या सगळ्यांची जबाबदारी कोणीतरी स्वीकारणे गरजेचे होते. सरकारने ती जबाबदारी स्वीकारून मागील खरीप हंगामामध्ये खतांचा तुटवडा निर्माण होणे आणि खतांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्यात 6 लाख मे.टन खतांचा राखीव साठा निर्माण करण्यात येणार असून जिल्हयातील शेतकऱ्यांना खताचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी जिल्हयांना 15 मे पूर्वी खताच्या राखीव साठ्याचे वितरण करण्याचे निर्देश माननीय राज्यपालांनी दिलेले आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. मागील काळात अनवधानाने ज्या काही चुका झाल्या त्याचा ऊहापोह करून नवीन मार्गदर्शक तत्वे माननीय राज्यपालांनी या अभिभाषणाच्या माध्यमातून तुम्हा आम्हाला घालून दिलेली आहेत.

सभापती महोदय, पीक विमा योजनेबाबत या सभागृहात अनेकदा चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने काही निर्णय देखील घेण्यात आले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर अनेकदा चर्चा झाली. देशातील शेतकऱ्यांना जे कर्जमाफीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले त्याबाबत मोठया प्रमाणात लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये चर्चा झाली. या सदनमध्ये सुध्दा दोन्ही बाजूच्या माननीय सदस्यांनी आपली भूमिका अत्यंत तळमळीने मांडली होती. कित्येकदा असे निदर्शनास आले की, व्याजदराचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबून गेला. शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले ते विचारात घेऊन 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची योग्य वेळेत परतफेड केली तर त्या रक्कमेवर व्याज लागू होणार नाही अशा प्रकारची एक नवीन योजना शासनाने कार्यान्वित करावी अशा प्रकारचे निर्देश माननीय राज्यपालांनी या अभिभाषणात दिले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता 50 हजार ते 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले तर या रक्कमेवर केवळ 2

..2..

श्री.भाई जगताप.....

टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. देशातील कोणत्याही राज्यात नव्हे तर जगामध्ये सुध्दा अशी योजना अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने राज्याला भरीव आर्थिक मदत दिली आहे. 8039 कोटी रुपये केंद्राकडून राज्याला मिळाले आहेत. आतापर्यंत या देशातील कोणत्याच राज्याला एवढी भरीव आर्थिक मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केवळ घोषणा न करता दिशा दिग्दर्शन करण्याचे काम माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणातून केलेले आहे.

नंतर 2वाय.1...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

YY-1

PFK/ KGS/ KTG/

पूर्वी श्री. भोगले.....

16:15

श्री. भाई जगताप

महोदय, कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांच्या संदर्भात मी मुद्दाम सांगू इच्छितो की, मी कामगारांचे नेतृत्व करणारा असल्यामुळे कामगारांना कामगार म्हणण्यापूर्वी त्यांना काम किती मिळणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या सर्व माध्यमातून रोजगार निर्मिती झाली नाही तर या विकासाचे किती कौतुक करावे असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून कापसाच्या बाबतीत सभागृहात अनेक वेळा चर्चा झाल्या, सदस्यांनी आपल्या वेदना मांडल्या आहेत. शासनाने यासंदर्भात एक नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्याच्या माध्यमातून संपूर्ण कापसावर आपल्याच राज्यात प्रक्रिया केली तर जवळपास 10 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळू शकतील. कारण शेवटी विकास कामे, विकास प्रकल्प आणि विकास योजना यांची उद्दिष्ट्ये काय आहेत आणि त्यातून शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या हाताला काम आपण देऊ शकलो नाही तर त्यांचा विकास कसा होऊ शकेल याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हा विचार करूनच 10 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे शासनाने ठरविले आहे.....अडथळा..... बळी राजा ज्याला आपण म्हणतो तो राज्याचा शेतकरी असून त्याच्या फायद्यासाठी एक दिशादर्शक असा निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे. शेवटी हे अभिभाषण म्हणजे नुसता वाक्याचा आणि शब्दाचा खल नसून खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक असे आहे. म्हणून त्यांचे आभार व्यक्त करणे हे आपले सर्वांचे काम आहे. या अभिभाषणाला सुधारणा सुचवावयाच्या असतील तर त्या जरूर सुचवाव्यात पण एखादी नीती बनवित असताना त्यात काही त्रुटी असू शकतील पण नियमामध्ये खोट कधीच नसते. उलट राज्यातील शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठीच या राज्याचे पुरोगामी सरकार विचार करीत आहे. स्वातंत्र्य मिळून 63 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे, त्यापासून आपल्याला दूर जाता येणार नाही. माननीय राज्यपालांचे जे अभिभाषण झाले आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार मी व्यक्त करीत आहे. राज्यातील उद्योगाच्या बाबतीत सुध्दा अनेक गोष्टी या अभिभाषणात दिलेल्या आहेत, त्यांची सविस्तर माहिती देऊन मी सभागृहाचा वेळ घेणार नाही. पण उद्योगाची गुंतवणूक या राज्यात जास्तत जास्त यावी यादृष्टीने शासनाचे नेहमीच प्रयत्न राहिले आहेत. बिहारसारख्या राज्यात श्री. नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाल्यापासून बऱ्याच सुधारणा होत आहेत, त्याबद्दल त्यांचे स्वागत

....2....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

YY-2

PFK/ KGS/ KTG/

पूर्वी श्री. भोगले.....

16:15

श्री. भाई जगताप

करायलाच पाहिजे. आम्ही अनेक वेळा तसे स्वागत केलेले आहे. मी स्वतः उत्तर प्रदेश राज्यात पक्षाचा निरीक्षक म्हणून गेलो आहे.....अडथळा.....

श्री. दिवाकर रावते : आपणास राग आला आणि त्यामुळेच आपण गांधी पध्दतीने बदला घेतला त्याबद्दल आपले मनापासून मी अभिनंदन करतो.

श्री. भाई जगताप : महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या तसेच राज्यातील लाखो लोकांच्या भावना माझ्यापर्यंत पोहचल्या होत्या. त्या व्यक्तिगत भाई जगताप म्हणून नव्हत्या तर एक पक्षाचा नेता म्हणून होत्या. तसेच आपले लोक सुध्दा गेले आणि फिरोजशहा कोटला मैदानाची खेळपट्टी उखडून काढली तेव्हा त्यांच्या भावनांशी आपण सहमत होता. मला इतकेच सांगावयाचे आहे की, ज्या उत्तर प्रदेश राज्याने देशाला सात पंतप्रधान दिले.....अडथळा.....

यानंतर श्री. जुन्नरे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी

श्री. भाई जगताप...

सभापती महोदय, ज्या उत्तर प्रदेश राज्याने आपल्या देशाला 7-7 पंतप्रधान दिले त्या राज्याच्या शेतक-यांची आजची अवस्था फार भयावह आहे.

श्री. दिवाकर रावते : सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी उत्तर प्रदेश राज्याने 7-7 पंतप्रधान दिले होते परंतु आज त्या राज्यातील शेतक-यांची अवस्था फार भयावह आहे अशी माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे मला असे वाटते की, बरे झाले आपल्या महाराष्ट्र राज्याने देशाला पंतप्रधान दिले नाहीत अन्यथा आपल्या राज्याची अवस्था त्यांच्याहीपेक्षा वाईट असती.

श्री. भाई जगताप : सभापती महोदय, जर महाराष्ट्रातील कै. यशवंतराव चव्हाणांना पंतप्रधान पद मिळाले असते तर आज आपल्या राज्याचे जे चित्र आहे ते चित्र दहा पटीने सुधारले असते एवढेच मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे. (अडथळा) एक गोष्ट आपल्याला विसरून चालणार नाही की, या देशाला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले होते तेव्हा एक तिरंगा व एक संसद यापेक्षा आपल्या देशाकडे काहीही नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली 25 वर्षे नवनवलाईची गेली. या देशात स्वातंत्र्यानंतर जी साधने तयार केली गेली ती कै.पंडित जवाहरलाल नेहरू, कै. इंदिरा गांधी यांनी तयार केलेली आहे. त्यांनी देशाच्या विकासाचा पाया घातला व त्यांच्या जिवावरच या देशाची प्रगती झालेली आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. परंतु मध्यंतरीच्या काळात जी प्रगती व्हावयास पाहिजे होती ती झाली नाही हे मला या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते.

सभापती महोदय, बिहार राज्यात, गुजरात राज्यात विकासाची एक नवी नांदी सुरु झालेली आहे. आमच्या पक्षाने चांगल्या गोष्टीचे नेहमीच स्वागत केलेले आहे. दुस-या राज्याची प्रगती होत आहे परंतु महाराष्ट्र राज्याची प्रगती होत नाही असे जे विरोधी पक्षाकडून बोलले जाते ते योग्य नाही.

सभापती महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांचे अभिभाषण शेतक-यांच्या बाबतीत, उद्योग धंद्यांच्या बाबतीत, कामगारांच्या नवीन धोरणाच्या बाबतीत दिशादर्शक आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या संदर्भात माननीय राज्यपालांनी राज्य शासनाला काही सूचना केलेल्या आहेत. त्यांनी राज्य शासनाला एक नवीन दिशा दिलेली आहे. त्यामुळे मी माननीय राज्यपालांनी जे अभिभाषण केलेले आहे त्याचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो व आपण मला बोलण्यासाठी जो वेळ दिला त्याबद्दल आपलेही आभार मानतो व माझे भाषण पूर्ण करतो.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र...

...2..

श्री. दिवाकर रावते : माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आम्हाला चांगले मार्गदर्शन केलेले आहे. खरे म्हणजे माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सत्ताधारी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांना चांगले भाषण करावेच लागत असते. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी आपले विचार मांडत असतांना विरोधी पक्ष नेहमी वाईट बोलतात, अमुक बोलतात, तमुक बोलतात. परंतु त्यांना असे वाटते की, विरोधी पक्षाने टीका केली नाही तर त्यांचे भाषण पडेल. त्यामुळे आपण जे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल धन्यवाद.

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. विनायक मेटे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर अभिनंदनाचा ठरावा मांडला आहे त्याला अनुमोदन देण्यासाठी मी उभा आहे.

विधीमंडळाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असून या वर्षात माननीय राज्यपालांनी आपल्या समोर जे अभिभाषण ठेवलेले आहे ते वर्तमान काळाचे विचार करणारे,..

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मी हरकतीच्या मुद्याद्वारे सभागृहाच्या असे निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, या सभागृहामध्ये महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरु आहे. माननीय राज्यपालांनी राज्याला चांगली दिशा देणारे भाषण केलेले आहे असे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे आहे. हे सर्वोच्च सभागृह असतांना या चर्चेसाठी मंत्रिमंडळातील एकही ज्येष्ठ मंत्री सभागृहात उपस्थित नाही हे भूषणावह नाही.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

श्री.पांडुरंग फुंडकर

या सभागृहात निराशाजनक स्थिती असून सभागृहामध्ये एकही ज्येष्ठ मंत्री महोदय उपस्थित नाहीत . ब-याचदा या सभागृहात जर मंत्री महोदय उपस्थित नसतील तर असे सांगण्यात येते की मंत्री महोदय खालच्या सभागृहात आहेत परंतु खालचे सभागृह आता स्थगित झालेले आहे.तरी देखील या सभागृहात जर ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित नसतील तर आम्ही माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेणार नाही. ही चर्चा चालू असतांना ज्येष्ठ मंत्री सभागृहात उपस्थित नसणे हा माननीय राज्यपालांचा अवमान आहे.सन्माननीय सदस्य श्री भाई जगताप यांचे भाषण आम्ही अत्यंत शांतपणे ऐकून घेतले आहे. त्यांचे भाषण सुरु असतांना आम्ही हा मुद्दा मांडू शकलो असतो. परंतु आम्ही त्यांचे भाषण सुरु असतांना हा मुद्दा उपस्थित केला नाही.त्यांचे भाषण जवळजवळ एक तास चालले होते परंतु या एक तासामध्ये एकही मंत्री सभागृहात आले नाहीत म्हणजे माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल मंत्री महोदय इतके उदासीन आहेत काय ? तसे जर असेल तर आम्हाला तसे सांगावे अन्यथा आम्हाला सुध्दा या चर्चेत भाग घेण्यामध्ये काहीही रस नाही. माननीय मंत्री जर उदासीन असतील तर या सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तरी कशाला बसावयाचे ? माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरु असतांना मंत्रिमंडळातील एकही ज्येष्ठ मंत्री या ठिकाणी उपस्थित नसणे हा माननीय राज्यपालांचा देखील अवमान आहे. सभागृहाच्या माध्यमातून जर त्यांचा अवमान होत असेल तर ते योग्य नाही. या संदर्भात आपण रुलिंग दिले पाहिजे असे मला सांगावयाचे आहे.त्यानंतर या चर्चेत भाग घ्यावयाचा किंवा नाही हे आम्हाला ठरवावे लागेल.

उप सभापती : सभागृहात मंत्री महोदयांनी उपस्थित रहावे असे माननीय सभापतींनी मघाशी सांगितले असून त्या बाबत निरोप देखील पाठविण्यात आला होता. सन्माननीय सदस्य श्री विनायक मेढे यांनी भाषण सुरु करावे तोपर्यंत मंत्री येतील.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, मी अत्यंत नम्रपणे सांगू इच्छितो की , माननीय मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे या सरकारला तंबी देण्याची वेळ आपल्यावर नेहमी येते ही बाब चांगली नाही. सभागृहात एक कॅबिनेट मंत्री उपस्थित असले तरी कामकाज करता येते,असे सन्माननीय सदस्य श्री भाई जगताप यांनी सांगितले आणि सभागृहाच्या कामकाजाच्या पध्दतीप्रमाणे ते बरोबर आहे.

प्रा.वर्षा गायकवाड : सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणातील मुद्दे मी लिहून घेत आहे.

श्री.दिवाकर रावते : सभागृहात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री नसले आणि राज्य मंत्री असले तरी चालेल अशी व्यवस्था आता आपण करावी आमचे काही म्हणणे नाही.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : कॅबिनेट दर्जाचे एक मंत्री सभागृहात उपस्थित असले पाहिजे हे तांत्रिक दृष्ट्या जरी बरोबर असले तरी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ज्यावेळी चर्चा सुरु असते त्यावेळी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे तसेच सभागृहाच्या नेत्यांनी देखील उपस्थित राहिले पाहिजे.

श्री.माणिकराव ठाकरे : सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी जो मुद्दा मांडला आहे त्याला सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी पाठिंबा दिला आहे. सभागृहातील कामकाज चालविण्यासाठी कॅबिनेट दर्जाचे एक मंत्री उपस्थित असले पाहिजेत ही आपली पध्दत असून ती आपण नेहमीच पाळत आलेलो आहोत. त्याप्रमाणे या ठिकाणी एक कॅबिनेट मंत्री उपस्थित आहेत. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ज्यावेळी चर्चा चालू असते त्यावेळी संबंधित मंत्री जरी उपस्थित नसले तरी ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित असले पाहिजेत हे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही परंतु एक गोष्ट आपणही विचारात घेतली पाहिजे की, या चर्चेला ज्यांना उत्तर द्यावयाचे आहे ते आपल्या कॅबिनमध्ये सर्व भाषणे ऐकत आहेत. त्याचबरोबर सन्माननीय सदस्य सभागृहात जी भाषणे करतात त्याची नोंद घेण्याकरता एक कॅबिनेट मंत्री येथे उपस्थित आहेत.

श्री.जयंत प्र.पाटील : हे सर्व चुकीचे चालले आहे.

डॉ.दीपक सावंत : आपण व्हीडिओ कॉन्फरसिंगची सोय करावी.

श्री.माणिकराव ठाकरे : मी तसे म्हटलेले नाही. आपल्या भाषणाची नोंद घेण्यासाठी एक कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत. सभागृहाचे कामकाज चालण्यासाठी एक कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री उपस्थित असावे लागतात त्याप्रमाणे ते येथे उपस्थित आहेत. त्यामुळे सन्माननीय सदस्य असा मुद्दा उपस्थित करू शकत नाही.

(एकाच वेळी अनेक सन्माननीय सदस्य बोलतात)

प्रा.वर्षा गायकवाड : सन्माननीय सदस्यांच्या भाषणातील मुद्दे मी लिहून घेत आहे. सन्माननीय सदस्य श्री विनायक मेटे यांनी भाषण सुरु करावे तोपर्यंत बाकीचे मंत्री सुध्दा सभागृहात येतील.

(विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून घोषणा देण्यात येतात)

श्री.दिवाकर रावते : माननीय सभापतींनी निदेश देऊन एक तास होऊन गेला तरी अजून माननीय मंत्री सभागृहात उपस्थित नाहीत . सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांचे भाषण आम्ही शांतपणे ऐकून घेतले आहे.

नंतर श्री.सरफरे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, प्रदेशाध्यक्ष श्री. माणिकराव ठाकरे हे आपल्या अनुपस्थित मंत्र्यांचे समर्थन करीत आहेत हे आम्ही कसे सहन करावयाचे?

(गोंधळ)

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, आम्ही निषेध म्हणून सभात्याग करीत आहोत.

(विरोधी पक्षाचे माननीय सदस्य सभात्याग करतात.)

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, आपण दहा मिनिटांकरिता सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे अशी मी विनंती करतो.

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, मी माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे टिपण लिहून घेत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या माननीय सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकणे योग्य नाही.

श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मघाशी माननीय सभापतींनी आपल्या आसनावरून संबंधित मंत्री महोदयांना ताबडतोब सभागृहात उपस्थित रहाण्यास सांगितले. या गोष्टीला एक तास होऊन गेल्यानंतर देखील मंत्री महोदय सभागृहात उपस्थित रहात नाहीत. माझी आपल्याला विनंती आहे की, या ठिकाणी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली पाहिजे याकरिता आपण सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करावे.

उप सभापती : ठीक आहे. मी सभागृहाची बैठक 15 मिनिटांकरिता स्थगित करतो.

(4.31 ते 4.45 बैठक स्थगित झाली.)

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

(स्थगितीनंतर)

सभापतीस्थानी - माननीय उप सभापती**पृ.शी.:** राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा**मु.शी.:** राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाच्या

प्रस्तावावर चर्चा

(चर्चा पुढे सुरु)

श्री.विनायक मेटे : सभापती महोदय, याठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप यांनी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा जो प्रस्ताव मांडलेला आहे, त्याला अनुमोदन देण्यासाठी मी उभा आहे.

सभापती महोदय, विधान मंडळाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या निमित्ताने माननीय राज्यपालांनी जे अभिभाषण केलेले आहे आणि त्यामधून जे विचार मांडलेले आहेत, त्याबाबतीत त्यांचे खरोखरच अभिनंदन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. माननीय राज्यपालांनी राज्याच्या वर्तमान काळाचा विचार करणारे, भविष्य काळाचा वेध घेणारे आणि त्याचबरोबर राज्याच्या प्रगतीला, विकासाला दिशा देणारे भाषण आपल्या सर्वासमोर केलेले आहे. माननीय राज्यपालांचे भाषण पहिल्यानंतर खरोखरच आपण सर्वांनी निश्चितपणे त्यांचे अभिनंदन करणे गरजेचे आहे.या अभिभाषणाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या सर्वासमोर मानव विकास निर्देशांकाची बाब मांडलेली आहे. शासनाने जिल्ह्यांचा गुणक्रम ठरविलेला आहे. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अनुशेषाचा प्रश्न कसा निर्माण होणार नाही याकडे लक्ष देण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकामध्ये जिल्ह्यांचा गुणक्रम ठरविण्याचे शासनाने ठरविलेले आहे.अगोदर आपण प्रादेशिक विभागामधील असमतोल पहात होतो. पण आता या माध्यमातून जर जिल्हानिहाय गुणक्रम ठरविला तर विभागाच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत. जिल्हानिहाय विकासात्मक गुणक्रम कशा पध्दतीचा आहे हे लक्षात आल्यावर जे जिल्हे विकासापासून वंचित आहेत, त्यांच्या संबंधातील चित्र आपल्या समोर स्पष्ट झाल्याशिवाय रहाणार नाही. त्यामुळे शासनातर्फे याबाबतीत जो प्रयत्न करण्यात येत आहे,तो नावाजण्याजोगा आणि कौतुकास्पद असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येईल.

सभापती महोदय, याठिकाणी मी खास करून एका गोष्टीचा उल्लेख करीन की, सदनामध्ये प्रादेशिक विभागामधील अनुशेषाबाबत, असमतोल विकासाबाबत अनेक वेळा चर्चा, विचारविनिमय

श्री.विनायक मेटे

किंवा टीकाटिप्पणी होत असते.अशा वेळी शासनाकडून अनेक वेळेला आपल्या विभागावर अन्याय होत आहे या भावनेतून काही विभागातील लोकांकडून सदरहू विभाग वेगळा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येते. परंतु अशा भागातील लोकांची अशा प्रकारचा विचार करण्याची मानसिकता तयार होणार नाही यादृष्टीने त्यांना न्याय दिला जाईल अशी घोषणा या शासनाने आणि येथे उपस्थित असलेले राज्याचे माननीय उप मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री यांनी केल्यानंतर आता त्या बाबी आपल्या समोर येणारच नाहीत ही बाब सर्वात महत्वाची आहे.

यानंतर कु.थोरात

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. विनायक मेटे.....

अशी घोषणा आणि असे विचार या शासनाने, या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या या राज्याच्या माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी आणि विशेषतः ते या राज्याचे अर्थमंत्री झाल्यानंतर घोषित केले आहेत, हे सगळ्यात महत्वाचे आहे. काही विभागामध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होत आहे. एखाद्या विभागाच्या जनतेमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होणार नाही या करिता शासनाच्या माध्यमातून काही उपाययोजना आणि कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या पुढे काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. हे निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने पहिले पाऊल म्हणून प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरिता एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे ही शासनाने केलेली एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी अतिशय चांगले मुद्दे मांडलेले आहेत. मी या अभिभाषणातील सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्श घेणार नाही तर पाच ते सात मुद्द्यांच्या संदर्भात माझे विचार व्यक्त करून माझे भाषण संपविणार आहे.

सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात असे म्हटले आहे की, "विकास कार्यक्रमांच्या विकेंद्रीत अंमलबजावणीच्या उत्साहवर्धक अनुभवातून शासनाने मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 53 टक्के इतकी वाढ करून जिल्हा योजना 2010-2011 करिता 3828 कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत." अनेक वेळा आमदार, खासदार आपापल्या जिल्ह्यातील महत्वाची कामे लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये असलेल्या अडचणी आणि समस्या दूर व्हाव्यात या करिता सातत्याने प्रयत्न करित असतात. अशा नावीन्यपूर्ण योजनांकरिता या वर्षीपासून खास राखीव निधी वेगळा काढला जाणार आहे. अतापर्यंत अशा प्रकारची तरतूद कधी करण्यात आली नव्हती. मी या संदर्भात काही ठिकाणांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही ठिकाणी माननीय अर्थ मंत्र्यांनी यासंदर्भात पुढील प्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी तसेच माननीय पालकमंत्री यांना आपल्या जिल्ह्यातील जी महत्वाची कामे किंवा उपक्रम नियोजनामध्ये घेता येणार नाहीत किंवा त्याबाबतीत अन्य काही अडचणी असतील तर अशी कामे किंवा उपक्रम नावीन्यपूर्ण योजनेमधून घेण्यात यावेत आणि त्यासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. खेळ, रुग्णालय, शाळा अशा बाबतीतील जे अतिशय गरजेचे उपक्रम असतील पण जे थोडेसे बाजूला राहिलेले असतील, पण हे विषय या नावीन्यपूर्ण योजनेमध्ये घेण्यासारखे असतील तर ते यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न होणार आहे, ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे.

..2...

श्री. विनायक मेटे.....

सभापती महोदय, गेल्या वर्षी राज्यावर फार मोठे संकट ओढवले होते. अतिरेकी हल्याच्या निमित्ताने ओढवलेले संकट आपण सगळ्यांनी अनुभवलेले आहे. आपण कोणीही अपेक्षित केले नव्हते अशा सागरी मार्गाने तो हल्ला झाला होता. गेट वे ऑफ इंडिया कडून हे अतिरेकी आले असे प्रसृत आहे व आपल्या सगळ्यांनाच हे माहीत आहे. पण त्यानंतर त्यांनी जो हल्ला केला, जो सगळा विध्वंस केला तो आपण कधीही विसरू शकणार नाही. या राज्यावर आणि या देशावर अशा पध्दतीचे संकट परत येऊ नये यासाठी "शासनाने सागरी किनारा सुरक्षा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने 12 सागरी पोलीस ठाणी व 32 तपासणी चौक्या कार्यान्वित केल्या आहेत. या व्यतिरिक्त टप्पा-2 मध्ये आणखी 7 सागरी पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात येणार आहेत. सागरी गस्तीसाठी एकूण 57 नौका उपलब्ध करण्यात येणार असून त्यापैकी 28 नौका प्राप्त झाल्या आहेत." सभापती महोदय, या हल्ल्यामध्ये जे जवान व सर्वसामान्य माणसे मृत्युमुखी पडलेले आहेत त्याच्या जखमा आजही ओल्या असल्याचे आपल्याला पहावयास मिळते, इतका निघृण हल्ला या ठिकाणी झालेला आहे. या निमित्ताने मला या ठिकाणी एकच सांगावयाचे आहे की, भारतावर अशा प्रकारचे अतिरेकी हल्ले वारंवार करण्याचे काम पाकिस्तान किंवा अतिरेकी करीत असतात. जगामध्ये ज्या ठिकाणी हल्ले झालेले आहेत मग अमेरिका असेल, इंग्लंड असेल, फ्रांस असेल, स्पेन असेल किंवा अन्य कुठेही

यानंतर श्री. बरवड....

श्री. विनायक मेटे

या सगळ्या ठिकाणी अतिरेकी हल्ले झाल्यानंतर काठेही जिवंत अतिरेकी पकडला गेलेला नाही. ते काम या महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी करून दाखविले आहे. त्यांनी अतिरेक्याला जिवंत पकडून दाखविले आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्रातील पोलीस दल अभिनंदनास पात्र आहे तसेच महाराष्ट्र शासन अभिनंदनास पात्र आहे. सागरी किनारा सुरक्षा अधिक बळकट करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

सभापती महोदय, अनेक योजना आहेत पण त्यांचा मी जास्त उल्लेख करणार नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने असलेल्या काही गोष्टींचा जरूर उल्लेख करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत शेतातील मातीचा दर्जा सुधारण्यासाठी 'गाव सुपीकता निर्देशांक' तयार करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्याबाबत खरोखर शासनाचे कौतुक केले गेले पाहिजे. या सभागृहातील अनेक सन्माननीय सदस्य ग्रामीण भागातून आलेले आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. सय्यद पाशा पटेल यांना याबाबत जास्त माहीत आहे. आपल्या गावातील जमिनीचा पोत कसा आहे, तेथील माती कशी आहे, हे आपल्याला सांगता येत नाही. या राज्यातील अनेक गावातील मातीचा पोत कसा आहे याची माहिती घेऊन त्या ठिकाणी मातीचा पोत कसा वाढेल, सुपीकता कशी वाढेल यादृष्टीने प्रयत्न होणार आहेत. त्यामुळे ही योजना अतिशय महत्वाची आहे. त्याचा फायदा राज्यातील अनेक गावातील, खेड्यातील, पाड्यातील, तांड्यातील शेतकऱ्यांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही योजना म्हणजे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे असे आपल्याला म्हणता येईल.

सभापती महोदय, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक गोष्टी करण्याचे या शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे शासनाचे जेवढे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे. गेल्या वर्षी आपण शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांपर्यंत अल्प व्याजाने पीक कर्ज देत होतो. यावर्षी त्यामध्ये 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केलेली आहे. आतापर्यंत बँकानी जवळपास 11,358 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केलेले आहे आणि 2014-2015 पर्यंत साधारणतः 20 हजार कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बँकांना दिलेले आहे. शासन ज्या पध्दतीने काम करीत आहे ते पाहिल्यानंतर हे उद्दिष्ट साध्य झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे मला वाटते. त्याबद्दल तीळमात्र शंका असण्याचे कारण नाही.

सभापती महोदय, या सगळ्या गोष्टी करीत असताना आपण ऊसाबद्दल अनेक गोष्टी

RDB/ KTG/ MMP/ KGS/ D

श्री. विनायक मेटे

बोलतो. या राज्यात विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा किंवा अन्य ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कापूस उत्पादित होतो. त्या जिल्ह्यांना अधिक प्रोत्साहित करण्यासाठी शासन योजना आखत आहे. या राज्यात शासन नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणू इच्छिते. केवळ शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यापुरतीच ही बाब मर्यादित नाही तर कापसावर सर्व प्रक्रिया राज्यामध्येच केली तर जवळपास महाराष्ट्रातील 10 लाख लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल असे या अभिभाषणामध्ये म्हटले आहे. काही सन्माननीय सदस्यांना कदाचित ही अतिशयोक्ती वाटू शकते, हे नाकारता येत नाही. जिनिंग असेल, प्रेसिंग असेल, स्पिनिंग असेल किंवा वस्त्र निर्मिती असेल हे सर्व प्रकारचे काम याच ठिकाणी केले तर 10 लाख लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण नाही. या राज्यात काही ठिकाणी शासनाने टेक्स्टाईल पार्क निर्माण केलेले आहेत. वसमत, बारामती आणि अन्य ठिकाणी टेक्स्टाईल पार्क निर्माण केलेले आहेत. त्यांची व्याप्ती वाढविण्याचे काम होऊ शकते. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या निमित्ताने मी मुद्दाम सांगू इच्छितो की, मध्यंतरी मी गुजरातमधील कडी गावामध्ये गेलो होतो. त्या कडी गावामध्ये कापूस नसताना स्पिनिंग, जिनिंग मोठ्या प्रमाणावर होते. देशातील बहुतांश कापूस केंद्रे गुजरातमध्ये तयार झालेली आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो आणि गुजरात राज्याला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.विनायक मेटे....

गुजरात राज्यातील कडी या गावामध्ये खानदेशातील, विदर्भातील आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यातील कापूस मोठ्या प्रमाणावर जातो. त्याच्यावर ते प्रक्रिया करतात आणि तेच कापड आपल्या राज्यामध्ये येते. परंतु आपण मात्र काही करीत नाही. पूर्वी वडवणी या गावाचे कापड खूप प्रसिद्ध होते. परंतु आज तेथे एक मीटर कापडाचीही निर्मिती होत नाही. शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित नाही, त्यामुळे ही वेळ आली आहे. आपल्याकडे जी केंद्रे आहेत ती तरी चालू राहतील यासाठी शासनाने खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यातून गरीब लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तामिळनाडूतील त्रिपूरमध्ये, पंजाबमधील लुधियानामध्ये अशाप्रकारचे गार्मेंटचे कारखाने आहेत. आपल्या राज्यातही अशा कारखान्यांसाठी खूप स्कोप आहे. शासनाने जर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी टेक्सटाईल धोरण चांगल्या प्रकारे राबविले तर या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल ते एक शस्त्र होईल.

सभापती महोदय, यानिमित्ताने माननीय उप मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करणे आवश्यक आहे. हे खरे आहे की, मागील काही वर्षांमध्ये आपण विजेचे उत्पादन करू शकलो नाही. परंतु अलीकडेच्या वर्षांमध्ये सन्माननीय उप मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी वीज निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सध्या राज्यातील विविध वीज प्रकल्पांमधून 12 हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होते, मागणी 17 हजार मेगावॉट इतकी आहे. म्हणजे 5 हजार मेगावॉट इतका विजेचा तुटवडा राज्याला भासत आहे. ही तूट डिसेंबर, 2012 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत भरून काढण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवलेले आहे. राज्याला आवश्यक असलेली वाढीव वीज निर्माण करून त्यातून जास्तीची वीज कशी शिल्लक राहिल यासाठी शासनाने धोरण आखले आहे. मग 'महाजेनको'च्या माध्यमातून घेण्यात आलेले विजेचे प्रकल्प असतील, भुसावळ, कोराडी, परळी, पारस या ठिकाणच्या वीज प्रकल्पातून विजेचे उत्पादन सुरु होणार आहे, काही प्रकल्पातून सुरु झाले आहे तर काही प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. तसेच खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून काही वीज प्रकल्प या राज्यात सुरु

2....

श्री.विनायक मेटे....

होणार आहेत. राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी, राज्याच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी, राज्याची प्रगती साधण्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी व सगळ्यांसाठी लागणारी वीज निर्माण करण्याचे माननीय ऊर्जा मंत्र्यांनी उद्दिष्ट्य ठरविले आहे. ते डिसेंबर, 2012 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यासाठी त्यांचे निश्चितपणे कौतुक केले पाहिजे.

सभापती महोदय, मी आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावयाचा आहे. माननीय ग्रामविकास मंत्री श्री.जयंत पाटील यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. या राज्यात 'पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम विकास अभियान' हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला जात आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून आजतागायत गडचिरोली जिल्ह्यापासून ते कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत 33 जिल्ह्यांना माननीय ग्रामविकास मंत्र्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत.

यानंतर श्री.शिगम.....

श्री. विनायक मेटे...

तसेच काही तालुक्यांना आणि ग्रामपंचायतींना देखील त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत. याचा परिणाम असा झालेला आहे की 28 हजार ग्रामपंचायती पैकी 19 हजार ग्रामपंचायतींनी या अभियानामध्ये सहभाग नोंदविलेला आहे. "पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम विकास अभियान" हे महत्वाकांक्षी असे अभियान आहे. आज आपण जपानमधील विघातक घटना पहात आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर या अभियानाचे महत्व आपणा सर्वांच्या लक्षात येईल. या अभियानामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीमागे एक झाड लावण्याची संकल्पना या अभियानाची आहे. आतापर्यंत 5 कोटी 13 लाख झाडे या अभियानांतर्गत लावण्यात आलेली आहेत. 16 हजार ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावामध्ये 60 टक्के शौचालये बांधलेली आहेत. घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची वसुली फार कमी प्रमाणात होते. परंतु या वसुलीमध्ये भरिव वाढ या अभियानाच्या माध्यमातून झालेली आहे. ज्या ग्रामपंचायती या अभियानामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत आणि ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 5 हजारापेक्षा अधिक आहे अशा ग्रामपंचायतींचा 20-25 वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. अशा तऱ्हेने गावांच्या विकासाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वपूर्ण असे अभियान राज्य शासन राबवित आहे. आता काही लोकांच्या मनामध्ये या अभियानाच्या संदर्भात विविध प्रश्न निर्माण होत असतील. झाडे कशी जगणार, उन्हाळ्यात त्यांना पाणी कसे मिळेल, जनावरे झाडे खाणार नाहीत काय, अशा प्रकारचे विविध प्रश्न उपस्थित केले जातील. परंतु मी सांगू इच्छितो की, या अभियानांतर्गत अशी तरतूद करून ठेवलेली आहे की, जर एखादे लावलेले झाड मेले तर त्याठिकाणी आजूबाजूला असलेल्या नर्सरीमधून 4-6 महिन्यांचे रोप आणून आपणास लावता येईल. अशा प्रकारचा हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे.

सभापती महोदय, स्थानिक प्रशासन व निमशासकीय यंत्रणा यांचे कामकाज कार्यक्षम बनविण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदणी प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे शासनाने ठरविलेले आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केन्द्रे, शाळा, हायस्कूल, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांची कार्यालये या ठिकाणी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल. या प्रणालीमुळे आजच्या दिवसाची सही उद्या करण्याची मुभा असणार नाही. आपण 21व्या शतकामध्ये असून उपलब्ध होणा-या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. मी माहितीकरिता

..2..

श्री. विनायक मेटे...

सांगू इच्छितो की, खाजगी कंपन्यामध्ये कामावर येताना आणि जाताना अधिकारी आणि कर्मचा-यांना बायोमेट्रिक पध्दतीने थम इंप्रेशन करुन आपल्या उपस्थितीची नोंद करावी लागते.

...नंतर श्री. गिते...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.विनायक मेटे...

सभापती महोदय, काही शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी उपस्थितीची रजिस्टर्स बंद केली आहेत. कार्यालयात येताना आणि जाताना कर्मचाऱ्याने बायोमेट्रीक मशीनमध्ये बोट लावून उपस्थिती नोंदवावयाची अशी कार्यप्रणाली सुरु केलेली आहे. बायोमेट्रीक मशीनमध्ये जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेले आहे, त्या सॉफ्टवेअर माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीची तसेच येण्या-जाण्याची नोंद होत असते. त्यानुसार पगार सुध्दा काढला जातो. आता उपस्थिती रजिस्टरची ची गरज राहिलेली नाही. बाहेरील कार्यालयात ही प्रणाली सुरु असेल तर त्या प्रणालीचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. जिल्हा स्तरावर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी तक्रारी आहेत. त्या तक्रारी निर्माण होण्यास वाव मिळणार नाही. रुग्णालये,शाळा, जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांना सांगता येणार नाही की, मी या ठिकाणी गेलो होतो, मी त्या ठिकाणी गेलो होतो असे सांगण्यास या प्रणालीमुळे वाव मिळणार नाही हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो.

सभापती महोदय, जात पडताळणी समिती कार्यालयात संगणकीकरण करणे बाबतचा राज्य शासनाने एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. जात पडताळण्या समित्या विभागीय पातळीवर तयार झालेल्या आहेत, त्याबाबतीत अशा वेळेला मत प्रदर्शन करणे बरोबर नाही. परंतु अनेक जिल्ह्यातील जात पडताळणी समित्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या आहेत असे मला अतिशय नाईलाजास्तव सांगावेसे वाटते. मी औरंगाबाद येथील उदाहरण दिले तर आपणास फार मोठे आश्चर्य वाटेल. जात पडताळणी कार्यालयात पाच-पाच,सहा-सहा वर्षांपासून तेच तेच अधिकारी कार्यरत आहेत. तुम्ही त्या कार्यालयात न जाता जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र मिळते. कोणत्या प्रमाणपत्रास किती दर आहे यासंबंधी तेथील अधिकाऱ्यांनी दर ठरविलेले आहेत. जात पडताळणी समितीवर अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या व्हाव्यात म्हणून मरणाचा आटापिटा करीत असतात. ते अधिकारी, कर्मचारी एवढ्यावर थांबत नाहीत तर त्यांना कोणता भाग मिळावा यासाठी त्यांची मोठी कसरत चाललेली असते. त्यांना स्वार्थ साधावयाचा असतो म्हणून ते प्रयत्न करीत असतात. जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयामध्ये संगणकीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे, त्यामुळे निश्चितपणे गैरप्रकारांना आळा बसेल. माझी शासनाचा एकच विनंती आहे की, आपण आय.टी.रिटर्नस् ऑनलाईन भरतो. अनेक गोष्टीसाठी आपण ऑनलाईनचा वापर करतो. जात पडताळणी समिती कार्यालयातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर व

2...

श्री.विनायक मेटे...

संगणकीकरण केले तर त्याचा निश्चितच गोरगरीब जनतेचा फायदा होईल असे मला वाटते. शासनाने जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाबाबत मी शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

सभापती महोदय, अल्पसंख्याक समाजाचा विकास करण्यासाठी सच्चर समितीच्या बाबतीत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे, त्याबाबतीत शासनाचे कौतुक करणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक समाजाबद्दल सगळ्यांनाच माहिती आहे. अल्पसंख्याकातील मुस्लीम समाजामध्ये शिक्षण घेण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प होते. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्र यामध्ये नोकऱ्यांचे तसेच उद्योगांचे प्रमाण अतिशय कमी असावयाचे. छोटे छोटे उद्योग सुरु करून ते आपली गुजराण करीत होते. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये शासनाच्या काही धोरणामुळे तसेच काही लोकांच्या प्रयत्नामुळे या समाजातील पिढी उच्च शिक्षण घेऊ लागली आहे. टेक्निकल, नॉन टेक्निकल शिक्षण घेण्यासाठी त्या समाजातील तरुण पिढी पुढे येऊ लागली आहे. त्यांनी उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना वाटू लागले की, आपल्याला कशाचीही संधी मिळालेली नाही. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत शासनाने जे धोरण आखले आहे ते दूरगामी परिणाम करणारे आहे.

यानंतर श्री. भोगले...

श्री.विनायक मेटे.....

त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना नोकरी, उद्योग, आयटीआयमधील कोर्सेस यादृष्टीने प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र, तंत्रनिकेतन उघडण्याचे काम शासनाने केलेले आहे.

सभापती महोदय, मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पर्यटन क्षेत्रात आपण अगणित रोजगार निर्मिती करू शकतो. सन्माननीय पर्यटन मंत्र्यांनी 2011-12 हे वर्ष 'पर्यटन वर्ष' म्हणून जाहीर केले आहे. मला खात्री आहे की, या पर्यटन वर्षात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासन निश्चितपणे ठोस भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाही. या देशातील किंबहुना जगातील अनेक राष्ट्रे केवळ पर्यटनावर आपला आर्थिक विकास साधण्याचे काम करीत आहेत. आपल्या देशात गोवा, केरळ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम यासारखी छोटी मोठी राज्ये पर्यटनाकडे अधिक लक्ष देताना आपण पहात आहोत. यासाठी पर्यटन धोरण असणे गरजेचे आहे. पर्यटन धोरण निश्चित केले तर रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उत्पन्नाच्या दृष्टीने आपण फार मोठी मजल गाठू शकतो. आपल्या राज्याला 720 कि.मी.चा सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी पर्यटनाला मोठया प्रमाणात चालना देता येईल. आपल्या राज्यात ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, शक्तीपीठे आहेत, त्यांचाही आपण पर्यटनाच्या दृष्टीने फायदा करून घेऊ शकतो. राज्यात ऐतिहासिक पर्यटन स्थळे आहेत. 300 ते 350 ऐतिहासिक किल्ले आहेत. त्यातील 25-30 महत्वाच्या किल्ल्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार केला तर शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड, पन्हाळगड, सिंधुदुर्ग, मुरुड जंजिरा आदी किल्ल्यांचा आपल्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने फायदा घेता येईल. राज्यात अनेक जगप्रसिद्ध लेणी आहेत. वेरुळ, घारापुरी, कार्ला, एलिफंटा लेण्यांचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. वन पर्यटनाच्या दृष्टीने ताडोबा, पेंच, मेळघाट आदी वन क्षेत्रातील ठिकाणांचा उपयोग होऊ शकतो. पर्यटन वर्षामध्ये राज्य शासन यादृष्टीने विचार केल्याशिवाय राहणार नाही याची मला निश्चितपणे खात्री आहे. 2011-12 हे वर्ष पर्यटन वर्ष म्हणून जाहीर केल्याबद्दल मी शासनाने मनःपूर्वक स्वागत करतो आणि अभिनंदनही करतो.

सभापती महोदय, किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार आणि संरक्षणाचा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. शासनाने ऐतिहासिक किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार आणि संरक्षण करण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे.

श्री. विनायक मेटे

मी मागील काळात राजस्थान राज्यात गेलो असता त्या राज्यात पुरातन काळातील ज्या वास्तू उभ्या आहेत त्यांचे जतन करण्यासाठी राजस्था हे राज्य अनेक परीने प्रयत्न करित आहे असे दिसून आले. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल यासाठी देखील त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. आपल्या राज्यात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी ज्याप्रमाणे सिंहगड आणि शिवनेरी किल्ल्यांच्या विकासासाठी केंद्राकडून पैसा आणला त्याप्रमाणे राज्यातील इतरही काही किल्ल्यांचा त्यात समावेश करुन केंद्राच्या माध्यमातून त्यांचा जीर्णोध्दार करावा.

महोदय, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक कसे उभे करता येईल या गोष्टीकडे संपूर्ण राज्याच्या जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे पण यावर वेगळी चर्चा घेण्याचे मान्य केलेले असल्याने मी जास्त ऊहापोह करणार नाही. पण ज्या ज्या गोष्टींचा उहापोह माननीय राज्यपालांनी अभिभाषणात केला आहे, ज्या गोष्टींचे नियोजन केलेले आहे त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा आभार मानतो. तसेच माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री यांचेही मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे दोन शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.

प्रस्ताव प्रस्तुत झाला.

उप सभापती : सत्ताधारी पक्षाकडून मांडलेल्या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावर प्रस्ताव मांडणारे आणि अनुमोदन देणारा अशा दोनच सन्माननीय सदस्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत. वास्तविक सत्ताधारी पक्षासाठी फक्त 35 मिनिटांचाच वेळ दिलेली होती. पण आतापर्यंत त्यांनी 1 तास 45 मिनिटे घेतलेली आहेत. त्यामुळे उर्वरित वेळ विरोधी पक्षासाठी द्यावा लागेल तसेच भाषण करताना वेळेचे बंधनही घालावे लागेल, हे सन्माननीय सदस्यांनी कृपया लक्षात घ्यावे.

.....2.....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3J-2

PFK/ D/ MMP/

पूर्वी श्री. भोगले.....

17:20

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होत असताना वास्तविक सत्ताधारी पक्षाकडून कमी बोलावे अशी अपेक्षा असते. त्यावर खरे तर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आपले विचार व्यक्त करून आणि उणिवा दाखवून त्याचे उत्तर मंत्री महोदयांनी देणे आवश्यक असते.अडथळा.....शासनाचे धोरण चांगले असेल तर सत्ताधारी पक्षाने इतका वेळ बोलण्याची काय गरज आहे ? तरीही सत्ताधारी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांना बोलायचेच असेल तर शासनाच्या ज्या उणिवा आहेत त्या मान्य करून विचार मांडावेत, आमची हरकत नाही.

उप सभापती : ठीक आहे, आता माननीय विरोधी पक्षनेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत.

.....3.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. पांडुरंग फुंडकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, महामहिम राज्यपालांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जे अभिभाषण केले त्यावरील चर्चेत माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे.

महोदय, माननीय राज्यपालांचे अभिभाषण मी एक वेळा नव्हे तर दोन वेळा वाचले आहे. त्यात जवळपास 70 मुद्दे दिलेले आहेत. त्यातील बरेच मुद्दे गेल्या तीन वर्षांपासून रिपीट झालेले आहेत. वास्तविक अभिभाषण म्हणजे शासनाचे त्या त्या वर्षाचे धोरण, नियोजन काय आहे, कोणत्या दिशेला राज्याला न्यावयाचे आहे यासंबंधीचे प्रत्यक्ष दिग्दर्शन असावे अशी अपेक्षा असते.

यानंतर श्री. जुन्नरे

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांनी जे अभिभाषण केलेले आहे त्यामध्ये एक मुद्दा सोडला तर भाषणास समर्थन करण्यासारखे काहीही नाही. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात गेल्या 10-11 वर्षांपासून जे चालले आहे त्यामुळे महाराष्ट्र बदनाम होत आहेत, महाराष्ट्राला कलंक लागणा-या घटना घडत आहेत हे मान्य केले असते तर बरे झाले असते.

सभापती महोदय, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे त्यामुळे या पुरोगामी राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत एवढा जरी उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांनीही केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. या राज्यातील भूखंड माफिया, दूध माफिया, रेंती माफिया, रोड माफिया, सावकार माफिया हे महाराष्ट्राला गिळंकृत करीत आहेत. महाराष्ट्रातील 10 कोटी जनतेला वेठीला धरून राज्य सरकारला न जुमानता, राज्य सरकारच्या नाकावर टिच्चून या माफियांनी राज्याच्या जनतेचे रक्त शोषण करण्याचे जे काम चालवले आहे त्याचा बंदोबस्त केला जाईल असे माननीय राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले असते तर आपल्या राज्यातील 10 कोटी जनतेला दिलासा मिळाला असता.

सभापती महोदय, मी पहिल्यांदा माननीय राज्यपाल महोदयांचे अभिनंदन करणार आहे त्याचे कारण असे आहे की, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात एक गोष्ट अभिनंदनास पात्र आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून शेतक-यांचे व्याज कमी करा अशी मागणी करीत होतो. यासंदर्भात माननीय राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात 50 हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज संपूर्णपणे व्याजमुक्त केले असून 50 हजार रुपयांपासून 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 2 टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे, हा जो उल्लेख आपल्या अभिभाषणात केलेला आहे तो उल्लेख अभिनंदनास पात्र आहे.

सभापती महोदय, मी माननीय राज्यपाल महोदयांचे तसेच माननीय मुख्यमंत्र्यांचेही अभिनंदन करणार आहे परंतु त्याबरोबर माझी एक भावनाही आपल्याला बोलून दाखवणार आहे. आपल्या राज्याच्या बाजूच्या कर्नाटक राज्यामध्ये शेतक-यांना 1 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

दिले जाते. महाराष्ट्र हे या देशातील एक पुरोगामी व अग्रगण्य राज्य आहे. आपल्या राज्याच्या पुढे काही राज्य का चालली चालली आहे त्याचाही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.

सभापती महोदय, माफियांचे पाठराखण करणारे, घोटाळेबाज, कर्जबाजारी, अकार्यक्षम अशा अनेक विशेषणानी या सरकारचे वाभाडे निधालेले आहे असे असतांना आपण शेतकऱ्यांना 2 टक्के दराने जो कर्ज पुरवठा केला आहे त्यामुळे सर्व काही झाकून जाईल असे समजण्याचे काही कारण नाही. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना यामध्ये दोष देणार नाही परंतु गेल्या 10-11 वर्षांपासून या राज्यात जे काही चालले आहे त्याबाबत आम्ही माननीय राज्यपालांना भेटून त्यांना भूखंडाची जवळपास 32 प्रकरणे दिली होती. आमच्या पक्षाचे काही नेते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटले असून त्यांना देखील या भूखंडाच्या संदर्भात निवेदन दिलेले आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात कारवाई करू असे आश्वासन दिलेले आहे. जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांचा दरोडा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर टाकण्याचे काम भूखंड माफियांनी केलेले आहे.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

श्री.पांडुरंग फुंडकर ..

त्याचे समर्थन कोण करते ? कशासाठी समर्थन केले जाते ? एका बाजूला 2 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य शासनावर आहे. राज्य दिवाळखोरीत आहे, त्याची कोणालाही चिंता नाही. राज्याची बदनामी होत आहे परंतु त्याची देखील कोणाला चिंता नाही. राज्यामध्ये वारंवार घोटाळ्या मागून घोटाळे उघडकीस येत आहेत. मुंबईत सिडकोची जमीन असो , एमएमआरडीएची जमीन असो, वा रिझर्व्हेशनची जमीन असो या सर्व जमिनी विकण्याचा सपाटा गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु आहे. त्याबाबतीत सरकारने काय कारवाई केली ? ही कौतुक करण्यासारखी बाब नाही. त्यासाठी आपल्या सर्वाना आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. एका बाजूला राज्य दिवाळखोरीत असतांना दुस-या बाजूला भूखंड माफिया राज्याचे लचके तोडत आहेत आणि करोडो रुपयांची माया त्यातून जमवत आहेत.

सभापती महोदय, माननीय श्री.पृथ्वीराज चव्हाण राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर एका कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी एका गोष्टीची कबुली दिल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करणार आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच कबुली दिली असल्यामुळे त्या बाबतीत मला जास्त काही बोलण्याची आवश्यकता नाही., बिल्डर ,नोकरशाह आणि राजकारणी यांनी मुंबई विकावयास काढली आहे असे माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच निवेदन केले होते. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसे सांगितलले असल्यामुळे त्याबाबतीत आम्हाला पुरावे देण्याची काहीही गरज नाही. तसेच अधिक बोलण्याची देखील गरज नाही. भूखंड विकण्याचे, दूध आणि तेलामध्ये भेसळ करण्याचे प्रकार राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. विधानमंडळाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून हे वर्ष साजरे केले जात असतांना याच विधानमंडळामध्ये आम्हाला तेल माफियासंबंधी चर्चा करावी लागत आहे ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात आहे आणि शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या राज्यात एका दलित अधिका-याला जाळून त्याची हत्या केली जात असेल तर ती आपल्या राज्याला कलंक आहे.

सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणात नेहमी प्रमाणे आश्वासनांची खेरात केलेली आहे.प्रत्यक्षात त्याची कितपत अंमलबजावणी होती हे आपण नंतर पाहू या. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या पान नंबर 5 मध्ये असे म्हटलेले आहे की," दहा लाख व्यक्तीसाठी

श्री.पांडुरंग फुंडकर.....

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर 1 लाख 44 हजार 556 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून त्यातून 2 लाख 15 हजार लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे पान नंबर 6 मध्ये लिहिलेले आहे. म्हाडाच्या मार्फत चार हजार परवडण्यासारखी घरे बांधण्यात येतील असे पान नंबर 11 मध्ये लिहिलेले आहे. अशा प्रकारे माननीय राज्यपालांनी अनेक पानांमध्ये आश्वासनाची खेरात केलेली आहे. परंतु सत्य परिस्थिती जर आपण पाहिली तर आपल्याला असे दिसून येईल की, हे सर्व मृगजळच आहे. या पूर्वीच्या माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातसुद्धा अशाच प्रकारे सूतोवाच करण्यात आले होते. पान नंबर 6 मध्ये असे म्हटलेले आहे की, 169 औद्योगिक विशाल प्रकल्पापैकी राज्यातील मागास असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाडयात जवळजवळ 111 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती त्यातील 70 प्रकल्प मराठवाडयात आणि विदर्भात आहेत याबाबतीत खरी परिस्थिती पाहिली तर आपल्याला असे दिसून येईल की ही सगळी कागदावरील आकडेवारी आहे. संपूर्ण विदर्भामध्ये 2005 सालापासून 56 विशाल औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती त्यापैकी फक्त 25 औद्योगिक विशाल प्रकल्पामध्ये आज उत्पादन सुरु झाले आहे. अमरावती विभागाचा विचार केला तर तेथील पाच प्रकल्पामध्येच आज उत्पादन सुरु झाले आहे.

नंतर श्री.सरफरे

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

आपण मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये हे 70 प्रकल्प सुरु करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे, त्या निमित्ताने गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर, वीज, पाणी आपण कोठून देणार आहात? महामहिम राज्यपालांनी सन 2012 पर्यंत हे राज्य भारनियमन मुक्त होणार असल्याचे सांगितले आहे. जर तुम्ही उद्योगांना लागणारी वीज देणार नसाल तर हा परिच्छेद याठिकाणी कशासाठी टाकला आहे. विदर्भ आणि मराठवाडयामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 70 प्रकल्पांना वीज मिळणार नसेल तर ते चालणार कसे, तर मग आपण याठिकाणी ही आकडेवारी कशासाठी देत आहात? ज्यावेळी हे महाराष्ट्र राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल त्यावेळी या राज्यात 70 नाही तर 100 उद्योग आम्ही सुरु करू असे या भाषणामध्ये म्हणा. त्यामुळे जोपर्यंत त्यांना वीज मिळणार नाही तोपर्यंत तुम्ही सांगून देखील ते उद्योग या राज्यात येणार नाहीत. या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल, वीज आणि पाणी आपण पुरविणार आहात काय, आज विदर्भ आणि मराठवाडयामध्ये पाण्याची टंचाई असतांना आपण या उद्योगांना कोठून पाणी देणार आहात?

महामहिम राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेला उद्योगांचे मृगजळ दाखविले आहे, त्यामुळे त्याचे आपल्याला अभिनंदन करता येणार नाही. यामधून विदर्भ आणि मराठवाडयातील जनतेची फसवणूक होऊ लागली आहे. या अभिभाषणामध्ये 1 लाख 44 हजार 556 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. परंतु अमरावती विभागामध्ये केवळ 721 कोटी आणि संपूर्ण विदर्भामध्ये 9 हजार 320 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याची आकडेवारी दाखविते. यापेक्षा मराठवाडयाची परिस्थिती वेगळी नाही. सन 2005 पासून मराठवाडयामध्ये मंजूर केलेल्या 14 प्रकल्पांपैकी केवळ 10 प्रकल्पांमध्ये उत्पादन सुरु झाले. असे असतांना माननीय सदस्य श्री. मेटे साहेब आपण महामहिम राज्यपालांचे कशासाठी अभिनंदन केले आहे? या प्रकल्पांमध्ये 2 हजार 95 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

सभापती महोदय, राज्यामध्ये म्हाडामार्फत 4 हजार परवडण्याजोगी घरे बांधण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु त्या घरांची किंमत किती रहाणार आहे हे याठिकाणी नमूद केले असते तर बरे झाले असते. ही 4 हजार घरे आपण कुणाला देणार आहात? ज्यांचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपये आहे त्या व्यक्तीला आपण 16 लाख रुपये किंमतीचे घर देणार आहात. त्या घराची किंमत आज 16 लाख रुपयापर्यंत गेली आहे. अशाप्रकारे महिना 10 हजार

DGS/ D/ MMP/

श्री. पांडुरंग फुंडकर

रुपये पगार असलेल्या माणसाला कोणतीही बँक 6 लाखापर्यंत कर्ज देत नाही तर मग उरलेले पैसे त्या व्यक्तीने कोठून उभे करायचे?

सभापती महोदय, महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये 2.15 लाख रोजगाराच्या, 10 लाख रोजगाराच्या संधी देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आज राज्यामध्ये प्रकल्प सुरु झाले नाही, उद्योग सुरु झाले नाही तर आपण बेरोजगारांना रोजगार कोठून देणार आहात? परंतु हे अभिभाषण वाचल्यानंतर हे राज्य शासन येणाऱ्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करित निघाले आहे. अभिभाषणाच्या पृष्ठ क्रमांक 6 वर "महाराष्ट्र हे भारतातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य राहिले आहे" असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु मुंबई, पुणे आणि नाशिक वगळता राज्यामध्ये कोठेही औद्योगिक विकास झालेला नाही. मुंबईमध्ये अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, येथील उद्योजकांनी शासनाकडून अल्प दराने जमीन घेऊन उद्योग सुरु केले आणि जमिनीचे भाव वाढल्यानंतर, जमिनीला सोन्याचा भाव आल्यानंतर ते उद्योग बंद केले.

(यानंतर श्रीमती रणदिवे)

श्री.पांडुरंग फुंडकर

व मिलच्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी परवानगी घेऊन उद्योजकांकडून विकण्यात आल्या. त्यामुळे तेथील कामगार बेकार झाला. मुंबईतील कापड गिरण्या बंद झाल्यावर तेथे मॉल उभे राहिले. कापड गिरण्या कशासाठी विकण्यात आल्या. कारण गिरणी मालकांनी त्या बंद केल्या. त्यामुळे हजारो कामगार बेकार झाले, देशोधडीला लागले. त्याठिकाणी मॉल उभे करण्याऐवजी कारखाने उभे केले असते तर बंद पडलेल्या गिरणीतील कामगार बेकार झाला नसता. मध्यंतरी नुकतीच ठाणे येथील रेमंड कंपनी बंद पडली. त्यामुळे तेथील कामगार देखील बेकार झाले आणि मालक मात्र या जमिनी विकून गब्बर झाले. तीच गत ठाणे,बेलापूर येथील आहे. आज बेलापूर आणि ठाणे परिसरातील जवळपास बहुतेक कारखाने हळूहळू कमी व्हावयास लागले आहेत. सभापती महोदय, मला तसे काही आरोप करावयाचे नाहीत, पण मी जे सांगत आहे ती वस्तुस्थिती आहे. आपण याबाबतीत काही विचार करणार आहोत की नाही हा प्रश्न आहे. या राज्याचा औद्योगिक विकास झाला पाहिजे यादृष्टीने औद्योगिक धोरण आखत असताना कुठेतरी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे समर्थन न करता, त्याचा विरोध करून याठिकाणी देशातील सर्वसामान्य कामगाराचा, उत्पादनाचाही विचार व्हावयास पाहिजे. पण पैशाच्या लोभापायी जर उद्योगपती कारखाने बंद करून जमिनी विकणार असतील तर आपण त्याचे समर्थन करणार आहोत काय ? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून कारखाने बंद करून जमिनीच्या विक्रीसाठी परवानगी न देता, जर उद्योगपतींना तेथे कारखानाच उभा करण्याच्या बाबतीत अट टाकण्यात आली असती तर आज येथील कारखान्यांची संख्या कमी झाली नसती आणि येथील कामगार बेकार झाला नसता. तसेच कारखाने परराज्यामध्ये गेले नसते आणि मुंबईमध्ये सिमेंटची जंगले उभी राहिली नसती.

सभापती महोदय,त्यामुळे एकंदर राज्याचे जे औद्योगिक धोरण आहे, त्याबाबतीत सन्माननीय सदस्य श्री.विनायक मेटे साहेब आपण कितीही घोषणा केल्या, गुंतवणुकीच्या बाबतीत कितीही आकडेवारी दिली तरी मराठवाडा तसाच रहाणार आहे, विदर्भ तसाच रहाणार आहे, खानदेश तसाच रहाणार आहे आणि कोकणही तसाच रहाणार आहे. याबाबतीत तुम्ही फार काही अपेक्षा करू नये. कारखानदारी अशीच फिरत रहाणार आहे आणि काही दिवस कारखाना चालविल्यानंतर त्याच्या जमिनी विकल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या धोरणामध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज आहे.

सभापती महोदय, आदिवासींच्या बाबतीत तीच स्थिती आहे. राज्यातील आदिवासींचा विकास

श्री.पांडुरंग फुंडकर

व्हावा म्हणून राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र बजेट असते. हा एकमेव विभाग असा आहे की, ज्या विभागासाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक असून, त्यासाठी जवळपास साडेतीन हजार कोटीपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद केली जाते आणि आपण या विभागाला तेवढी रक्कम उपलब्ध करून देतो. पण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पोषण आहार योजने अंतर्गत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तुंसाठी अनुदानाची तरतूद नाही. त्यामुळे पुरवठादार, बचत गट व ठेकेदार यांना शासनाकडून गेल्या जुलै महिन्यापासून पैसेच देण्यात आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत आदिवासी कसा जगणार आहे ? एका बाजूला आपण त्यांना सांगतो की, तुम्हाला पोषण आहार दिला जाईल, तुला वस्तू दिल्या जातील. पण प्रत्यक्षात जुलैपासून गेल्या सात-आठ महिन्यामध्ये शासनाने पैसेच दिलेले नाही. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड या चार तालुक्यातील आश्रमशाळांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या बचत गटाची सरकारने आर्थिक कोंडी केली. त्यामुळे त्यांनी आता पोषण आहार पुरविण्याचे काम बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कारण त्यांना पूर्वीची बिलेच मिळत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा दीड ते दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना जर विद्यार्थ्यांना जेवणच मिळाले नाही तर त्यांचे काय होईल याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

यानंतर कु.थोरात

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

या चार तालुक्यात 30 आश्रमशाळा आहेत. जव्हार तालुक्यात 5450, मोखाडा तालुक्यात 3233, विक्रमगड तालुक्यात 3010 तर वाडा तालुक्यात 2777 असे 1400 विद्यार्थी या आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. परंतु आज या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागलेले आहे. **उप सभापती** : माननीय विरोधी पक्ष नेते यांच्या भाषणानंतर सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र.पाटील हे बोलतील तोपर्यंत सभागृहाच्या कामाकाजाची वेळ वाढविण्यात येत आहे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये "माझ्या शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक दर्जा वाढविण्याचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे" असे वाक्य आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेवून त्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक दर्जा कसा वाढणार आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा देताना प्राणपणाने लढलेल्या गिरणी कामगारांची आज काय अवस्था आहे? आपल्या अस्तित्वासाठी ते अजूनही लढत आहेत. मुंबईतील 58 गिरण्यांपैकी 23 गिरणी मालकांनी कामगारांच्या घरांकरिता जमीन देण्याचे सरकारला आश्वासन दिले होते. त्यांचे करार झाले होते परंतु प्रत्यक्षात 11 गिरणी मालकांनी जमिनी दिल्या. उरलेल्या 12 गिरणी मालकांचे काय केले? 1/3 वाटपाने 100 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मिळावयास पाहिजे होती परंतु प्रत्यक्षात जेमतेम 25 एकर जमीन मिळाली, त्यावर 10 हजार घरे बांधली असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यातील केवळ 6948 घरे गिरणी कामगारांना दिली जाणार आहेत, परंतु या 6948 घरांसाठी 16,000 गिरणी कामगारांचे अर्ज आलेले आहेत. या 16,000 अर्जांचा व 6948 घरांचा ताळमेळ शासन कसा बसविणार आहे. घरे देण्याच्या तारखांमध्ये घोळ आहे. सन 2001 नंतर बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील कामगारांना घरे देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. घरांची किंमत 8.50 लाख रुपयावरून 10.50 लाख ते 12 लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. गेली 20 वर्षे हा गिरणी कामगार बेकार आहे. त्यामुळे या गिरणी कामगाराने 10 लाख रुपये कसे उभे करावयाचे याचे उत्तर न देता माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात पृष्ठ क्रमांक 11 वर असे म्हटले आहे की," मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरणी कामगारांना घरे बांधून ती वितरित करण्यास

माझे शासन वचनबद्ध आहे." यावर आम्ही कसा विश्वास ठेवावयाचा.

सन्माननीय सदस्य श्री. मेटे यांनी प्रादेशिक असमतोलाचे फार कौतुक केले. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा उल्लेख माननीय

...2..

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या भाषणात केला. माझा या ठिकाणी सवाल आहे की, यापूर्वीही अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी दांडेकर समिती, अनुशेष निर्मूलन समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समित्यांनी त्यांचे अहवाल सादर केले. या अहवालांमध्ये महाराष्ट्रातील मागास भागावर विशेषतः विदर्भ मराठवाडयावर फार मोठा अन्याय झाल्याचे या समित्यांनी सूचित केले होते. या समित्यांनी अहवाल देऊन सुध्दा राज्य शासनाने आजपर्यंत आडमुठे धोरण स्वीकारल्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष कमी न होता तो वाढत गेला. आता परत नव्याने हा अनुशेष दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्यामध्ये आणखी किती वेळ घालविण्यात येणार आहे? मला माहित आहे की, दादा आता अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे आता दादा असे सांगतील की, आर्थिक अनुशेष संपलेला आहे. आर्थिक अनुशेष संपलेला असला तरी भौतिक अनुशेष संपलेला नाही. या भौतिक अनुशेषाचे काय करण्यात येणार आहे?

सभापती महोदय, 10 कोटी रुपयांच्या निविदा 100 कोटी रुपयांपर्यंत गेल्या आहेत. आपण ते 100 कोटी रुपये धरणार आहात, 10 कोटी रुपये धरणार नाही. गेल्या दोन ते चार वर्षांचे पाटबंधारे विभागाचे रेकॉर्ड पाहिले तर 10 कोटी रुपयांच्या निविदा 100 कोटी रुपयांपर्यंत आणि 100 कोटी रुपयांच्या निविदा 150 कोटी रुपयांपर्यंत गेलेल्या आहेत.

यानंतर श्री. बरवड.....

श्री. पांडुरंग फुंडकर ...

त्यातून अॅडव्हान्स दिले गेले. अशा पध्दतीने हा आर्थिक अनुशेष संपविण्याचा दुष्ट कट राज्यामध्ये शिजला गेला आणि त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता वाढली नाही. 2010-2011 या वर्षाकरिता अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 7919 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उल्लेख माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये केलेला आहे. परंतु त्या तरतुदीपैकी किती रक्कम विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला आली, ही बाब माननीय राज्यपालांच्या निदर्शनास आली नसल्याचे कालच्या लोकसत्तेमध्ये छापून आलेले आहे. माननीय राज्यपालांनी लोकसत्तेमध्ये विधान केलेले आहे. महालेखापालांकडून सविस्तर आकडेवारी प्राप्त न झाल्याचे कारण राज्य सरकारने पुढे केल्याचे त्यात म्हटले आहे. मी अशी मागणी करतो की, या 7919 कोटी रुपयांचा विनियोग कसा झाला याची माहिती दोन दिवसात माननीय राज्यपालांना दिली पाहिजे तसेच या सभागृहालाही दिली पाहिजे. माननीय राज्यपालांनी राज्य सरकारला याबाबत ठणकावले आहे.

सभापती महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कौतुक झाले. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. या राज्यामध्ये पहिल्यांदा 1972 मध्ये या राज्यातील गरीब लोकांना कामाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना सुरु केली. त्यानंतर सर्व हिंदुस्थानात या योजनेची कॉपी करण्यात आली. आज आपल्या रोजगार हमी योजनेची काय अवस्था आहे ? रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात आज सकाळी या सभागृहामध्ये चर्चा झाली. मला एका बैठकीला जावे लागल्यामुळे त्या चर्चेच्या वेळी मी उपस्थित नव्हतो. आमची रोजगार हमी योजना बंद झाली. त्या ऐवजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणली. वि. स. पागे समितीने शिफारस केलेली योजना महाराष्ट्रातील आदर्श योजना होती. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केली. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र राज्य हे या योजनेचे प्रवर्तक राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा सर्वात जास्त निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. जेव्हापासून केंद्राची योजना सुरु झाली तेव्हापासून त्या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये किती पैसे खर्च झाले, किती कामे सुरु झाली ?

...2...

RDB/ MMP/ D

श्री. पांडुरंग फुंडकर

केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्याने आपल्याला मागे टाकले आहे. आपल्या राज्याने चालू केलेली जी योजना केंद्र शासनाने घेतली त्याच योजनेमध्ये आपण मागे पडलो आहोत. ही योजना राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोन्ही यंत्रणा जबाबदार असल्याने प्रत्येक अधिकारी आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत आहेत.

सभापती महोदय, या राज्यामध्ये केंद्रातून नवीन मुख्यमंत्री आले. नवीन मुख्यमंत्री आल्यानंतर माननीय राज्यपालांनी केलेले हे पहिलेच अभिभाषण आहे. या पुरोगामी महाराष्ट्राला आत्महत्येचा कलंक लागला आहे. 5 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या वर्षी 1 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. त्या शेतकऱ्यांसाठी या अभिभाषणामध्ये काही तरी वेगळे धोरण नवीन मुख्यमंत्री आणतील अशी अपेक्षा होती. परंतु दोन तीन परिच्छेद सोडले, कमी व्याजाने बँकेचे कर्ज देण्याचा एक मुद्दा सोडला तर या अभिभाषणात शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही. 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' अशी या अभिभाषणाची अवस्था झालेली आहे.

सभापती महोदय, 20010-2011 मध्ये राज्यात प्रचंड प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. शेतकऱ्यांचे अंदाज चुकले. शासनाचे अंदाज चुकले.

यानंतर श्री. खंदारे ...

श्री.पांडुरंग फुंडकर....

मराठवाडा, विदर्भ, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील फळ बागायतदार या अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेले, त्याचे कारण असे की, या भागांमध्ये सरासरीपेक्षा दुपटीने पाऊस पडला. या भागातील शेतकऱ्यांवर निसर्ग कोपला. तरी सुद्धा शेतकऱ्यांनी महागडी खते, बियाणे घेतली, प्रचंड मजुरी खर्च करून शेतात बियाणे पेरले, पीक आले, परंतु अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झालेले. पुरोगामी राज्यामध्ये प्रजेची, रयतेची काळजी राजाला असली पाहिजे. रयतेवर संकट आले असेल तर त्याची काळजी राजाने घेतली पाहिजे. या अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसंबंधी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 1 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यावेळी आम्ही म्हटले होते की, 1 हजार कोटीपेक्षा जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे झालेले आहे. त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले की, नुकसानीचे पंचनामे झाल्यावर नुकसान अधिक झाल्याचे दिसून आले तर अधिक रक्कम देऊ. परंतु तसे घडले नाही हे आजच्या एका प्रश्नाच्या माध्यमातून सिद्ध झालेले आहे.

माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केल्यावर केंद्र सरकारने 450 कोटी रुपयांची मदत देऊ असे सांगितले. त्यानंतर ते देशाच्या कृषी मंत्र्यांकडे मदतीसाठी गेले, त्यांनी 200 कोटी रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे 1600 कोटी रुपयांची मदत अतिवृष्टीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार असे जाहीर झाले. डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान झाल्याचे आम्ही शासनाला सांगितले होते. पण शासनाने 1 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात वाढ करण्याची आम्ही मागणी केली होती, त्यावेळी पंचनामा झाल्यानंतर अधिक मदत जाहीर केली जाईल, शेतकऱ्यांसाठी लागेल तेवढी मदत दिली जाईल, कोठेही कमी पडू दिले जाणार नाही असे सांगण्यात आले होते. त्या 1 हजार कोटीमध्ये हे 600 कोटी रुपये लपले आहेत काय, मग अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा जगणार ? त्यावेळी आम्ही घेतलेली शंका बरोबर होती. मुख्यमंत्री महोदयांनी खुल्या दिल्याने, मोठया मनाने शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने व माननीय श्री.पवार साहेब यांनी 600 कोटी रुपये दिले ते राज्याच्या मदतीच्या व्यतिरिक्त असावयास पाहिजे होते. म्हणजे

2...

श्री.पांडुरंग फुंडकर....

राज्यातील शेतकऱ्यांना 1600 कोटींची मदत मिळाली पाहिजे होती. परंतु सरकारी यंत्रणांकडून नुकसानीचे पंचनामेच झाले नाहीत, जिल्हाधिकारी सांगतात की, पंचनामे करण्याचे सरकारकडून आदेशच आले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव मदत मिळाली नाही. मागील 250 कोटी रुपये 31 मार्चच्या पूर्वी शेतकऱ्यांचे जे देणे असेल ते देऊन टाकू असेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याचा या 1 हजार कोटीशी काही संबंध नाही. हे 1 हजार कोटी रुपये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंबंधी दिले आहेत.

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या, पूरात वाहून गेल्या, गारपीट झाली. त्यामुळे नुकसान झाले आहे. त्यावेळी 250 कोटी रुपये 31 मार्चपूर्वी दिले जातील असे कबूल केले होते. पण ती सुध्दा मदत मिळाली नाही. शेतकऱ्यांचे खरीपाचे पीक गेले, त्याचा संसार चालला पाहिजे म्हणून त्याने कर्जाऊ रक्कम घेऊन दुबार पेरणी केली. त्याने गहू व हरभरा पेरला होता. आणखी काही पिके घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अचानकपणे पडलेल्या थंडीमुळे त्याचा गहू करपला, हरभरा करपला. हे संकट सुध्दा त्याच्यावर आले. त्याची तर शासनाने दखलच घेतली नाही. शेतकऱ्यांच्या गव्हाच्या पिकाला, हरभऱ्याच्या पिकाला पाणी द्यायचे असेल तर पंप चालू करण्यासाठी वीज नाही. ग्रामीण भागात 14-14 तास लोडशेडिंग असते. वीज आली तर ट्रान्सफॉर्मर जळतो. जळालेला ट्रान्सफॉर्मर 2-2 महिने बदलून मिळत नाही. मला आता नुकताच फोन आला आहे.

यानंतर श्री.शिगम.....

MSS/ KTG/ D/ KGS/ MMP/ पूर्वी श्री. खंदारे

18:00

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

सन्माननीय सदस्य श्री. पाशा पटेल यांनी आताच दिलेल्या माहिती प्रमाणे लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील सारोळा गावातील शेतक-यांनी वीज मंडळाच्या 3 अधिका-यांना वीज नाही म्हणून झाडाला बांधून ठेवलेले आहे. आता शेतकरी इतके संतप्त झालेले आहेत की कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. तेव्हा शासनाने वेळीच खबरदारी घ्यावी. सभापती महोदय, त्या गावामध्ये 8 दिवस वीज नाही म्हणून शेतक-यांनी या क्षणाला वीज मंडळाच्या 3 अधिका-यांना झाडाला बांधून ठेवलेले आहे. 8 दिवस वीज नसल्यामुळे शेतीला पाणी कसे द्यायचे हा मोठा प्रश्न शेतक-यांसमोर आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या कर्तृत्वावर आमचा विश्वास आहे. पण खालचे अधिकारी इतके बेदरकार झालेले आहेत की ते शेतक-यांशी बोलायला देखील तयार नाहीत. शेतकरी ट्रान्स्फॉर्मर मागायला गेले तर त्यांना वीज मंडळाचे अधिकारी दारात उभे करीत नाहीत. ट्रान्स्फॉर्मरसाठी पैशाची मागणी केली जाते आणि पैसे दिले तरीही ट्रान्स्फॉर्मर दिला जात नाही अशी स्थिती आहे. शेतक-यांना रब्बीचे पीक घेणे मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी कसा जगेल ? ज्या शेतक-याला जगाचा पोशिंदा म्हटले जाते त्या अन्नदात्या पोशिंदाची इतकी वाईट अवस्था झालेली असताना हे शासन कोणते दिग्दर्शन करीत आहे ? अन्नदाता शेतकरी जो आपला पोशिंदा आहे तो आज विजेविना, पाण्याविना तडफडत आहे. एकीकडे निसर्ग त्याला मारत आहे आणि दुसरीकडे सरकार. 1000 कोटीमध्ये मागचे 600 कोटी आणि 250 कोटी देणे अंतर्भूत असेल तर मग शिल्लक काय राहाणार ?

सभापती महोदय, राज्यातील शेतक-याचे 5 हजार कोटी रुपयाचे नुकसान झालेले आहे. शेतक-यासमोर आता आत्महत्ये शिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. 3750 कोटीचे पॅकेज केन्द्राने दिले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 1 हजार कोटी रुपये दिले. अशा प्रकारे एकूण 4750 कोटीचे पॅकेज आल्यानंतर देखील राज्यात शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सुरुवातीला असे वाटले होते की, फक्त विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करतात. परंतु आता मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र या भागातील शेतकरी देखील आत्महत्या करायला लागला आहे. आत्महत्यांचे हे सत्र कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. मग हे शासन कोणते दिग्दर्शन करणार आहे ? या राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या कमी होण्याच्या दृष्टीने या अभिभाषणामध्ये काही उल्लेख केला गेला असता तर या अभिभाषणाचे आम्ही खुल्या दिलाने समर्थन केले असते.

..2..

श्री. पांडुरंग फुंडकर....

सभापती महोदय, शेतक-याला 2 टक्के दराने कर्ज पुरवठा करीत आहात म्हणजे आपण शेतक-यांवर काही उपकार करीत नाही. आपण गेली 11 वर्षे या राज्याच्या सत्तेवर आहात. 2 टक्के दराने आधीच कर्ज दिले असते तर कदाचित शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्याही नसत्या. मागील अधिवेशनामध्ये माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितलेले होते की, राज्यातील सावकारग्रस्त असलेल्या शेतक-याला वाचविण्यासाठी सावकार विरोधी कायदा आणणार आहे. हा कायदा विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत करून एक वर्ष झाले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महामहिम राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळत नाही. मी या निमित्ताने माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की, ते वर्षानुवर्षे केन्द्रामध्ये मंत्री होते. हा सावकार विरोधी कायदा केन्द्र सरकारच्या गृहमंत्रालयामध्ये अडकून पडलेला आहे. तेथून त्यांनी या कायद्याला मंजूरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु करावी. सभापती महोदय, राज्यात कोण महासावकार आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्या सावकाराचे नाव सर्वांना माहित आहे. गरीब शेतक-यांची हजारो एकर जमीन या सावकाराने खरेदी केलेली आहे. पैशाच्या मोबदल्यामध्ये त्याने शेतक-यांच्या जमिनी खरेदी केलेल्या असतानाही त्याचे समर्थन या शासनाकडून होते ही अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे. शेतक-यांची शेती हडप केल्याची हजारो प्रकरणे मी जिल्हाधिका-यांकडे, डीडीआरकडे, अेआरकडे आणि पोलीस स्टेशनला दिली आहेत.

...नंतर श्री. गिते....

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

पोलीस स्टेशन कारवाई करण्यास तयार नाही, डी.डी.आर.कारवाई करण्यास तयार नाही, जिल्हाधिकारी कारवाई करण्यास तयार नाही.

माननीय श्री.हर्षवर्धन पाटील साहेब आपण सभागृहाच्या बाहेर जाऊ नका, तुम्हीच सभागृहात सावकारी कायद्याचा पुनरुच्चार केला होता. सावकारी कायद्याचे काय झाले त्याबाबतची माहिती आम्हाला सांगावी. सावकारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सावकारी कायदा आणू असे सभागृहात अविर्भावात सांगितले गेले. आम्ही आमच्या गावातील सावकाराच्या बाबतीत संघर्ष केला. पोलीस स्टेशनमध्ये जवळपास 80 तक्रारी दाखल केल्या. शासन म्हणते की, आम्ही माफियांचे पाठीराखे नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयातून पोलीस स्टेशनला फोन केला गेला व सांगितले गेले की, मी सांगेपर्यंत या सावकाराच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नका. परंतु त्या पोलीस स्टेशनमध्ये एक मर्द पोलीसवाला होता, त्याने स्टेशन डायरीत नोंद केली की, "माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयातून फोन आला आहे की, मा.मुख्यमंत्र्यांकडून सांगेपर्यंत श्री. सानंदा नावाच्या सावकारावर कारवाई करू नका." तेथील पोलीस अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितले की, माननीय भाऊसाहेब, तुम्ही आम्हाला कारवाई करावयास सांगता. परंतु आम्हाला माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून फोन आला. पोलीस अधिकाऱ्याने स्टेशन डायरीत जी नोंद करून घेतली होती त्याची झेरॉक्स प्रत मला उपलब्ध करून देण्यात आली. मी हा विषय सभागृहात मांडला. मी माननीय श्री.आर.आर.पाटील साहेबांना सांगितले की, तुमच्या खात्यावर अतिक्रमण चालले आहे. त्यांनी मला सांगितले की, मी माझ्या खात्यावर अतिक्रमण होऊ देणार नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, यासंदर्भात परिपत्रक काढले गेले की, कोणाही नेत्यांनी पोलीस स्टेशनला फोन केला तर त्यांची नोंद केली जाऊ नये. परिपत्रक पोलीस स्टेशनला गेले की, कोणी आमदार असेल, खासदार असेल तर त्यांच्या फोनची नोंद पोलीस स्टेशन डायरीत करू नका. ही बाब मी माननीय श्री.आर.आर.पाटील साहेबांच्या समोर मांडली, त्याबाबतीत त्यांनी मला सांगितले की, मी यासंदर्भात चौकशी करतो. मी कोणाचीही गय करणार नाही. जिल्हाधिकारी यांना मुंबईला बोलाविण्यात आले. जिल्हाधिकारी, डी.डी.आर.आणि एस.पी. यांची त्रिसदस्यीय समिती आहे त्या समितीला आदेश देण्यात आला की, मी सांगेपर्यंत या सावकारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई

2...

श्री. पांडुरंग फुंडकर...

करु नका. ते जिल्हाधिकारी देखील बहादर निघाले. जिल्हाधिकारी बुलढाणा येथे गेले आणि त्यांनी एस.पी.यांना एक पत्र लिहिले. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अशी अशी बैठक झाली आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, मी सांगेपर्यंत श्री.सानंदा या सावकारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु नका. तेथील एस.पी.यांनी त्या पत्राची झेरॉक्स प्रत मला उपलब्ध करुन दिली. त्यांनी मला विचारले की, क्या हम कुछ नहीं कर सकते ? त्या ठिकाणी श्री.कृष्णप्रकाश नावाचे एस.पी.आहेत.

सभापती महोदय, हे सर्वोच्च सभागृह आहे. या सर्वोच्च सभागृहात आम्हाला न्याय मिळत नसेल तर न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही. त्यानंतर आम्ही न्यायालयात गेलो. ज्याच्या नावाने केस टाकली तो माझा तालुका अध्यक्ष होता. त्याला सांगितले की, श्री.सानंदाच्या दहशतीमुळे तू देखील पक्ष सोडशील आणि माझी केस खराब करशील. मी असे करणार नाही असे त्याने मला सांगितले. या प्रकरणी हायकोर्टाने 25 हजार रुपयांचा दंड व ताशेरे ओढले अशा प्रकारचा निर्णय दिला. यासंदर्भात सरकार सुप्रीम कोर्टात का गेले याची मला कल्पना नाही. सुप्रीम कोर्टाने तो 25 हजार रुपयांचा दंड 10 लाख रुपये केला. सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या विरोधात जे ताशेरे ओढलेले आहे ते माननीय मुख्यमंत्र्यांनी वाचावे अशी माझी विनंती आहे. सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर भयानक ताशेरे ओढलेले आहेत. आमची अशी अपेक्षा होती की, हा दंड राज्य सरकारच्या तिजोरीतून भरला जाणार नाही. चूक एका माणसाने केली. राज्य सरकारच्या तिजोरीत जनतेकडून वसूल करण्यात आलेला कराचा पैसा जमा होतो. राज्याच्या तिजोरीतून शासनाने 10 लाख रुपयांचा दंड भरला. सावकार आणि माफियांची हे सरकार किती पाठराखण करणार आहे ? या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे....

यानंतर श्री. भोगले....

श्री.पांडुरंग फुंडकर.....

या सरकारने सावकारी माफियांची पाठराखण केली. आम्हाला बोलायची गरज उरलेली नाही. या राज्यात भूखंड माफिया, दूध माफिया, तेल माफिया, वाळू माफिया, टोल माफिया, रेशन माफिया निर्माण झालेले आहेत. अशा माफियांची यापुढे पाठराखण होता कामा नये. या राज्यावरचा कलंक पुसून टाकायचा असेल तर हे माफिया मातीमध्ये गाडले जातील असा निर्णय शासनाकडून घेतला जावा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यादृष्टीने निर्णय घ्यावा. आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. महाराष्ट्रातील 10 कोटी जनतेला ज्यांनी गिळंकृत केले आहे अशा माफियांना मातीत गाडण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून तुम्हाला नेहमीच सहकार्य मिळेल याची ग्वाही देतो. सभापती महोदय, मी सन्माननीय गृहमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी असे सांगितले की, काय करणार? दंडाची रक्कम न्यायालयात भरावी लागली. शेवटचा दिवस होता. अन्यथा कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होईल. कोर्टाच्या धाकाने शासनामार्फत रक्कम भरण्यात आली.

सभापती महोदय, अनेक विषय आहेत. कृषी पंपधारकांवर अन्याय होत आहे. विजेच्या प्रकल्पांचा प्रश्न आहे. माननीय उप मुख्यमंत्र्यांची विदर्भावर वक्रदृष्टी का झालेली आहे? जे नवीन वीज प्रकल्प विदर्भात येऊ घातले आहेत तो मुद्दा मांडू इच्छितो. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष 10 लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. राज्य शासनाने विदर्भात 20 हजार मे.वॅट निर्मितीचे खाजगी औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी पाणी कुठून आणणार? विदर्भात पुरेसे पाणी नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातून विदर्भात पाणी आणले जाणार नाही. विदर्भात पाण्याचे प्रमाण तुटपुंजे आहे. विदर्भात धरणे कमी आहेत. त्या धरणातील पाणी या प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार आहे. या नवीन प्रकल्पांमध्ये अनुक्रमे मे.ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड, चंद्रपूर (मारथेगाव), मे.फरनडे इन्फापॉवर लिमिटेड, चंद्रपूर(मूल), मे.सेंट्रल इंडिया पॉवर कंपनी लिमिटेड, चंद्रपूर (विरादेवी), मे.नागपूर एनर्जी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., चंद्रपूर (देऊळवाडा), मे.इंमको एनर्जी लिमिटेड, चंद्रपूर (नायदेव), मे.धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी.) लिमिटेड, चंद्रपूर (ताडाली), मे.सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कं.लि., भंडारा (वरठी), मे.मुरली इंडस्ट्रीज, नागपूर (वरोडा/कामठी), मे.लेणेक्सीस एनर्जी लिमिटेड, नागपूर (खुरसापूर), मे.इंडिया बुल्स पॉवर लिमिटेड, अमरावती (नांदगाव), मे.अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, गोंदिया (तिरोडा), मे.पृथ्वी

..2..

श्री.पांडुरंग फुंडकर.....

एनर्जी लिमिटेड, चंद्रपूर (कोरपना), मे.पृथ्वी खनिज संपदा प्रा.लिमिटेड, भंडारा (सुकली), मे.इंडोरामा सिन्थेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड, यवतमाळ (नांदेपेरा/वणी), मे.डी.बी.प्रॉजेक्ट प्रा.लि., भंडारा (कुसारी), मे.गुप्ता एनर्जी प्रा.लि., चंद्रपूर (उषेगाव), मे.अॅक्स्ट्रीक पॉवर प्रा.लिमिटेड, नागपूर (पांढरातळ), मे.डॉल्बी मायनिंग अॅड पॉवर लिमिटेड, नागपूर (उमरी), मे.आयडीयल एनर्जी प्रॉजेक्ट लिमिटेड, नागपूर (किनहाला) आणि मे.जिन भूविश पॉवर जनरेशन प्रा.लिमिटेड, यवतमाळ (बिजोरा) असे एकूण 20 वीज निर्मिती प्रकल्प नव्याने उभारले जाणार आहेत. विदर्भ आणि कोकण हे दोन भाग वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी निवडले जात आहेत. महाराष्ट्रात अन्यत्र कुठेही जागा नाही का, महाराष्ट्रात कुठेही पाणी नाही का? या 20 वीज प्रकल्पांमुळे आणि अस्तित्वात असलेल्या चंद्रपूर, खापरखेडा, कोराडी, पारस वीज निर्मिती प्रकल्पांमुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होणार आहे. आज विदर्भात पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. या नवीन वीज प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असलेले पाणी वापरले जाणार आहे. यामुळे विदर्भातील सिंचनाचा बॅकलॉग कमी होण्याऐवजी वाढणार आहे. सभापती महोदय, कोकणामध्ये हीच अवस्था आहे. कोकण आणि विदर्भात 9 वीज प्रकल्प सध्या कार्यरत आहेत. याचा कुठेतरी विचार करण्याची गरज आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याची गरज आहे. विदर्भात सिंचनाचा बॅकलॉग कमी होण्याऐवजी वाढणार आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या मी एक बाब लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, माननीय पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केले. या राज्यातील सामुहिक विवाहासाठी सरकारने अनुदान जाहीर केले होते. प्रत्येक वर्षी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये हा एक मुद्दा प्रकर्षाने नमूद केला जात होता. सामुहिक विवाह योजनेनुसार प्रत्येक जोडप्याला 10 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. ती कन्यादान योजना आता बंद करण्यात आली. या वर्षीच्या अभिभाषणामध्ये या योजनेचा उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सामुहिक विवाहामध्ये सामील होणाऱ्या जोडप्यांना यापुढे हे 10 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार की नाही?

नंतर 3यू.1...

श्री. पांडुरंग फुंडकर

त्यामुळे आता राज्यात सामूहिक विवाहांची संख्याही कमी झाली आहे. गोर-गरिबांची लग्न होत नाहीत. पंतप्रधान पॅकेजमध्ये जो प्रकल्प केंद्र शासनाने जाहीर केला होता तो आता बंद झालेला आहे. कारण त्यासाठी मागील वर्षाचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. अशा प्रकारे आपण राज्याला कोणती दिशा देत आहात हे या अभिभाषणातूनच स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे कुठल्याही प्रकारे समाधान झाले नाही तसेच राज्याला कोणती दिशा देणार हे न सांगता दिवाळखोर राज्याला प्रगत राज्य म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणार असे हे अभिभाषण आहे पण सन्माननीय सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी आपल्या भाषणातून या मुद्याचे कौतूक केले नाही. आज राज्यातील गरीब माणूस महागाईत जळतो आहे, त्याच्यासाठी काय बंदोबस्त हे सरकार करणार आहे याचा उल्लेख अभिभाषणात न केल्याबद्दल माननीय राज्यपालांचे अभिनंदन करतो आणि माझे बोलणे संपवितो.

....2....

श्री. जयंत प्र. पाटील (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांचे मी प्रथम अभिनंदन करतो की, या सभागृहात अभिभाषण करताना सीमा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीतील मुद्याने भाषणाचा शेवट होत असतो. मागील वेळेस माननीय उप मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला शब्द दिला होता की, पुढील वर्षी यामध्ये सुधारणा होईल म्हणून हा प्रश्न अभिभाषणात घेणे सोडून दिले की काय अशी शंका यायला लागली. हा प्रश्न या अभिभाषणात घेणे सोडून दिले की काढूनच टाकला हे मात्र मला समजत नाही.....अडथळा.....क्र. 69 वर हा मुद्दा आहे याची मला जाणीव आहे. पण दर वेळेस हा मुद्दा शेवटी असतो आता मात्र मध्येच घेतलेला आहे.

महोदय, सांगली जिल्ह्यातील 400 कानडी शाळांना शासनाने अनुदान देण्याचे मान्य केले परंतु बेळगांवचा मराठी माणसाला डी.एड. ला सुध्दा अॅडमिशन मिळत नाही, अशी त्याची गळचेपी होत आहे. बेळगावात कानडी साहित्य संमेलन भरविले जाते आणि त्यात बेळगांवचे नाव बदलण्याचा ठराव होतो हे या राज्याला शोभादायक नाही, त्याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो.

महोदय, दुसरा मुद्दा असा की, मंत्रिमंडळाची संख्या आपण मर्यादित केली त्याबद्दल धन्यवाद देतो पण माझ्याकडे मंत्र्यांची यादी आहे. त्यातील काही मंत्र्यांकडे जास्तीत जास्त विषय आहेत आणि काही मंत्र्यांकडे फक्त एक एकच विभाग आहे. मग ही खाती वाटप चेहरा बघून केले जाते की कसे हे समजत नाही. तसेच प्रशासनामध्ये सुधारणा करायला हे शासन निघाले याचा मला अभिमान वाटतो तसेच या निमित्ताने बाबा आणि दादाची जोडी काही तरी वेगळे करेल अशीही अपेक्षा करतो. पण मंत्र्यांनी स्वतःच्याच मतदारसंघात किती वेळा जावे याला काही तरी बंधन असले पाहिजे. मी त्यांच्या दौऱ्याच्या कार्यक्रमाची डायरी बघितली.

यानंतर श्री. जुन्नरे

श्री. जयंत प्र.पाटील...

सभापती महोदय, मंत्र्यांनी स्वतःच्या मतदार संघात किती वेळेस जावयाचे हे ठरवण्याची आता वेळ आलेली आहे. मंत्री आता केवळ स्वतःच्या मतदार संघातच जास्त करून जात असतात. माननीय उप मुख्यमंत्री आपण स्वतः बारामती येथे शिक्षण घेतले आहे, आम्ही सुध्दा खेड्यात शिक्षण घेतलेले आहे. त्यावेळेस गावामध्ये कधी तरी मंत्री येत असल्यामुळे गावामध्ये दिवाळी दस-या सारखा जोश असायचा. परंतु आज मंत्री आले तर त्यांच्याकडे मामलेदार बघत नाहीत, ते कोणत्याही कार्यक्रमाला थांबत नाहीत. मामलेदार सोडा परंतु सरपंच सुध्दा मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला थांबत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे मंत्र्यांच्या दो-यासाठी काही तरी प्रोटोकॉल असण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते.

सभापती महोदय, मंत्र्यांनी जिल्हयातील अधिका-यांना मुंबईला किती वेळा बालवावे याला सुध्दा काही तरी धरबंध असणे आवश्यक आहे. आम्ही जेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिका-यांकडे, प्रांत अधिका-यांकडे जातो व साहेब कोठे गेले आहेत असे विचारले तर आम्हाला सांगितले जाते की, "साहेब मुंबईला मिटिंगसाठी गेलेले आहेत". या अधिका-यांना कधी गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री बोलवतात. आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग केलेले असल्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगने विचारणा केली तर आपला पैसा व वेळ सुध्दा वाचू शकेल. मला माहिती आहे की, सर्वच मंत्री काही अधिका-यांना मुंबईला बोलवत नाही परंतु अधिकारी विनाकारण आपल्या डायरीमध्ये लिहित असतात त्यामुळे याला कोठे तरी बंधने आणली गेली पाहिजेत असे मला वाटते. मुंबईच्या आजूबाजूचे जे जिल्हे आहेत त्यांच्याकडे खास करून याबाबतीत कटाक्षाने बघण्याची गरज आहे असे मला वाटते.

सभापती महोदय, कोणत्या मंत्र्यांनी किती वेळेस हेलिकॉप्टरने प्रवास करावा याबाबत आम्हाला काही म्हणावयाचे नाही. परंतु हेलिकॉप्टर शासनाचे आहे की, खाजगी आहे याला सुध्दा काही तरी बंधने आणण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे हेलिकॉप्टरने प्रवास केल्यामुळे राज्याची बदनामी होते व राज्याची बदनामी झाली म्हणजे आमचीही बदनामी होते त्यामुळे हे प्रकार थांबले पाहिजेत, यासाठी काही प्रोटोकॉल असणे आवश्यक आहेत. याला काही तरी मर्यादा ठरवल्या गेल्या पाहिजेत असे मला वाटते.

..2..

श्री. जयंत प्र.पाटील...

सभापती महोदय, जात पडताळणी समिती कार्यालयाचे आपण संगणकीकरण करणार आहात ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समिती कार्यालयामध्ये कॅमेरे सुध्दा लावण्यात यावे अशी माझी विनंती आहे. ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी सदस्य म्हणून उभे राहावयाचे असेल तर त्यासाठी जात पडताळणीचा दाखला लागतो व जात पडताळणी समितीचे अधिकारी त्या त्या ग्रामपंचायतीच्या बजेट प्रमाणे 1-1 लाख रुपये सुध्दा मागत असतात. जात पडताळणी समितीकडून ओबीसीचा दाखला घ्यावयाचा असेल तर 1-1 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. एस.सी., एस.टी.चे प्रमाणपत्र तर सोडूनच द्या. परंतु साधे ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 1-1 लाख रुपये मागितले जाते. माझ्या जिल्ह्यातील ओबीसीचे 500 पेक्षा जास्त जात पडताळणीचे दाखले कोकण भवन येथील जात पडताळणी समितीकडे पेंडींग आहेत. पैसे दिल्याशिवाय आता जातपडताळणीचे दाखले मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आज 5-25 हजार रुपये दिल्याशिवाय जात पडताळणीचे कोणतेही दाखले मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामामध्ये सुधारणा होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

सभापती महोदय, मुंबई आमच्या जवळ आहे. ग्रामीण भागात एमएमआरडीएचे क्षेत्र का देण्यात आलेले आहे हे आम्हाला समजत नाही मुंबईपर्यंत या भागाचा विस्तार होईल अशी राज्य शासनाची बहुतेक अपेक्षा असावी. आज आमच्या भाषणावर एमएमआरडीए मुळे बर्डन पडत आहे. एमएमआरडीएचा फंड ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना किंवा नगरपालिकांना मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. उल्हासनगर, पेण, खोपोली, अलीबाग, वसई-विरार या ठिकाणी एमएमआरडीएच्या पैशांचे बरोबर वाटप होत नाही. ग्रामीण भागात एमएमआरडीएचे रस्ते, सुविधा या संदर्भातील वाटप कशा प्रकारे व्हावयास पाहिजे यासंदर्भात माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात कोठेही उल्लेख नाही.

यानंतर श्री. गायकवाड.....

17-03-2011

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3W1

VTG/ KGS/ KTG/

प्रथम श्री.जुन्नरे

18.25

श्री.जयंत प्र.पाटील ..

सभापती महोदय,शेवटचा एक मुद्दा मांडून मी माझे भाषण संपविणार आहे. विदर्भात खारपाटण जमीन आहे. मी विदर्भामध्ये ब-याचवेळा जात असतो. सिंचनाचे पाणी जर अधिक प्रमाणात आले तर जमिनी खारवट होते आणि त्या ठिकाणी पिके घेता येत नाही.अशा प्रकारच्या जमिनी अमरावती जिल्हयात काही ठिकाणी आहेत त्याचबरोबर अकोला जिल्हयात आकोट आणि बुलढाणा जिल्हयात जळंब तालुक्यात आहेत. तेव्हा विदर्भामध्ये सिंचन प्रकल्प घेत असतांना किंवा या पूर्वी जे काही प्रकल्प हाती घेतलेले असतील तर त्या प्रकल्पातील पाणी या भागात अधिक प्रमाणात येऊन जमिनी खराब होणार नाहीत, याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एखाद्या समितीची नियुक्ती करावी जेणे करुन त्या भागातील शेतक-यांना ख-या अर्थाने दिलासा मिळेल. या बाबतीत माझी एक वेगळी मागणी असून त्या संदर्भात मी माननीय उप मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र दिलेले आहे. पूर्वी खार लॅन्ड बोर्ड होते त्या बोर्डामार्फत समुद्राजवळील खार लॅन्डचे संरक्षण केले जात होते आणि त्याची दुरुस्ती करण्याचे कामसुध्दा केले जात होते परंतु नंतर हे बोर्ड रद्द करुन खार लॅन्ड विभाग सुरु करण्यात आला होता. तेव्हा विदर्भातील खारपाटण जमिनीचा अभ्यास करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात यावी व ही कामे करण्यासाठी एखादे मंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशा प्रकारची मी मागणी करतो आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल माननीय सभापतींचे आभार मानून मी माझे भाषण संपवितो.

उप सभापती : सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. उद्या शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011 रोजी सकाळी 10.00 ते दुपारी 12.30 या वेळेत सभागृहाची विशेष बैठक होईल. या बैठकीत महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 102 अन्वये अशासकीय ठराव घेण्यात येतील व सभागृहाची नियमित बैठक दुपारी 12.45 वाजता पुन्हा भरेल.

(सभागृहाची बैठक सायंकाळी 6 वाजून 26 मिनिटांनी, शुक्रवार , दिनांक 18.3.2011च्या सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत स्थगित झाली)